RNI Reference No. 1328500

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

16-30 नवम्बर, 2018

हिमाचल,
वर्ष 1/ अंक 9/ पृष्ठ: 16
मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

मिशन रीव का यही ध्येय, हर घर पहुंचे स्वास्थ्य सेवा : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

छह माह में पांच हजार लोगों की घर पर स्वास्थ्य जांच

स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिशन रीव ने हासिल किया नया आयाम

टीम रीव, शिमला

दूर गांव से बसों में धक्के खाते हुए दूर अस्पताल तक पहुंचना, लंबी कतारों में घंटो खड़े रहना, फिर एक टेस्ट आज हो गया तो दूसरे के लिए अगले दिन जाना। अपने जीवन के 80 बसंत दे चुके चंबा के दूरदराज के गांव शीलाघराट के थोलू राम की ये बातें इस हकीकत को जानने के लिए काफी है कि हिमाचल के गांवों में आज भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल में थोलू के जैसे ही सैंकड़ों लोग है जो इसलिए अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते और चाहकर भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते। लेकिन पिछले छह माह में ये तस्वीर काफी हद तक बदली है मिशन रीव ने। बहरहाल, मिशन रीव प्रतिनिधि जब थोलू राम के घर पर पहुंचे तो प्रतिक्रिया कुछ युं थी, आप कौन है, मैं अस्पताल नहीं जा सकता, मैं घर में ही ठीक हूं। लेकिन जब मिशन रीव स्वास्थ्य सेवक नरेश ने बताया कि हम आपके टेस्ट आपके घर पर ही करेंगे, दवाई चाहिए तो वो भी लाकर घर पर देंगे तो 80 साल की बुढ़ी आंखों में हल्की चमक आ गई, झुर्रियों के बीच होटों पर हल्की मुस्कुराहट के बीच जवाब आया, तब तो ठीक है बेटा।

हिमाचल के गांवों में बसने वाले हजारों लोगों के चेहरों पर ऐसी ही मुस्कुराहट लाने में मिशन रीव कामयाब रहा है। मई 2018 से गांवों में स्वास्थ्य सेवकों को स्वास्थ्य स्लेट दी गई और लोगों के घरों में ही उनके प्रारंभिक टेस्ट कराने की जिम्मेदारी सौपी गई। मिशन रीव इस काम को करने में पूरी तरह सफल रहा और महज छह माह में ही प्रदेश के विभिन्न गांवों में तीन हजार से अधिक लोगों के करीब पांच हजार बेसिक टेस्ट किए गए। ये वो टेस्ट हैं जिन्हें करवाने से कोई भी अपने स्वास्थ्य के बारे में प्रारंभिक जानकरी प्राप्त कर सकता है। आंकड़ों पर गौर करें तो मई से अक्तूबर तक 12 जिलों के 3 हजार लोगों के 5 हजार टेस्ट करवाए गए। खास बात ये कि ये सभी टेस्ट लोगों के घर पर जाकर मिशन रीव स्वास्थ्य सेवकों द्वारा किए गए।

गांवो में शुगर के मरीज बन रहे लोग

द रीव टाइम्स
The RIEV Times
मिशन रीव बनेगा ग्रामीण विकास का सूत्रधार: डॉ॰ एल.सी. शर्मा
गांव में 60% लोग हाई बीपी के शिकार
हिमाचल के अधिकतर लोग रक्तचाप और शुगर से ग्रस्त

टीम रीव, शिमला

हिमाचल के गांव के लोग धीरे धीरे मीठे जहर की चपेट में आ रहे हैं। मिशन रीव के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य स्लेट के माध्यम से पिछले छह माह में जो टेस्ट किए गए हैं, उनसे प्रदेश के ग्रामीणों के स्वास्थ्य को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मई से अक्तूबर के मध्य स्वास्थ्य स्लेट से जो टेस्ट किए गए उनमें 515 लोगों ने शुगर टेस्ट करवाए। इनमें 201 लोगों में शुगर लेवल नार्मल से अधिक पाया गया। यानी 39 फीसदी लोग हाई शुगर का शिकार पाए गए हैं। अगर इस आंकड़े पर गौर करें तो साफ है कि हिमाचल के गांवों की सेहत में सब कुछ सही नहीं है और इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। जरूरी है कि लोग बीमार होने से पहले एतिहातन अपने स्वास्थ्य की प्रारंभिक जांच करवाए और समय रहते स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि उन लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाई जाए जो किन्हीं कारणों से अस्पताल नहीं पहुंच पाते।

मिशन रीव स्वास्थ्य स्लेट के माध्यम से गांवों में टेस्ट की सुविधा देकर इसी कार्य को पूरा करने में लगा है। मई 2018 से अभी तक विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य स्लेट से जो टेस्ट किए गए उससे हिमाचल के गांवों के स्वास्थ्य की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। द रीव टाइम्स के प्रथम अंक में भी ग्रामीणों के स्वास्थ्य की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जो मिशन रीव के अपने स्वास्थ्य आकलन पर आधारित थी। अब छह माह बाद मिशन रीव की ही यह दूसरी आकलन रिपोर्ट है । यह रिपोर्ट पूरी तरह से स्वास्थ्य स्लेट से किए गए आंकड़ो पर आधारित है। शुगर के साथ ही हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी गांव के लोग हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर की आकलन रिपोर्ट द रीव टाइम्स के प्रथम अंक में प्रकाशित की गई थी। अब शुगर के मरीजों को लेकर प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और अभी तक के आकलन में गांव के 39 प्रतिशत लोग शुगर की चपेट में है।

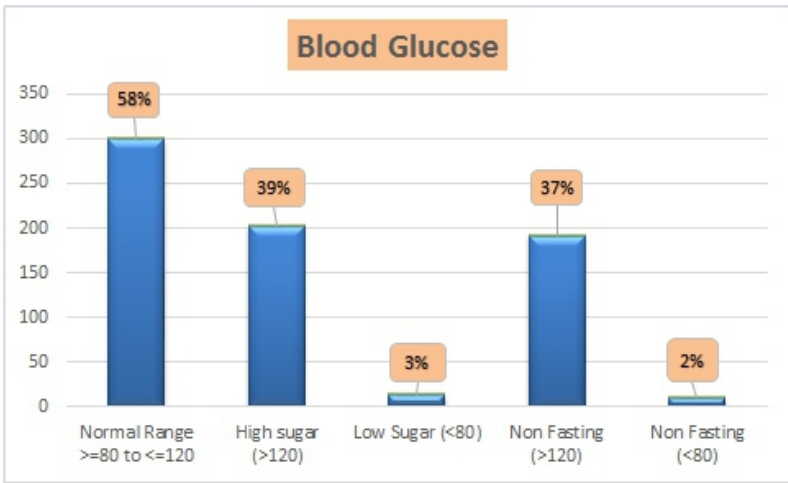

Maximum Test		513	%
Normal Range	>=80 to <=120	299	58%
High sugar	(>120)	201	39%
Low Sugar	(<80)	13	3%
Non Fasting	(>120)	191	37%
Non Fasting	(<80)	10	2%

कहां कितने टेस्ट

District	SpO2	BP	Temperature	Hb	Blood Glucose	Typhoid	Others	Total
Bilaspur	4	13	6	3	8	1	0	35
Chamba	108	239	25	204	273	0	1	850
Hamirpur	618	418	44	232	463	7	20	1802
Kangra	24	23	9	27	52	0	0	135
Kinnaur	14	26	12	20	23	0	0	95
Kullu	41	84	5	88	80	0	0	298
Lahaul spitti	1	1	1	0	0	0	0	3
Mandi	13	7	9	6	4	0	0	39
Shimla	38	30	18	20	34	0	3	143
Sirmaur	0	0	0	0	0	0	0	0
Solan	12	14	11	2	9	0	0	48
Una	427	204	184	274	436	15	13	1553
Total	1300	1059	324	876	1382	23	37	5001

स्वास्थ्य स्लेट के लाभ

स्वास्थ्य स्लेट से वे लगभग 13 टेस्ट किए जाते हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति को होने वाले अधिकतर शारिरीक कमियों से होने वाली बीमारी या रोगों के बारे में स्क्रिनिंग के माध्यम से जानकारी मिल सकती है। स्वास्थ्य स्लेट से एचबी, बीपी, शुगर, पल्सऑक्सिमीटीर टेस्ट, बॉडी टेंपरेचर, मलेरिया, सिफलिस, हैपेटाइटिस बी, टाईफाईड एवं प्रेगनेंसी टैस्ट आदि टेस्ट किए जाने की सुविधा है।

हिमोग्लोबिन टेस्ट

इस टेस्ट से खून मे हिमोग्लोबिन नामक तत्व की प्रतिशतता की जांच की जाती है। खून मे हिमोग्लोबिन की कमी को अनीमिया कहा जाता है। इससे शारीरिक थकावट, सांस लेने मे दिक्कत, भूख न लगना जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

शुगर टेस्ट

मधुमेह (सामान्य शुगर 80–120) शुगर टेस्ट से मधुमेह नामक रोग की जांच होती है इस टेस्ट से रक्त मे ग्लूकोज़ तत्व के कम या अधिक मात्रा मे होने की जांच की जाती है। शुगर अधिक हाने पर व्यक्ति मधुमेह का शिकार हो जाता है। वजन घटना, बार–बार पेशाब आना, अधिक भूख लगना, प्यास लगना, जख्म भरने में देरी होना, हड्डियों का कमजोर होना, किडनी फेल होने की समस्या बढ़ जाना समेत अन्य कई तरह की स्वास्थ्य संबंधि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय समय पर शुगर का टेस्ट करना जरूरी है और इसमें स्वास्थ्य स्लेट बेहद कारगर साबित हो रही है।

रक्तचाप (बीपी)

रक्तचाप अधिक होने से हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और दूसरी गंभीर समस्याएं हो सकती है।

पल्स आक्सीमीटर

इस टेस्ट से खून में आक्सीजन की सही मात्रा का पता लगाया जा सकता है। आक्सीजन की मात्रा सही न होने से सांस संबंधि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में समय समय पर टेस्ट करवाना जरूरी है।

टाइफाइड टेस्ट

यह रोग दूषित खाद्य पदार्थों और गन्दे पानी के सेवन से होता है । कई बार व्यक्ति को बुखार भी आता है। समय पर टेस्ट न होने पर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है।

क्या कहते हैं लोग

"आज तक तो कोई नहीं आया था घर पर जांच करने। सिर में दर्द रहता था और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इसलिए काफी समय पहले अस्पताल में जांच करवाई तो डाक्टर ने बताया कि ब्लड प्रेशर हाई रहता है आपका और जांच करवाते रहना। अब मिशन रीव के लोग आकर घर पर ब्लड प्रेशर चैक कर देते हैं तो आराम हो गया। घर में जांच हो जाए तो आधा आराम अपने आप ही हो जाता है।"

डोलमा, कुल्लू ,ग्राम पंचायत नसोगी, गांव सियाल

"मेरी उम्र 80 साल हो गई। ऐसे कभी टेस्ट नहीं करवाए। कई बार सोचा कि अस्पताल जाकर टेस्ट करवा लूं। लेकिन अस्पताल दूर है, जाने के लिए बड़ी परेशानी है। बसों में धक्के खाने पड़ते हैं, लाईनों में खड़ा होना पड़ता है। पूरा दिन लग जाता है। लेकिन अब तो मिशन रीव के लोग स्वास्थ्यस्लेट से ही घर पर टेस्ट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है।"

चिमनू राम, चंबा

"मिशन रीव गांव तक स्वास्थ्य सुविधा पहुचाकर बेहतर कार्य कर रहा है। आज भी गांव से अस्पताल पहुंचना आसान नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि गांव के लोगों को गांव में ही प्रारम्भिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जाए। इस कार्य को करने में मिशन रीव सफल रहा है।"

श्याम लाल, कुल्लू

"मिशन रीव का काम सही मायनों मे प्रंशसनीय है। काजा जैसे क्षेत्र में लोगों के घरों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना आसान काम नहीं है। हमें खुशी है कि गांव के लोगों को अब गांव में ही टेस्ट कराने की सुविधा मिल जाती है। मैं खुद भी काफी राहत महसूस कर रही हूं।"

ताशी डोलमा, ग्राम पंचायत हल, काजा, किन्नौर

विनय हेटा ने किस-किस के साथ मिलकर किया था घपला

जालसाजी पर जुड़ें सभी पहलुओं की हो रही है जांच

जालसाज विनय हेटा के साथ कुछ और कर्मचारी भी संदेह के घेरे में

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

आईआईआरडी में मिशन रीव के तहत जुड़े रहे जालसाज विनय हेटा ने कंपनी को चूना लगाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से धोखाधड़ी कर भारी नुकसान पहुंचाने की फिराक में था। उसने इस जालसाजी को करने के लिए कुछ अन्य लोगों और कर्मचारियों का सहारा लिया....जांच में ऐसी संभावनाऐं सामने आ रही है। विनय हेटा मूलतः ठियोग से संबन्ध रखता है और शिमला के विकासनगर में भी रहता है।

गौरतलब है कि विनय हेटा कंपनी में मिशन रीव के तहत कर्मचारी रहते हुए अपनी पत्नी के बैंक खाते में पैसे डलवाता रहा जबकि उसकी पत्नी सरकारी महकमें सेवाऐं दे रही है। उसकी पत्नी न तो कंपनी की कर्मचारी थी और न ही वो मिशन रीव से संबद्ध रही है। यह घपलेबाजी तब सामने आई जब कंपनी अपना आंतरिक ऑडिट करवा रही थी। उसके तुरंत बाद जालसाज विनय हेटा को नोटिस जारी किया गया जिसका संतोषजनक उत्तर वो नहीं दे पाया। उसके बाद अपनी जालसाजी को छुपाने के लिए उसने राजनैतिक एवं बाहरी दबाव बनाने की कोशिश करने लगा। कंपनी ने उसे धोखाधड़ी, जलसाजी और कंपनी को सोशल मिडिया आदि के माध्यम से बदनाम करने के लिए 50 लाख रुपये का मानहानि का नोटिस दिया है। कंपनी सारे पहलुओं की जांच कर रही है तथा जालसाज विनय हेटा के साथ जुड़ने वाले सभी लिंक खंगालने के बाद कंपनी कानूनी कार्यवाही करेगी।

मिशन रीवः दूसरा संस्करण पहले पायदान से शिखर की ओर...

कि दुनिया देखती रह जाए

- जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है तथा हर व्यक्ति का संघर्ष स्वयं में जटिल तथा चुनौतिपूर्ण है। जीवन में कुछ ही व्यक्ति अपने संघर्ष तथा चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते है लेकिन अधिकांश इतने टूट जाते हैं कि दोबारा उठना मुश्किल हो जाता है।
- इसके अतिरिक्त जीवनयापन की इस यात्रा में कुछ सरकारी तथा ग़ैर सरकारी कार्य ऐसे होते हैं जिनके बग़ैर आगे बढ़ना मुश्किल होता है तथा इन कार्यों को सिरे चढ़ाना बहुत जटिल है। मिशन रीव का जन्म एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में हुआ है जहां से विभिन्न परिवारों की दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है।
- इस मिशन की खूबी यह है कि एक ओर जहां लोगों के दुःख–दर्द उनके घर–द्वार पर दूर हो रहें हैं, वहीं दूसरी ओर गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए अपने जीवन–यापन के अवसर पैदा हुऐ हैं । हर पंचायत क्षेत्र में कम से कम तीन व्यक्तियों के प्रशिक्षित दल के साथ यह मिशन प्रदेश में युवाओं को रोज़गार देने की प्रक्रिया में है।
- यह मिशन हर व्यक्ति का मिशन बने, इसके लिए एक सदस्यता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत बनने वाले सदस्यों की व्यक्तिगत समस्याओं तथा आवश्यकताओं का भी आकलन किया जा रहा है ताकि उन सबके लिए उपयुक्त समाधान तथा सहायता प्रक्रिया तैयार की जा सके ।
- मिशन रीव के एक वर्ष पूरा होने पर हमने आपसे साझा किया कि किस प्रकार विकास एवं आमजन के हित एवं समस्याओं को समझने का विचार हवा में तैर रहा था जिसे मिशन रीव ने धरातल पर लाकर उसे आत्मसात करने का सफल प्रयास इस एक वर्ष में किया । यानि यह सफर फर्श से अर्श का नहीं अपितु अर्श से फर्श तक का रहा। इस बीच बहुत से अनुभवों की कढ़ाई में कढ़ने और लोगों की बात को सुनने और महसूस करने के बाद कुछ आमूलचूक परिवर्तनों के साथ मिशन रीव का दूसरा संस्करण भिन्नता एवं आत्मीयता लेकर आपके सामने लाने की योजना है

सदस्यता अभियान

- मिशन रीव के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए वार्षिक सदस्यता ग्रहण करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन मिशन रीव के दूसरे संस्करण में इसके प्रारुप में परिवर्तन कर तीन भागों में विभाजन किया गया है ।
- मिशन रीव के प्रथम संस्करण में भरसक प्रयास रहा कि अपने प्रिय सदस्यों तक पहुंचकर आपकी समस्याओं का आकलन किया जाए तथा उसका समाधान भी। लेकिन प्रारंभिक चुनौतियों के बाद जो ख़ामियां रह गई उन्हें पूरा करते हुए मिशन रीव द्वितीय संस्करण में आपके लिए एक नई शुरुआत के साथ सामने आ रहा हैं ।

दिल से सेवा-दिल से भुगतान

मिशन रीव के एक वर्ष पूरे होने पर शुरु हुआ रीव संस्करण-2
मानसिक संपन्नता से ही आर्थिक संपन्नता का उद्भव संभव
सबके चेहरे पर मुस्कान ही मिशन रीव का अंतिम लक्ष्य

हालांकि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सेवा और समर्पण मिशन रीव के मूल में है किंतु व्यवहारिकता के साथ प्राप्त होने वाले अनुभव और सीख निरंतर आगे बढ़ने में सहायक होती है। इसी अनुभव को आधार बनाकर मिशन रीव ने लोगों के दिल तक पंहुचने और दिल से सेवा का प्रदेश के लोगों के मध्य लेकर जाने का प्रण लिया, जिसका आगाज़ आप सभी के आशीर्वाद के साथ किया जा रहा है ।

क्या है दिल से सेवा दिल से भुगतान

- मनुष्य बनना और मनुष्य होना यह बड़े सौभाग्य की बात है। इसके होने के पीछे इसका मूल सेवा के अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता। सेवा से अर्जित संपन्नता का विकल्प हो ही नहीं सकता। मिशन रीव भी इसी दर्शन को सर्वोपरी रखते हुए अपने मिशन को लोगों तक लेकर जाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी दैनिक परेशानियों और समस्याओं से जूझ रहा इंसान अपनी वास्तविक उद्देश्य से भटक रहा है और स्वयं तथा अपने सकारात्मक उत्पादक समय को अनचाहे ही नष्ट करता जा रहा है। यह आधुनिक दौड़ समय और सूकून के अलावा बाकि सभी कुछ प्रदान कर सकती है। इतना ही नहीं जानकारी के अभाव और बदलते परिवेश में कार्यों का निष्पादन भी एक समस्या से कम नहीं है। ऐसे में निरर्थक भागदौड़ और चिंताओं में हम अपने स्वास्थ्य को भी दांव पर लगा रहे हैं और बहुमुल्य समय की बर्बादी तो हो ही रही है। चेहरे पर मुस्कान, ईद के चांद जैसी है जो कभी–कभार ही दिखाई देती है। इन्हीं सपनों को धरातल पर उतारने और सबके चेहने की मुस्कान बनने के संकल्प के साथ 'दिल से सेवा–दिल से भुगतान' के मूलमंत्र के साथ मिशन रीव दूसरी पारी के साथ आपके बीच है।
- आपकी समस्याओं को समझना और निदान हेतु संपूर्ण जिम्मेवारी के साथ आगे आने के लिए मिशन रीव अब आपके साथ है। मिशन का प्रयास आपके चेहरे पर मुस्कान लाना और देखना है। इसी मुस्कान के लिए सहर्ष सेवाऐं दी जाऐंगी। इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि हर चीज अथवा सेवा की भी एक कीमत होती है। हमारे श्वास भी इस प्रकृति के ऋणी है और ये ऋण हम प्रकृति को बचाकर, पेड़ पौधे लगाकर, उन्हें जल से सींचित कर, उनका संरक्षण कर चुकाने का प्रयास करते हैं। यही भाव और तात्पर्य दिल से सेवा–दिल से भुगतान पर भी लागु होता है। किंतु इसमें सेवा और सबके चेहरे पर मुस्कान का मूल इसे सर्वथा भिन्न श्रेणी में रखता है। हमें चिंता है आपकी..... इसलिए अपनी सारी चिंताओं को मिशन रीव को दें..... और एक सुंदर सी मुस्कान हमारे ध्येय को सफल कर देगी।

समस्त सेवाओं को आप तक पंहुचाने और सभी समस्याओं के समाधान में जो भी न्यूनतम कीमत अदा की जानी है उसे आपके पर्स से नहीं.....आपके दिल से भुगतान के लिए रखा गया है । यानि एक कार्य की कीमत यदि न्यूनतम 100 रुपये हैं तो भी हम इसे आप के दिल पर छोड़ते हैं कि आप इसका भुगतान निर्धारित मुल्य के बाद दिल से ही करें ..... क्योंकि आपको जोड़ने और आपकी समस्या को सुलझाने के लिए यदि आप सेवाओं से संतुष्ट हैं और इन सेवाओं के कारण आपके चेहरे पर एक मुस्कान लाने में हम सफल हुऐं हैं..... तो उसके लिए भुगतान भी उसी मुस्कान के साथ होना चाहिए।

दिल से सेवा-दिल से भुगतान : इन चरणों में आपके मध्य

- मिशन रीव के पुराने सदस्य और जिन्होंने 31 मार्च 2018 तक सदस्या ली है, उन्हें पुनः इसमें नवीनिकृत किया गया है तथा इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार की फीस अदा नहीं करनी पड़ी ।
- सदस्यता के प्रारुप/तौर तरीके : तीन प्रकार की सदस्यता

क. वार्षिक प्रदत/Paid सदस्यता :

इस प्रारुप में पहले जैसे ही ढांचे पर एक वर्ष के लिए रुपये 2000/ के भुगतान पर सदस्या प्रदान की जाएगी ।

ख. आजीवन सदस्यता :

मिशन रीव के दूसरे संस्करण में आजीवन सदस्यता का नया विकल्प रखा गया है । इसके लिए एक बार के 10,000/के भुगतान पर इसका आजीवन सदस्य बन सकता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक पंचायत से जो भी आजीवन सदस्य होंगे उन्हें ही रीव सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनने को अवसर प्राप्त होगा।

ग. स्वैच्छिक सदस्यता :

इस प्रारुप में सदस्य बनने के लिए कोई भी भुगतान नहीं किया जाऐगा। इसमें कोई भी सदस्य बन सकता है तथा सदस्य बनने के बाद उनका आवश्यकता आकलन होगा ।

पूरा प्रदेशः दिल से सेवा-दिल से भुगतान

प्राथमिक चरण में दूसरा संस्करण प्रदेश के सभी 12 ज़िलों में लागु किया जा रहा है। मिशन रीव अपने 10 खण्डों में विभाजित समस्त सेवाओं को आम लोगों में ले जाकर आवश्यकता आकलन के आधार पर समस्याओं का समाधान करेगा । दिल से सेवा भाव रखते हुए रीव सेवाकर्मी आपके पास आकर आपसे बात करेंगें और आपके लिए सेवाऐं देंगें। निश्चित भुगतान की स्थिति में भी आपसे हमारे साथी एक मुस्कान और दिल से भुगतान की बात करेंगे ..... यही ध्येय मिशन रीव को अन्यों से पृथक करता है।

पहले सेवा-बाद मे आमदन-आपके चेहरे पर मुस्कान : दिल से सेवा-दिल से भुगतान

इसी मूलमंत्र को मिशन रीव आपके आंगन में दस्तक दे रहा है। आपकी चिंता ही हमारी सेवा को दिशा देता है । समस्या का निदान हमारा सर्वोपरी लक्ष्य है।
आपकी समस्याओं का बेहतरीन सेवाओं के साथ सुगम्य विकल्प
आयु विशेष वर्ग में समस्याओं पर एक क्लिक से सुविधाऐं होंगी आपके द्वार

सेवाओं तक पहुंचने की प्रक्रिया

- मिशन रीव का प्राथमिक चरण इसके सदस्य बनने से आरंभ होता है। सदस्य बनने के लिए सर्वप्रथम ऑनलाईन फॉर्म भरे जाते हैं। इसमें कुछ आधारभूत औपचारिकताओं को पूरा करना होता है।
- सदस्यता लेने के साथ ही आम जन अपनी चिंताओं को रीव के साथ साझा करने व समाधान हेतु संबद्ध हो जाता है। इसमें उसका परिवार भी सेवाओ के लाभ का पात्र बन जाता है। द्वितीय संस्करण में सदस्यता प्रारुप अब सरल प्रक्रिया में आपके सामने हैं।
- सदस्यता के बाद सबसे महत्वपूर्ण क़दम आवश्यकता आकलन का है जो कि आयु विशेष वर्ग को आधार बनाकर तैयार किया गया है। अपनी आयु वर्ग में अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को मात्र एक क्लिक करके समाधान तक की प्रक्रिया को ऑनलाईन देख सकता है। यह इस प्रकार का पोर्टल और ऑनलाईन सेवा है जिसमें समस्या/ आवश्यकता पर क्लिक करते ही सामने उस समस्या के निदान के लिए किस विभाग या योजना से संपर्क करना है, उसका पूर्ण विवरण सामने आ जाता है। यानि समस्या के निदान की प्रक्रिया स्पष्ट रुप से सामने आ जाती है । उसके साथ ही उस सेवा के लिए भुगतान की जाने वाली राशि का पूर्ण विवरण भी सामने आ जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की मध्यस्तता की आवश्यकता ही नहीं रही और ऑनलाईन ही सारी सुविधाओं देखने, समझने और स्वीकार करने की यह एक अनूठी पहल है। शर्तों को स्वीकार करने के साथ ही मिशन रीव के स्वयंसेवक आपकी आवश्यकता आकलन को आधार बनाकर एक निश्चित समय के अंदर समाधान हेतु अनुबंधित हो जाते हैं।

आवश्यकता आकलन के माध्यम से सभी वर्गो की आवश्यकताओं का आकलन होगा। ये आयु वर्ग हैं: 0–6, 7–12, 13–18, 19–25, 26–35, 36–50, 51–60, 61–70 तथा 71 वर्ष की आयु से उपर का वर्ग। सदस्यता लेने के बाद संबन्धित आयु वर्ग के सदस्य अपनी आवश्यकताओं का आकलन ऑनलाईन कर पाऐंगें और आपको मिलेगा अपनी हर समस्या का समाधान।

आप सभी का मिशन के द्वितीय संस्करण में हार्दिक स्वागत है।

मिशन रीव की सेवाऐं

सेवाओं का लाभ सदस्यता के उपरांत आवश्यकता आकलन के आधार पर लिया जा सकेगा और आपके जीवन को सरल व खुशहाल बनाने के लिए मिशन रीव है निरंतर तत्पर।

स्वास्थ्य डिविजन

- स्वास्थ्य स्लेट–12 विभिन्न टेस्टों के साथ प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच
- मोबाईल मेडीकल लैब–78 मानकों पर आधारित स्वास्थ्य जांच
- जनऔषधि केंद्र– लोगों को घर द्वार पर सस्ती दवा उपलब्ध कराना
- टेलीमेडीसन– लोगों के घर पर ही स्वास्थ्य जांच और ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा

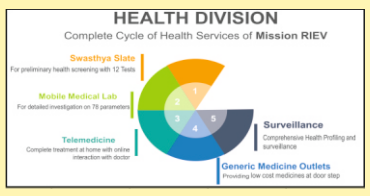

कृषि डिविजन

- मृदा परीक्षण लैब– सदस्यों और किसानों के लिए सेवाऐं
- जैविक खाद निर्माण–किसानों को जैविक खाद निशुल्क प्रशिक्षण और उनके द्वारा निर्मित खाद को बाजार उपलब्ध कराना
- बीज और कृषि उपकरण–किसानों को उनकी मांग के आधार पर उत्तम किस्म के बीज और आधुनिक उपकरण
- फीड सप्लीमेंट– पशुओं में दुग्ध उत्पादन और स्वास्थ्य सुधार के लिए
- जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना और कृषि विकास के लिए योजना बनाकर किसानों को सहयोग देना

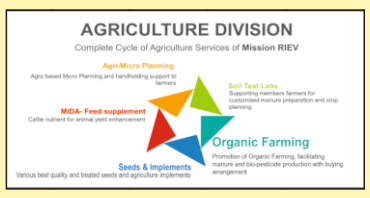

यूटिलिटी, लाइसेंस व अन्य ऑनलाइन सर्विसेज डिविजन

- सरकारी योजनाओं और उन पर मिलने वाली छूट की जानकारी आमजन तक पहुंचाना
- पंजीकरण, लाइसेंस, एनओसी और सर्टीफिकेट व अन्य संबंधित दस्तावेजों के निर्माण में सहयोग करना
- बिजली, पानी, व अन्य रोजमर्रा से संबंधित यूटीलिटी सेवाऐं उपलब्ध कराना
- ई– स्टेंप, ऑनलाइन शिकायत व अन्य ऑनलाइन सेवाऐं

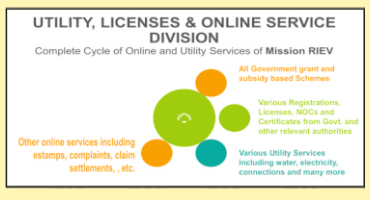

उद्यमिता और व्यवसाय विकास डिविजन

- क्षमतानुसार बेहतर व्यवसाय चयन और संसाधन जुटाने में सहयोग
- प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता संवर्द्धन में सेवाऐं
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, लोन दिलाने और व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग
- व्यवसाय शुरु करने से लेकर एक साल तक विभिन्न चरणों में सहयोग
- पहले से स्थापित व्यवसाय को बढ़ाने में सहयोग

बैंकिंग, फाइनेंस और इंशोरेंस डिविजन

- बचत, जमा और अन्य बैंकिंग सेवाओं में सहयोग
- बैंक लोन देना और रिकवरी व देनदारी संबंधि सेवाऐं
- संपत्ति प्रबंधन,जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, पशुधन और फसल बीमा संबंधि सेवाऐं

शिक्षा और प्रशिक्षण डिविजन

- गणित, विज्ञान और अंग्रेजी और अन्य विषयों पर ऑनलाइन कोचिंग
- साइकोमीट्रिक और फिंगर प्रिंट आधारित करियर परीक्षण
- व्यक्तित्व विकास और अन्य विकासात्मक पहलुओं में सहयोग
- बचपन, किशोरावस्था व व्यस्क आयुवर्ग आधार पर काउंसलिंग
- ई–लर्निंग टूल्ज और अन्य तकनीक

सामाजिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवा डिविजन

- बच्चों और बजुर्गों की देखभाल व महिला सशक्तिकरण व अक्षम वर्ग की देखभाल से संबंधित सेवाऐं
- पेंशन व उपलब्ध समय के सदुपयोग में सहयोग
- किसी भी आपदा और आकस्मिक दुर्घटना के समय सेवाऐं
- सामाजिक समस्या, कुरितियों और बुराईयों के निराकरण में पहल

ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग डिविजन

- गांवों में तैयार होने वाले शुद्ध उत्पादों का क्रय– विक्रय
- खरीददारों तक ग्रामीण उत्पादों को पहुंचाना
- गांवों में मांग आधारित उत्पादों की आपूर्ति करना और गांवों से उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना
- प्रदेश के भीतर आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना

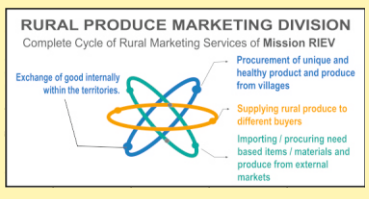

संपत्ति प्रबंधन डिविजन

- संपत्ति संबंधि देनदारियों, पंजीकरण, इंतकाल, राजस्व से संबंधित विभिन्न सेवाऐं
- नक्शा तैयार करवाने और स्थानीय प्राधिकरणों से मंजूरी आदि में सहयोग करना
- विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने में सहयोग

मीडिया, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन डिविजन

- द रीव टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल
- ग्रामीण विकास से जुड़ी समस्याओं को विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना
- मिशन रीव ने इस सेवाओं को सार्वजनिक कर आम आदमी को उसकी परेशानियों से मुक्त करने और देश हित तथा स्वयं के विकास के लिए स्वतंत्रता एवं समय प्रदान करने का एक सुअवसर प्रदान किया है ।

मृदा परीक्षण से लाभान्वित होंगे किसान

खण्ड मशोबरा में सर्वे में किसानों ने मिशन रीव के अंतर्गत मृदा जांच के लिए दिखाया उत्साह

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

मिशन रीव के अंतर्गत गांव में किसानों को मृदा जांच के लिए सुविधाऐं प्रदान की जा रही है। इसके लिए किसानों से गांव में जाकर जानकारी दी जा रही है और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश भी की जा रही है। मिशन रीव के कृषि प्रभाग से डॉ0 शशि किरण ने विकास खण्ड मशोबरा के विभिन्न गांवों का सर्वेक्षण किया और किसानों से बात की। उन्हें मृदा जांच के बारे में पूछा और मिशन रीव द्वारा घर पर ही इस सुविधा को उपलब्ध करवाने की जानकारी दी।

शिमला के शोघी के गांव खुशाला में किसानों से बात कर खेती बाड़ी में चल रहे समस्त कार्यों की जानकारी ली गई। वहां किसानों से बाद कर पता चला कि लोग अपने खेतों में मिट्टी की जांच करवाने के लिए इच्छुक है और उसी के आधार पर अपने खेतों में फसलों को लगाऐंगे। वहां लगभग 10 परिवारों से बातचीत के बाद मिशन रीव में मृदा जांच की भी जानकारी प्रदान की गई। वहां किसानों को रीव जैविक खाद की जानकरी दी गयी तथा इसके उपयोग की विधि पर भी चर्चा की गई। गांव खुशाला के किसान कपिल कुमार को रीव जैविक खाद का नमूना भी दिया गया। इसी प्रकार शनान क्षेत्र के गांव भरयुंटी में भी किसानों को मृदा जांच एवं रीव जैविक खाद की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि हम खेतों में किस प्रकार बिना मृदा जांच के ही फसलें उगाते हैं जिससे इसकी गुणवत्ता पर तो अंतर पड़ता ही है साथ ही सही फसल के न लगाने पर परिणाम भी सही नहीं होते हैं। मृदा जांच में यह पता लग जाता है कि खेत को किन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है और किस प्रकार की फसलें खेत में लगानी होगी। इस गांव में मदन कुमार, देवेन्द्र कुमार और शकुंतला देवी आदि से बात कर पूरी जानकारी प्रदान की गई साथ ही उन्हें सैंपल भी वितरित किए गए।

जुब्बल में मृदा जांच से लाभान्वित होंगे किसान

मृदा जांच शिविर में 12 तरह के मृदा परीक्षण होंगे उसी आधार पर रीव जैविक खाद भी रहेगी उपलब्ध

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

मिशन रीव (आईआईआरडी) के सौजन्य से शिमला ज़िले के जुब्बल में एक विशाल मृदा जांच शिविर का आयोजन कर रहा है । इसके लिए मिशन की ओर से टीम जुब्बल के लिए रवाना हुई। जुब्बल में किसानों की मांग पर मृदा जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर मे आसपास के गांव के लोग भाग लेंगे। मिशन रीव से टीम प्रतिनिधि दीपा ने बताया कि किसानों के खेतों से नमूने लेकर प्रत्येक नमूने के 12 टैस्ट किए जाऐंगे। इसके लिए रीव सदस्यों को अलग दाम पर तथा जो लोग सदस्य नहीं है, उन्हें अलग दाम पर ये सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ किसानों को मृदा परीक्षण का परिणाम भी साथ ही दिया जाऐगा। जांच के बाद आने वाले परिणामों के आधार पर रीव जैविक खाद की जानकारी दी जाएगी। यानि जिन पोषक तत्वों की खेत की मिट्टी में कमी होगी, रीव जैविक खाद उसी आधार पर तैयार होगी। रीव जैविक खाद पर भी रीव के प्रतिनिधि लोगों को जानकारी प्रदान करेंगे तथा इसका वितरण भी करेंगे ।

पाठकों से अपील

प्रिय पाठक वर्ग

पाक्षिक विकासात्मक समाचार पत्र 'द रीव टाइम्स' का नौवा अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है । आशा करता हूं कि पिछला अंक आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा। द रीव टाइम्स लोगों को जीवन में प्रगतिशील बनने में कारगर सिद्ध हो, इसी उद्देश्य से आप की प्रतिक्रियाओं, आलोचनाओं, सुझावों तथा परामर्श को सादर आमंत्रित करते हैं ताकि विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने संबन्धि सभी पहलुओं का क्रमबद्ध समावेश किया जा सके ।

आनन्द नायर प्रबन्ध संपादक

किन्नौर में बांटी गई रीव जैविक खाद

सोलन से पंहुची खाद को किसानों ने लिया हाथों-हाथ

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

किन्नौर में रीव जैविक खाद की मांग बढ़ती जा रही है । लोगों में खाद की गुणवत्ता को देखकर एवं उपयोग करने के बाद मिशन रीव के प्रतिनिधि गांव–गांव जाकर लोगों की मांग को पूरा करने के लिए प्रयासरत है । इसी के चलते रीव जैविक खाद को वितरण किया गया । टापरी और रिकांगपियो में किसानों को खाद का वितरण ज़िला समन्वयक मिशन रीव विशाल नेगी की अगुवाई में टीम के सदस्यों ने किया। कुछ किसानों से बात की गई जिन्हें रीव जैविक खाद का वितरण किया गया । उनके अनुसार उन्हें आगे भी इसकी आवश्यकता रहेगी । ये किसान हैं चंद्र भूषण, विभूति, हीरा सिंह, अश्विनी, मोनिका, लीला देवी आदि ।

रीव प्रतिनिधि ने बताया कि किन्नौर के लोगों की मांग की आपूर्ति की जाएगी तथा सभी किसानों को समय पर रीव जैविक खाद उपलब्ध करवायी जाएगी ।

लाहौल स्पिति में लोगों को मृदा जांच पर किया जागरुक

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

मिशन रीव के तहत पूरे प्रदेश में सुविधाजनक तरीके से घर–खेत में ही सस्ती प्रक्रिया के तहत मृदा जांच करवाई जा रही है। इसी के तहत दूरदराज के ज़िला लाहौल स्पिति के गांवों में मिशन रीव टीम ने इसके विषय में लोगों से बात की तथा उन्हें मृदा जांच के बारे में जागरुक किया। लोगों में खासा उत्साह देखा गया है तथा आने वाले समय में लोगों को घर–द्वार पर ही इस प्रकार की मृदा जांच की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं तथा अधिकतर लोगों को इस शिविर के लिए पंजीकृत किया जा रहा है। लोगों को यह जानकारी भी दी गई है कि मृदा जांच के आधार पर ही फसलों को खेतों में उगाने की प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि खेतों में पौष्टिक तत्वों की कमी का पता चलने के बाद रीव जैविक खाद के समिश्रण से इसे और अधिक बेहतर बनाया जा सकेगा जिससे किसान मन मुताबिक फसलों को उगा कर और मृदा पौष्टिक तत्वों की कमी को पूरा कर अपनी आर्थिकी भी मजबूत कर सकते है।

चायली पंचायत में मिशन रीव देगा अपनी सेवाऐं

पंचायत प्रधान मीरा ठाकुर ने सराही रीव की गतिविधियां

टीम रीव, शिमला

ग्राम पंचायत चायली में मिशन रीव अपने उत्पादों एवं कार्यक्रमों के साथ सेवाओं को प्रदान करेगा। मिशन रीव प्रतिनिधि ने जब वहां लोगों से संपर्क किया तो लोगों में रीव जैविक खाद एवं मृदा जांच के लिए अपनी सहमति भी दी। वहीं रीव प्रतिनिधि डॉ0 शशि किरण ने ग्राम पंचायत चायली की प्रधान मीरा ठाकुर से बात की तथा मिशन रीव की समस्त सेवाओं की जानकारी उन्हें दी। रीव के सभी उत्पादों से किसानों एवं ग्रामीणों को किस प्रकार संबद्ध कर उन्हें लाभान्वित किया जा सकता है, इसकी जानकारी प्रधान को दी गई। ग्राम पंचायत प्रधान मीरा ठाकुर ने मिशन रीव की सेवाओं की सराहना की तथा बताया कि उनकी पंचायत में किसानों के लिए यदि मृदा जांच शिविर लगता है तो पंचायत उसे सहयोग करेगी। साथ ही रीव जैविक खाद पर भी प्रशंसा की और कहा कि यह क़दम किसानों को घर–द्वार पर ही सेवाओं की उपलब्धता प्रदान करता है। गांव में किसानों विशेषकर महिलाओं को खेतों में जाकर रीव खाद का डेमो दिया गया। तथा खाद को महिलाओं को वितरित किया गया। महिलाओं ने मृदा जांच कर रीव जैविक खाद को खरीदने के लिए भी कहा ।

गडावग में महिलाओं को दी रीव जैविक खाद और मृदा जांच की जानकारी

टीम रीव, शिमला

मिशन रीव गांव–गांव में पहुंचने के उद्देश्य से अपनी सेवाओं को भी विस्तार दे रहा है। मिशन रीव के प्रतिनिधि लोगों से संपर्क कर रीव की योजनाओं एवं सेवाओं से उन्हे जोड़ रहे हैं। शिमला के समीप गांव गडावग में महिलाओं को मिशन प्रतिनिधि डॉ0 शशि किरण ने महिलाओं को गांव और खेतों में जा कर रीव जैविक खाद की जानकारी दी । महिलाओं ने रीव उत्पादों की प्रशंसा की और कहा कि यदि रीव जैविक खाद हमारे खेतों में बेहतर परिणाम देती है तो हम सभी को इसकी आवश्यकता रहेगी । साथ ही रीव के अन्य उत्पादों पर भी जानकारी प्रदान की गई।

रीव जैविक खाद का वितरण भी सैंपल के रुप में महिलाओं को किया गया। खेतों में खाद डालकर महिलाओं ने स्वयं इस परीक्षण भी किया ।

चायली ग्राम पंचायत की प्रधान मीरा ठाकुर से बात करते मिशन रीव के प्रतिनिधि

नेरी ग्राम पंचायत के प्रधान देवेन्द्र ठाकुर से बात करते मिशन रीव के प्रतिनिधि

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न ज़िलों के लिए रीव जैविक खाद को भिजवाते मिशन रीव के प्रतिनिधि

द रीव टाइम्स पहुच रहा है गांव-गांव मिल रही है सराहना

मिशन रीव के अंतर्गत पूरे हिमाचल में रीव जैविक खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई गई है। इसके प्राप्त करने लिए इन दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें .... 9459584566 और 8219175636, साथ ही आप हमारी वेबसाइट : missionriev.in/www.iirdshimla.org पर लॉगइन कर अधिक जानकारी ले सकते हैं

पूर्ण जैविक हिमाचल की ओर बढ़ते क़दम....

...रीव जैविक खाद

20रू. किलो / 40 किलो का कट्टा उपलब्ध है

Parameter	Percentage
PH	7-8
Organic carbon	7.36 - 9
Nitrogen	1.69 - 2
Phosphorus	0.75 - 1
Potassium	1.17 - 1.50
Sulphur	0.042 - 0.70
Zinc	0.0053 - 0.0075
Iron	0.14 - 0.30
Copper	0.0011
Calcium	2.2 - 3
Magnesium	1.03 - 1.20
Boron	0.0012
Manganese	0.0097
Calorific Value	219.96

किसानों को बताई जैविक खाद/पेस्टीसाईड बनाने की विधि

टीम रीव, ऊना

मिशन रीव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसमें जहां लोगों को उनकी जरूरतों का सामान और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है वहीं कृषि को व्यवसाय के तौर पर विकसित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बसोली में किसानों को जैविक खाद और प्राकृतिक (जीवामृत यानी पेस्टीसाइड बनाने की विधि) की जानकारी लोगों को दी गई। इस मौके पर आईआईआरडी ब्लॉक कोआर्डीनेटर किरण राणा , मोहन सिंह, स्वर्ण सिंह व रोशनी देवी मौजूद रहीं। ब्लॉक कोआर्डीनेटर किरण राणा ने किसानों को बताया कि जीवामृत भूमि की सभी कमियों को दूर करता है और मिट्टी को नरम कर देता है। मिट्टी नरम होने से पौधों को सभी पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं और भरपूर व स्वस्थ फसल होती है। उन्होंने बताया कि जीवामृत बनाने की विधि काफी आसान है और यह कम समय में बनकर तैयार हो जाता है।

यह बाजार में मिलने वाले रासायनिक पेस्टीसाइड के मुकाबले काफी सस्ता और अधिक प्रभावशाली होता है। इसके छिड़काव से न तो फसलों को कोई नुकसान होता है और न ही स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका इस्तेमाल करना भी आसान है और सिंचाई के पानी के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा लोगों को जैविक खाद बनाने की विधि भी मिशन रीव के तहत बताई जा रही है। इसके साथ ही इस खाद की बिक्री के लिए बाजार भी मिशन रीव के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है।

किसानों को नहीं मिल पा रहा है फसलों का उचित दाम

मिशन रीव घर से ही किसानों से खरीदेगा टमाटर और अन्य नकदी फसलें

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

सिरमौर और सोलन आदि ज़िलों के किसानों की टमाटर एवं अन्य नगदी फसलों को सब्जी मंडी तक पहुंचाने तथा उनसे घर पर ही उचित दाम पर खरीददारी करने के लिए सेवाएं प्रदान करेगा। दरअसल, किसान अपनी फसलों को मंडी तक पहुंचाने के लिए कई मुश्किलों से गुजरता है। दूर–दराज के गांवो में नगदी फसलों को मार्केट तक ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है जिससे उनकी फसलें विशेषकर टमाटर आदि मंडी तक आते–आते ख़राब हो जाते हैं और उनके दाम भूस के भाव भी नहीं रह जाते हैं। एक या दो रुपये किलो टमाटर के भाव से किसानों को बीज तक के दाम भी पूरे नहीं हो पाते हैं।

मिशन रीव अब इन्हीं दूर–दराज के गांवो के किसानों से उनकी फसलों को घर पर ही उचित दामों पर खरीद कर मंडी तक ले जाने में सहयोग करेगा। रीव प्रतिनिधि इस बाबत किसानों के संपर्क में हैं तथा इसके लिए किसानों से बात की जा रही है।

सामाजिक कार्यों में आगे मिशन रीव

टीम रीव ऊना

ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने के साथ साथ मिशन रीव के प्रतिनिधि समाजिक दायित्व को निभाने में भी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इसके तहत मिशन प्रतिनिधियों की ओर से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत हाल ही में ऊना में गगरेट के अतिरिक्त ब्लॉक समन्वयक साहिल उपमन्यु और उनकी टीम की ओर से नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों के साथ मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साहिल ने बताया कि सर्दियों में अक्सर अस्पतालों में रक्त की कमी हो जाती है।

इसके चलते मिशन रीव की ओर से नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान युवाओं को रक्तदान के लिए आगे आने के लिए भी प्रेरित किया गया और बताया गया कि रक्तदान से स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और स्वस्थ्य महिला व पुरूष हर तीन माह बाद रक्तदान कर सकते हैं। साहिल ने बताया कि मिशन रीव के तहत समय–समय पर विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है।

सोलन से जुब्बल और किन्नौर भेजी जैविक खाद

घर में ही खाद के उचित दाम मिलने से किसानों में खुशी

टीम रीव, सोलन

रीव जैविक खाद निर्माण में सोलन बेहतरीन कार्य कर रहा है। सोलन में किसान अब अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही बाजार में भी खाद की बिक्री कर रहे हैं। हाल ही में सोलन से मिशन रीव के तहत किसानों द्वारा तैयारी की गई खाद को किन्नौर और जुब्बल भेजा गया।

इस कार्य को करने के लिए रीव सचिवालय की ओर से सोलन विशेष टीम भेजी गई थी। किसानों को पहले मिशन रीव के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद किसानों ने खाद तैयार की और इसकी सूचना मिशन रीव के प्रतिनिधियों को दी। किसानों को केवल खाद तैयार करनी पड़ी जबकि इसकी पैकिंग से लेकर सप्लाई आर्डर लेने और तय स्थान पर इसे भेजने और वहां वितरित करने का पूरा कार्य मिशन रीव की ओर से गया। किसानों को खाद के उचित दाम उनके घर पर ही मिल गए, जिससे किसानों में खुशी की लहर है।

सोलन में किसानों को रीव खाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया था तथा उसके बाद गांव में किसानों ने अपने स्तर पर खाद तैयार की। खाद के दो प्रकार है। एक तो प्रथम चरण में रीव जैविक खाद जिसे सामान्य विधि से तैयार किया जाता है तथा दूसरी जिसमें एलगे पावर बूस्टर आदि मिला कर और अधिक गुणवत्ता बढ़ा दी जाती है।

ऐसा इसलिए आवश्यकता रहती है क्योंकि रीव मृदा जांच में यदि मिट्टी के गुणों को बढ़ाने की आवश्यकता रहती है तो एलगे मिश्रित रीव जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। सोलन में किसान जागरुक होकर कार्य कर रहे हैं, खेतों में अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। सोलन के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी किसानों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें इसी तरह बाजार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

लोगों के घर पर पहुंच रहा जरूरत का सामान

टीम रीव, ऊना

अन्य जिलों की तरह जिला ऊना में भी पंचायत फेसिलिटेटर लोगों को घर तक सुविधा देने मे अहम भूमिका निभा रहे हैं। अंब ब्लॉक के तहत पीएफ अश्विनी ने बताया कि वह गांव के लोगों को उनकी जरूरत का सामान उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं।

गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाजार नहीं जा सकते। ऐसे में इन लोगों को जब भी किसी सामान की जरूरत होती है तो वह पीएफ से संपर्क करते हैं और पीएफ जरूरत का सारा सामान घर तक पहुंचा देते हैं। कुछ उत्पाद मिशन रीव के तहत भी लोगों को बाजार से बेहद कम कीमत पर उनके घर तक पहुंचाए जा रहे है। इसके साथ ही अगर विभिन्न कार्यों के लिए जरूरी दस्तावेज बनवाना, सरकारी योजनाओं की जानकारी, खेती संबंधि समस्याओं का समाधान करने में भी मिशन रीव के प्रतिनिधि ग्रामीणों का भरपूर सहयोग कर रहे हैं जिससे लोग काफी संतुष्ट है।

हरोली में 83 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकापर्ण

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की कई घोषणाएं

टीम रीव, ऊना

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में ऊना दौरे के दौरान हरोली विस को करोड़ों रुपये की सौगात दी। हरोली विस क्षेत्र में 83 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं को समर्पित किया। उन्होंने प्रणव–बालिवाल–पूबोवाल सड़क के निर्माण के लिए 8.67 करोड़ रुपये, लालड़ी–कंगराथ सड़क के लिए 3.15 करोड़ रुपये, टाहलीवाल–बीटन–सिंगा सड़क के लिए 6.87 करोड़ रुपये, चंदपुर खड्ड पर पुल के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये और पलकवाह सीसे स्कूल भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की घोषणा की। उन्होंने सलोह में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जल समस्या को हल करने के लिए एशियन विकास बैंक को वित्त पोषण के लिए 10 करोड़ रुपये की चार पेयजल योजनाएं तैयार की जाएंगी। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने 1.88 करोड़ रुपये की लागत से पूरा होने वाले फूड पार्क तक गुरप्लाह–गोंदपुर सड़क के स्तरोन्यन कार्य और टाहलीवाल–बाथडी सड़क में बाथड़ी खड्ड पर 1.53 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 41.50 मीटर लंबे बॉक्स सेल पुल की आधारशिला रखी। उन्होंने पलकवाह में विभिन्न गांवों के लिए 2.08 करोड़ रुपये की उठाऊ जलापूर्ति योजना तथा पंजुआणा, धुग, नागनोली, पंडोगा, बदेहड़ा, पंजावर और बाथड़ी गांवों के लिए 6.87 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली उठाऊ सिचांई योजना की भी आधारशिलाएं रखीं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रामपुर–हरोली सड़क पर स्वां नदी पर 33 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 773.30 मीटर उच्च स्तरीय पुल का उद्घाटन किया। उन्होंने पंजावर–बाथड़ी सड़क पर खड्ड चैनल पर 1.78 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 62.3 मीटर कॉज वे पुल तथा नगनोली खड्ड पर नागनोली गांवों के लिए 2.09 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कॉज वे पुल का उद्घाटन किया। उन्होंने जोल–कैंथ सड़क तथा अमरोह–धरून कुहरू सड़क की आधारशिलाएं रखीं, जिन पर 10.33 करोड़ रुपये की लागत आएगी। उन्होंने 24.07 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले नंदपुर–मैड़ी सड़क के उन्नयन की भी आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए।

खस्ताहाल हो रहा केंद्रीय पुस्तकालय सोलन

टीम रीव, सोलन

केंद्रीय पुस्तकालय सोलन के भवन की हालत खस्ता होती जा रही है। हालात यह है कि पुस्तकालय की छत से पानी टपकता है और उससे अब किताबे खराब होन लगी है। माल रोड पर स्थित मोती लाल नेहरू केंद्रीय राज्य पुस्तकालय देश के प्राचीन इतिहास को संजोकर रख रहा है। इस पुस्तकालय में करीब 200 ऐसी पुस्तकें आज भी मौजूद हैं जो दुनिया के शायद किसी भी पुस्तकालय में नहीं मिलेंगी। यहां पर 1.20 लाख पुस्तकों का विशाल भंडार है। यह हिमाचल का एकमात्र पुस्तकालय है जहां इतने बड़े स्तर पर पुस्तकों को रखा गया है। इस पुस्तकालय को 1959 में खोला गया था। यहां पर पाठकों को केबिनेट कैटलॉग की सुविधा दी गई है जिससे पाठक कोई भी पुस्तक आसानी से खोज सकते हैं। इस पुस्तकालय में कई ऐसी पुस्तकें भी हैं जो हस्तलिखित हैं। पुस्तकालय में राजनीति, इतिहास, हस्त लिखित कविता और रेफरंस बुक, साहित्य, मुंशी प्रेम चंद की कहानियां, संस्कृति उपन्यास, हिंदी उपन्यास आदि मौजूद हैं।

पुस्तकालय के सदस्यों को ही मिलतीं हैं घर के लिए किताबें

पाठक कई बार किताबों को घर ले जाते हैं और बाद में पुस्तकालय में भी जमा करवाते हैं। पुस्तकालय में अधिकारी व कर्मचारी बच्चों को समय–समय पर किताबों के लिए रिमाइंडर करवाते हैं। उन्हीं पाठकों को घर के लिए किताबें दी जाती हैं जो पुस्तकालय का सदस्य हो। पुस्तकालय में बच्चों की सुविधा के लिए प्रतिदिन सात अंग्रेजी अखबार, सात हिंदी अखबार, एक उर्दू और पंजाबी समाचार पत्र भी आता है।

योजनाओं का लाभ लेने में सहायक बना मिशन रीव

विभिन्न जरूरतों को कर रहा पूरा

टीम रीव, कांगड़ा

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में मिशन रीव विभिन्न माध्यमों से सेवाओं को आमजन तक पहुंचा रहा है। बात जमीनी दस्तावेजों को बनाने की हो या किसी प्रमाण पत्र बनाने की। सभी काम करने में मिशन रीव ग्रामीणों का सहयोग कर रहा है। वर्तमान में ज़िला पंचायत कांगड़ा की विभिन्न पंचायतों में फेसिलिटेटर गांव के लोगों को सेवाएं दे रहे हैं।

लोगों के रोजमर्रा के जीवन में आने वाली सामान्य समस्याओं के समाधान के अतिरिक्त मिशन रीव के कार्यकर्त्ता उन दुर्गम क्षेत्रों में भी लोगों तक पहुंच रहे हैं, जहां पहुंच पाना बहुत ही कठिन है। मौजूदा समय में मिशन कार्यकर्त्ता स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को घर–द्वार पर ही उपलब्ध करवा रहे हैं। स्वास्थ्य स्लेट के माध्यम से विभिन्न तरह की स्वास्थ्य जांच घर–द्वार पर ही उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त जैविक खेती व जैविक खाद के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि आम आदमी को जैविक खाद की सही जानकारी व उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। ज़िला की अलग–अलग पंचायतों में परिवारों की आवश्यकताओं का आकलन किया जा रहा है तथा उनके अनुसार ही सेवाऐं प्रदान की जा रही है।

आईआईआरडी की ओर से पंचायतों में मिशन रीव के तहत नियुक्त किए गए प्रतिनिधि विभिन्न कार्यों के लिए जरूरी दस्तावेजों को बनाने में भी लोगों की सहायता कर रहे हैं। इसमें यूनिवर्सल हैल्थ कार्ड, बीपीएल परिवारों को इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने के लिए मिलने वाले अनुदान में सहायता करना और पैन कार्ड आदि बनाना शामिल है। इसके अलावा सैंकड़ों लोगों के आधार कार्ड पंचायत स्तर पर ही संशोधित किए गए, वृद्धों एवं विद्यवाओं को पेंशन लगवाने में सहायता की गई ताकि सरकार की योजनाएं लोगों को सुलभ हो सकें। घर–द्वार पर ही लोगों के विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य –टेस्ट सुनिश्चित किए जा रहे हैं जिनके लिए पहले लोगों को दूर – दूर तक जाना पड़ता था।

अपने गांव में ही रोजगार का मौका

टीम रीव, हमीरपुर

सिरमौर ज़िले में मिशन रीव के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर सेवाएं प्रदान की जा रही है। सेवाओं के साथ ही मिशन रीव ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के सबसे बड़े मिशन की ओर अग्रसर है।

ज़िले के अभी तक अनेक बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है तथा वे सभी ग्रामीण स्तर, खण्ड स्तर एवं ज़िला स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अभी भी यह प्रक्रिया जारी है। पंचायतों में बतौर फेसिलिटेटर तैनात किए गए युवा पंचायत से संपर्क कर गांव–गांव जाकर लोगों से सीधा संपर्क साध रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानकर उनका निवारण भी कर रहे हैं। लोगों की मांग पर कम कीमत में फूलों का बीज, मटर तथा मक्की का बीज लागों को उनके घर पर ही प्रदान किया गया। ऑनलाइन सेवाओं के बारे में आम ग्रामीणों को निरंतर जागरुक किया जा रहा है तथा किस प्रकार ऑनलाइन बिजली के बिल, टेलिफोन एवं अन्य बिलों का भुगतान अपने मोबाइल से ही घर बैठे कर सकते हैं, इसकी जानकारी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दी जा रही है। मिशन रीव से गांव में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा रहा है ।

खुले में कूड़ा फेंकने पर लगेगा जुर्माना

धर्मशाला नगर निगम ने गठित की कमेटी

टीम रीव कांगड़ा

नगर निगम धर्मशाला की ओर से कूड़ा निस्तारण को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। अब खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना भी लगेगा। एमसी धर्मशाला ने अपने नियम बनाने के लिए समिति का गठन किया है, जो खुले में कूड़ा फेंकने पर जुर्माना लगाने के नियम को जोड़ने की योजना बना रही है। धर्मशाला नगर निगम की ओर से कुछ और भी नियम बनाए जाने हैं जिसके लिए नगर निगम की ओर से पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें महापौर देवेंद्र जग्गी, उपमहापौर ओंकार नेहरिया, पूर्व महापौर एवं पार्षद रजनी ब्यास, नीनू शर्मा और सविता कार्की को रखा गया। समिति पहले देश के विभिन्न शहरी निकायों के नियमों की स्टडी करेगी। उसके बाद जो नियम धर्मशाला शहर की दृष्टि से सही लगते हों, उन्हें अपने नियमों में जोड़ेगी। उसके बाद उन निमयों को समिति हाउस में रखेगी, जिसमें सभी पार्षदों से बदलाव करने या जोड़ने के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। समिति विभिन्न शहरी निकायों के नियमों का अध्ययन करके अपने नियम बनाएगी। इसे मंजूरी के लिए हाउस में रखा जाएगा।

लोगों की अंकाक्षाओं पर खरा उतर रहा मिशन रीव

द रीव टाइम्स भी बना लोगों की पसंद

बिलासपुर, टीम रीव

बिलासपुर ज़िला में मिशन रीव लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतर रहा है तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सेवाओं को प्रदान किया जा रहा है। मिशन रीवे टीम ने साथ घर–घर जाकर लोगों की आवश्यकताओं का आकलन किया तथा सेवाओं के प्रति जागरुक भी किया।

लोगों ने बेहतर गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाने के लिए मांग की जिसे रीव के तहत हर संभव पूरा करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध करवाए गए हैं और उत्तम किस्म के पौधे भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिनमें लीची, आम, अमरुद, सेब, मौसम्मी, नीम इत्यादि पौधे शामिल है।

फेसिलिटेटर द्वारा विभिन्न पंचायतों में टीम रीव के साथ पेंशन फॉर्म भरने व अन्य औपचारिकताओं को पूरा करते हुए लाभार्थियों भी पेंशन लगवाई गई। ग्रामीण लोगों को पैन कार्ड की सुविधाओं से अवगत करवा कर इसे बनवाने में सहायता की। साथ ही यह प्रक्रिया सदस्यता से लेकर सेवाओं तक जारी है। मिशन रीव ने लोगों को मीटर लगाने की भी सेवाएं प्रदान की। लोगों को स्टील के टब की उपलब्धता करवा कर इसे लोगों में वितरित किया गया। लोगों के घर–घर जाकर सभी लोगों से जानकारी लेकर उनकी मांग के मुताबिक सेवाएं प्रदान की जा रही है।

इसके अलावा द रीव टाइम्स भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लोगों का कहना है इस समाचार पत्र में 15 दिन की खबरों का सार एक साथ मिल जाता है तथा साथ ही हर संस्करण में दी जाने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारी काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भी मिशन रीव काफी कारगर साबित हो रहा है।

घर पर ही जैविक खेती के गुर सिखा रहा मिशन रीव

लोगों के स्वास्थ्य के साथ पशुधन की भी देखभाल

हमीरपुर, टीम रीव

हमीरपुर में मिशन रीव लोगों के जीवन को आगे ले जाने में महत्पूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैविक खेती का प्रशिक्षण लोगों के घरों पर ही मिशन रीव के तहत दिया जा रहा है तो स्वास्थ्य जांच भी घर पर ही की जा रही है। इसके अलावा पशुओं के लिए फीड सप्लीमेंट दिया जा रहा है जिससे पशुओं के दुग्ध उत्पादन के साथ–साथ उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है।

सुजानपुर में बतौर स्वास्थ्य सेवक रजनीश बताते हैं कि वह पिछले तीन माह में करीब 15 सौ से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की प्रारंभिक जांच लोगों के घरों पर जाकर कर चुके हैं और लोग इस सुविधा से काफी खुश हैं। इसके अलावा जैविक खाद बनाने के प्रशिक्षण का भी लोग काफी लाभ ले रहे हैं।

सपाहल पंचायत के राजेश, ज्वाला प्रसाद, जयराम, परमील कुमार, राकेश किशोरी लाल व अन्य लोगों का कहना है कि मिशन रीव के तहत गांवों के लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिन योजनाओं का लाभ गांव तक नहीं पहुंच पाता, मिशन रीव उन्हें भी गांव के लोगों को उनके घर तक पहुंचा रहा है। मिशन रीव के तहत लोगों की जरूरतों को पहचाना गया बल्कि उनकी जरूरतों को पूरा भी किया जा रहा है। इसके लिए मिशन रीव के तहत पंचायत में तैनात आईआईआरडी के प्रतिनिधि विशेष बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

बिझड़ी ब्लॉक में पानी के ड्रमों का वितरण, काचवीं में लोगों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण, पशुओं को फीड सप्लीमेंट मुहैया कराने जैसी सेवाएं मिशन रीव के तहत लोगों को दी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले ऐसा कोई नहीं था जो घर तक आकर जरूरत का सामान पहुंचाकर दे। लेकिन अब मिशन रीव के तहत यह काम किया जा रहा है जिससे गांव का जीवन भी आसान हो गया है।

अपने स्तर पर सुविधाएं देने के अलावा मिशन रीव के तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी और उन योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जा सकता है इस बारे में भी मिशन रीव के तहत लोगों को अवगत करवाया जा रहा है।

एनएबीएल आईएसओ सर्टिफिकेट जारी करने वाली पहली लैब बनी धर्मशाला

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होगा मान्य

टीम रीव कांगड़ा

क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला देश की पहली एनएबीएल आईएसओ सर्टिफिकेट जारी करने वाली लैब बन गई है। लैब की ओर से जारी सर्टिफिकेट अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य होंगे। इन्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर की मान्यता का सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में जारी किया। इस प्रयोगशाला ने एशिया की सर्वश्रेष्ठ सरकारी फोरेंसिक प्रयोगशाला हांगकांग के साथ पिछले दो वर्षों से लगातार दक्षता परीक्षण में सफलतापूर्वक हिस्सा लिया है। उधर, मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला में डीएनए भवन की आधारशिला भी रखी। करीब एक करोड़ की लागत से बनने वाले इस भवन का निर्माण कार्य एक वर्ष में पूरा होगा। सीएम ने आपराधिक जांच में नियोजित वैज्ञानिक उपकरणों के अधिक से अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भी विभाग की जरूरतों को पूरा करने के निर्देश दिए है।

धर्मशाला में डीएनए की सुविधा मिलने से कांगड़ा, चंबा और ऊना जिलों को फायदा होगा। इससे पहले डीएनए से संबंधित मामलों को जुन्गा भेजा जाता था।

वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा शुरू

मुख्यमंत्री ने आरएफएसएल उत्तरी रेंज धर्मशाला में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा का भी शुभारंभ किया। इसके माध्यम से अब एक्सपर्ट को गवाही के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही वह किसी भी कोर्ट में अपनी गवाही दे सकेगा।

मिशन रीव ने लिया ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य का जिम्मा

टीम रीव, चंबा

चंबा के दूरदराज के गांवों में मिशन रीव लोगों के स्वास्थ्य का रक्षक बनता जा रहा है। खासकर उन गांवों में जहां आज भी लोगों को अस्पताल पहुंचने के लिए पूरा दिन लग जाता है, मिशन रीव की टीम लोगों के घरों पर ही स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में कामयाब रही है।

हाल ही में जडेरा पंचायत में स्वास्थ्य स्लेट जांच शिविर आयोजित गया। इसमें पंचायत के अधिकतर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इसके साथ ही उन्हें चंबा में आईआईआरडी की ओर से खोले गए जैनरिक औषधि केंद्रों की जानकारी भी दी गई। कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि उन्हें दवाइयां और जरूरत का अन्य सामान घर पर पहुंचाकर दिया जाए। इन लोगों को मिशन रीव की टीम ने पूरा सहयोग दिया।

इसके अलावा लोगों को मिशन रीव के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। सभी लोगों ने मिशन रीव के तहत गांवों में दी जा रही सेवाओं की सराहना की और कहा कि मिशन ने गांवों के लोगों का जीवन आसान बना दिया हैं।

भुंतर के हाथीथान में खुला जनऔषधि केंद्र

टीम रीव, कुल्लू

एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान, आईआईआरडी शिमला की एक नई पहल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में लोगों को सस्ते दामों पर दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तीन सौ जनऔषधि केंद्र खोले जा रहे हैं।

इसी के तहत कुल्लू में भुंतर के हाथीथान में भी जनऔषधि केंद्र खोला जा चुका है। भुंतर में यह पहला जनआषधि केंद्र है। इसके खुलने से भुंतर के लोगों को अब सस्ती दवाईयों के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। भुंतर निवासी गौरव का कहना है कि अभी तक उन्हें बाजार से मंहगे दामों पर दवाईयां खरीदनी पड़ती थी। कई बार तो ये दवाईयां जेब पर इतनी भारी पड़ जाती थी कि घर का पूरा बजट ही बिगड़ जाता था। लेकिन अब आईआईआरडी की ओर से प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना के तहत हाथीथान में सस्ती दवाईयां उपलब्ध हो रही है। इससे स्थानीय लोगों को काफी राहत है।

जनऔषधि केंद्र खुलने से इलाज सस्ता हो गया और लोगों के समय की भी बचत भी हो रही है क्योंकि उन्हें अब दवाईयां लेने बाजार नहीं जाना पड़ता।

उल्लेखनीय है प्रदेश के लोगों को सस्ती दवाईयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पांच जनऔषधि केन्द्रों का लोकार्पण तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य और वर्तमान मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश बीके अग्रवाल ने रीव सचिवालय शिमला से किया था।

उन्होंने इस दौरान कहा था कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और लोगों को इसकी रक्षा के लिए मंहगी दवाईयों के लिए अब नहीं तड़पना पड़ेगा तथा जनऔषधि केन्द्रों से अब सभी को सस्ते दामों पर दवाईयों की उपलब्धता होगी ।

ये मिल रही सुविधा

आईआईआरडी की ओर से खोले गए जनऔषधि केंद्रो पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ते दामों पर बेहतर क्वालिटी की दवाईयां उपलब्ध है।इससे पहले लोगों को सस्ती दवाओं के लिए शहरों में भटकना पड़ता था। आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा ने कहा कि आईआईआरडी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहा है।

इसी कड़ी में ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) की ओर से आईआईआरडी को हिमाचल में तीन सौ जनऔषधि चलाने की अनुमति प्रदान की गई है।

खरल पंचायत के लुहानी में खोला जाए स्वास्थ्य केंद्र

टीम रीव, चंबा

ग्राम पंचायत खरल के लुहानी गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोलने की ग्रामीणों ने मांग की है। लोगों ने बताया कि यहां पांच किमी के दायरे में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इसके कारण लोगों को छोटी से छोटी बीमारी का उपचार करवाने के लिए छह किमी दूर सलूणी जाना पड़ता है। ऐसे में अगर लुहानी में स्वास्थ्य केंद्र खुलता है तो सलूणी, खरल और सूरी पंचायतों में रहने वाली तीन हजार से ज्यादा की आबादी को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य केंद्र खुलने से ग्राम पंचायत के लोगों को लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले को जनमंच में भी उठाया गया था लेकिन कोई हल होता नहीं दिख रहा।

ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य विभाग गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए गंभीर ही नहीं है। इसकी वजह से लोगों को बीमारी का उपचार करवाने के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की कि उपरोक्त पंचायत में जल्द स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए।

ऐतिहासिक हुनसुन नाग मंदिर जलकर राख

टीम रीव, चंबा

जनजातीय क्षेत्र पांगी मुख्यालय किलाड़ में ऐतिहासिक हुनसुन नाग मंदिर आग की भेंट चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की तमाम कोशिशें की लेकिन देवदार की लकड़ी से निर्मित मंदिर का पूरा भवन देखते ही देखते राख के ढेर में तबदील हो गया। हालांकि लोग मंदिर में रखीं प्राचीन मूर्तियां बचाने में सफल रहे। पांगी घाटी में ऐतिहासिक मेला फूल यात्रा की शुरुआत इसी मंदिर से की जाती है। मंदिर पूरे इलाके के प्राचीन धार्मिक स्थलों में शुमार है। जानकारी के अनुसार 14 नवंबर की रात करीब पौने नौ बजे किलाड़ में बिजली सप्लाई बंद हो गई। पांच मिनट बाद बिजली बहाल होने पर मंदिर की छत में अचानक आग भड़क गई। मंदिर का निर्माण देवदार की लकड़ी से हुआ है। ऐसे में आग तेजी से फैली। इलाके में अग्निशमन विभाग का कोई स्टेशन नहीं है। सूचना मिलने पर पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने के प्रयास किए गए लेकिन पूरा मंदिर आग की भेंट चढ़ गया। बताया जा रहा है कि जलने के बाद छत नीचे गिरी, जिसके बाद लोगों ने मंदिर में स्थापित मूर्तियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार इलाके में न तो फायर टेंडर की सुविधा है और ना ही आग की घटना में रेस्क्यू के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता।

थुनाग में मिनी सचिवालय, मुख्यमंत्री ने रखी आधारशिला

टीम रीव, मंडी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते दिनों एक दिवसीय दौर के दौरान थुनाग में 28 करोड़ की लागत से बनने वाले मिनी सचिवालय भवन की आधारशिला रखी। वहीं सराज दीप उत्सव को जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय भवन अढ़ाई वर्ष में बनकर तैयार होगा। इसमें पांच मंजिलें होंगी।

भवन में एसडीएम, तहसील और आईपीएच विभाग के कार्यालयों सहित अन्य सभी कार्यालय मौजूद होंगे। भविष्य में जो भी नया कार्यालय सराज के लिए मिलेगा, उसे भी इसी भवन में खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा अभी तक कई विभागों के दफ्तर दूर–दूर हैं और कई विभागों के कार्यालय अभी बने ही नहीं हैं। यह एक ऐसा भवन बनेगा, जहां एक छत के नीचे कई विभागों के अधिकारी बैठेंगे। पहले लोगों को अलग–अलग जगह जाने से असुविधा होती थी। धन और वक्त दोनों की बर्बादी होती थी। अब यहां मिनी सचिवालय के बनने से लोगों को ऐसी असुविधाओं से छुटकारा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण के लिए 5 करोड़ देने की घोषणा भी की। बाकी पैसे का प्रावधान अगले बजट सत्र में किया जाएगा।

यह भी की घोषणाएं

सीएम ने कहा कि थुनाग में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। टैक्सी स्टैंड बनाया जाएगा, जिसका प्रारूप तैयार हो जाने के बाद धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। तूनागपुर से लेकर लोक निर्माण विभाग के विश्रामगृह तक पक्का पैदल रास्ता बनाने के लिए 5 लाख रुपये, 5 महिला मंडलों को 3–3 लाख रुपये प्रत्येक महिला मंडल के भवन निर्माण के लिए दिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 51000 रुपये दिए।

डोली गांव में पेयजल संकट

टीम रीव, चंबा

ग्राम पंचायत मंगला के गांव डोली में लोगों को पेयजल किल्लत से जूझना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पानी की आपूर्ति अनियमित तौर पर होती है और इस बारे में आईपीएच विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया गया है। लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। इस कारण ग्रामीणों में विभाग के प्रति खासा रोष है। ग्रामीणों ने आईपीएच विभाग के सहायक अभियंता से प्राथमिकता के आधार पर समस्या का स्थायी हल निकाले की मांग उठाई है। पानी की अनियमित आपूर्ति के चलते डोली मोहल्ले में रहने वाले 200 की आबादी परेशानियां झेलने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि डोली में काफी समय से पानी की अनियमित सप्लाई चल रही है। पंचायत प्रतिनिधियों ने विभाग से मांग की है कि पानी की समस्या का हल जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े।

सड़क सुविधा को तरसे लोग

टीम रीव, कुल्लू

उपमंडल बंजार की ग्राम पंचायत चैहणी के करीब आधा दर्जन गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। पंचायत के गांव मियागी, वछियार, चैहणी, खदरेहड व कांडी नाल की लगभग 250 आबादी पैदल चलने को मजबूर हैं। किसानों–बागवानों को फल व सब्जियों को पीठ पर उठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ रहा है। मरीजों को कुर्सी पर बिठा कर तीन से चार किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पडता है। वार्ड पंच नोक सिंह, देवेंद्र सिंह, लाल सिंह, चेत राम, चुनी लाल, नरोत्तम सिंह, भूपेंद्र सिंह, सुरेश चंद, दिनेश, देवेंद्र, रतीराम, भगत राम, खूब राम, अनंत राम, युवराज तथा भीमसेन का कहना है कि इन गांवों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2012 में सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। इसके बाद भी अभी तक सड़क का कार्य शुरू नहीं किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क सुविधा न होने के कारण गांव की बीमार महिला पुनी देवी को उपचार के लिए कुर्सी पर उठाकर सड़क तक पहुंचाया गया। ग्रामीणों का कहना है सबसे अधिक परेशानी गांव में किसी के बीमार पड़ने पर होती है। ग्रामीणों ने लोनिवि तथा स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी से जल्द ही सड़क का निर्माण शुरू करने की मांग की है।

दिघाई पंचायत के आधा दर्जन गांव आज भी सड़क से कोसों दूर

बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने में पेश आती हैं दिक्कतें

टीम रीव चंबा

ग्राम पंचायत दिघाई के आधा दर्जन गांव आज भी सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाए हैं। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को सड़क तक पहुंचने के लिए पहले आठ किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। लोगों का कहना है कि प्रशासन और लोनिवि को ज्ञापन देने के बाद भी सड़क का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। एहनी मोड़ से अंदेश्वर तक सड़क स्वीकृत है। लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। ऐसे में स्थानीय लोगों में काफी असंतोष है। लोगों का कहना है कि अगर सड़क बनती है तो आधा दर्जन गांव के करीब एक हजार लोगों को इसका लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बनाने के लिए ग्राम सभा में भी प्रस्ताव पास हो चुका है और इस बारे में लोकनिर्माण विभाग को भी अवगत करवाया जा चुका है। लेकिन उसके बाद भी सड़क का कार्य शुरू नहीं हो रहा है। सड़क न होने की वजह से ग्रामीणों को जरूरत का सामान पीठ पर उठाकर घरों तक पहुंचाना पड़ता है। इसके अलावा गांव में बीमार होने वाले व्यक्ति को पीठ या पालकी में उठाकर आठ किमी पैदल चलने के बाद सड़क तक पहुंचाया जाता है।

यहां से मरीज को एंबुलेंस या निजी वाहन के जरिये स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जाता है। इस दौरान तीमारदारों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से सड़क बनाने की मांग की है। वहीं अधिकारियों का तर्क है कि वन विभाग से एनओसी मिलना बाकि है। इसके मिलने के बाद ही काम शुरू हो पाएगा।

आओ कानून को जानें

इंडियन कानून धारा 376 आईपीसी - इंडियन पीनल कोड - बलात्कार के लिए दण्ड

जो भी व्यक्ति, धारा 376 के उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के तहत दंडनीय अपराध करता है और इस तरह के अपराधिक कृत्य के दौरान लगी चोट एक महिला की मृत्यु या सदैव शिथिल अवस्था का कारण बनती है तो उसे एक अवधि के लिए कठोर कारावास जो कि बीस साल से कम नहीं होगा से दंडित किया जाएगा, इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता हैं, जिसका मतलब है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए या मृत्यु होने तक कारावास की सजा ।'

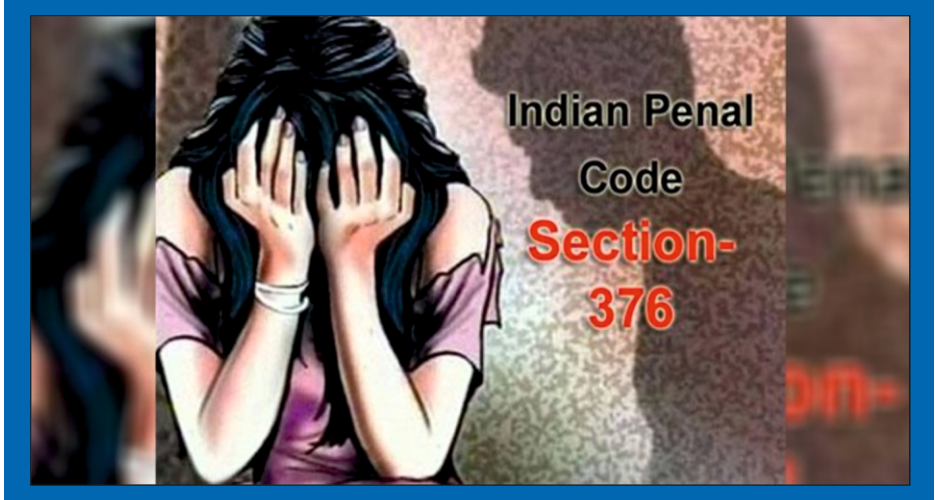

'आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013

लागू अपराध

बलात्कार

सजा – 7 वर्ष से कठोर आजीवन कारावास ।

आर्थिक दण्ड

यह एक गैर–जमानती, संज्ञेय अपराध और सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है।

एक पुलिस अधिकारी या एक सरकारी कर्मचारी या सशस्त्र बलों के सदस्य या जेल के प्रबंधन कर्मचारी, रिमांड घर या अन्य अभिरक्षा की जगह या महिला बच्चों की संस्था या प्रबंधन पर किसी व्यक्ति द्वारा बलात्कार द्वारा बलात्कार या किसी अस्पताल के प्रबंधन कर्मचारी द्वारा बलात्कार और बलात्कार पीड़ित के किसी भरोसेमंद या प्राधिकारिक के व्यक्ति द्वारा जैसे किसी नजदीकी संबंधी द्वारा बलात्कार ।

दंड – 10 साल से कठोर आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन तक के लिए) ।

आर्थिक दण्ड

यह एक गैर–जमानती, संज्ञेय अपराध और सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है ।

पत्नी से दुष्कर्म करने पर भी होगी सजा : यदि किसी व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी के साथ दुष्कर्म किया है और उसकी आयु 12 वर्ष से कम नहीं है तो अरोपी को दो वर्ष तक की सजा हो सकती है या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कई मामलों में अदालत पर्याप्त और विशेष कारणों से सजा की अवधि को कम कर सकती है।

आईपीसी धारा 375 परिभाषित करती है दुष्कर्म को जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। किसी भी कारण से संभोग क्रिया पूरी हुई हो अथवा नहीं कानूनन वो बलात्कार ही कहलाएगा। इस अपराध को अलग–अलग हालात और श्रेणी के हिसाब से धारा 375, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ के रूप में विभाजित किया गया है।

आपसी सहमति से बना संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। बांबे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है अगर कोई शिक्षित और 18 वर्ष की उम्र से बड़ी लड़की रिलेशनशिप में सहमति से संबंध बनाती है तो रिश्ते खराब होने के बाद वो बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती है। न्यायालय के मुताबिक समाज में यौन संबंधों को सही नहीं माना जाता है तब भी यदि कोई महिला यौन संबंधों के लिये 'न' नहीं कहती है तो उसे सहमति से बनाया संबंध माना जाएगा।

376(क)– अलग रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। जिसके लिए दो वर्ष तक की सजा और जुर्माना देना पड़ेगा।

376(ख) –लोक सेवा द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग करने की दशा में ये अपराध की श्रेणी में आएगा। जिसके लिए पांच वर्ष तक की जेल के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा।

376(ग)– जेल में अधिकारी द्वारा किसी महिला बंदी से संभोग करना भी बलात्कार की श्रेणी में आता है । जिसमें पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।

376(घ) – अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारी आदि से किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा तो वह तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। जिसकी सजा अवधि पांच साल तक हो सकती है।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार आईआईआरडी

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याऐं सादर आमंत्रित है । आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे कानून विशेषज्ञ ऐडवोकेट प्रदीप वर्मा अगले अंक में देंगे। प्रश्न हमारी मेल आई डी पर डालें therievtime@iirdshimla.org hem.raj@iirdshimla.org

'कुछ भी कर सोशल मीडिया पर डाल', कुछ यही हो गया है यंग जनरेशन का हाल

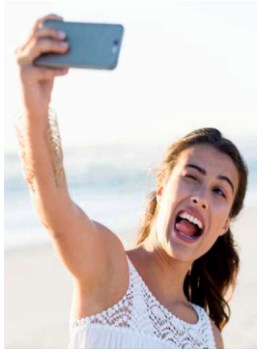

कभी लोगों को कहते सुना जाता था, नेकी कर दरिया में डाल। अब लोग कहने लगे हैं कुछ भी कर सोशल मीडिया पर डाल। यहां केवल शब्दों में ही नहीं, हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व में भी बदलाव आया है। इसकी मुख्य वजह लोगों में सोशल मीडिया का बहुत अधिक इस्तेमाल और लगातार बढ़ती पोस्ट करने की आदत है। कोई भी चीज एक सीमा तक ही सही रहती है। इसके बाद अपने दुष्परिणाम दिखाने लगती है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। इसके पीछे सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाले सेल्फी हैं, जिनका क्रेज पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। अब इसे लेकर किए गए एक अध्ययन में इसके दुष्परिणाम का भी जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि बहुत ज्यादा सेल्फी पोस्ट करने से लोगों में आत्ममुग्धता बढ़ती है। लोगों में यह बदलाव अच्छा संकेत नहीं है।

ओपेन साइकोलॉजी नामक जर्नल में इस अध्ययन को प्रकाशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि शोधकर्ता एक विशेष अध्ययन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इसके लिए शोधकर्ताओं ने 18 से 34 वर्ष के 74 लोगों पर निगरानी रखी और उनमें व्यक्तित्व यह बदलाव देखा। ब्रिटेन स्थित स्वांजी यूनिवर्सिटी और इटली की मिलान यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से यह अध्ययन किया है।

शोधकर्ताओं ने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचेट जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर प्रतिभागियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी। शोधकर्ताओं का कहना है कि आत्ममुग्धता व्यक्तित्व की एक विशेषता है, जिसमें व्यक्ति अपने आपको बहुत अधिक प्रदर्शित करता है और स्वयं को हर चीज के हकदार के रूप में दिखाता है। साथ ही दूसरों को कमतर आंकता है।

शोधकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर प्रतिभागियों की गतिविधियों पर चार माह तक निगरानी रखी और पाया कि जिन प्रतिभागियों ने सोशल मीडिया का बहुत अधिक इस्तेमाल किया और अत्यधिक सेल्फी पोस्ट कीं उनमें आत्ममुग्धता के लक्षण में 25 फीसद का इजाफा देखने को मिला। मापक पैमाने का प्रयोग कर शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि ऐसे प्रतिभागियों में इस लक्षण का यह स्तर विकार के स्तर तक पहुंच गया। यह उनके व्यक्तित्व के साथ–साथ स्वास्थ्य के लिए भी बुरा था।

अध्ययन में यह भी सामने आया कि प्रतिभागियों ने अपनी सेल्फी को सबसे ज्यादा फेसबुक पर पोस्ट किया। कुल सेल्फी की 60 फीसद सेल्फी फेसबुक पर, 25 फीसद इंस्टाग्राम पर और 13 फीसद ट्विटर, स्नैपचेट व अन्य साइट्स पर पोस्ट की गईं।

यह भी आया सामने

इसके अलावा शोधकर्ताओं ने अध्ययन में यह भी पता लगाया कि जो लोग ट्विटर जैसी माइक्रोब्लॉगिंग साइट का अपने विचार या शब्दों को पोस्ट करने के लिए अधिक प्रयोग करते हैं, उनमें इस तरह के लक्षण दिखाई नहीं दिए। यानी आत्ममुग्धता के लक्षण केवल बहुत अधिक सेल्फी पोस्ट करने वालों में ही सामने आए।

दो फीसद लोग इस बीमारी से ग्रस्त

बार–बार सेल्फी लेना और सुंदर दिखने के लिए फिल्टर्स का प्रयोग कर फोटो की एडिटिंग करना, अब ये शौक नहीं दिमागी बीमारी बनता जा रहा है । शोधकर्ताओं ने अध्ययन के आधार पर पता लगाया कि फोटो, खासकर सेल्फी में सुंदर दिखने वाले युवा शारीरिक कुरूपता संबंधी मानसिक विकार के शिकार हो रहे हैं। युवा पहले सेल्फी लेते हैं और फिर उन्हें फोटो पसंद न आए तो एडिटिंग के जरिये अपने लुक को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। बार–बार फोटो में सुंदर न दिखने पर लोग प्लास्टिक सर्जरी और अन्य थेरेपी की ओर रुख कर रहे हैं। कुल जनसंख्या में करीब दो प्रतिशत लोग इस बीमारी के शिकार हैं।

सोशल मीडिया को माना प्रामाणिक

शोध में सामने आया है कि बार–बार अपनी फोटो बदलने वाली और हाव–भाव बदल फोटो अपलोड करने वालीं लड़कियां मानती हैं कि सोशल मीडिया पर ही सुंदर दिखना वास्तव में सुंदर होना है । शोध में शामिल किए किए गए 55 प्रतिशत प्लास्टिक सर्जन का भी यही कहना है कि उनके पास सबसे ज्यादा ऐसे मरीज आ रहे हैं जो सेल्फी में सुंदर दिखना चाहते हैं ।

दिखावे से बचें

बुद्धिजीवियों का मानना है कि यह समस्या किशोरों के लिए बहुत खतरनाक है। चिकित्सकों को चाहिए कि वे अपने मरीजों को सोशल मीडिया के प्रभावों के बारे में बताएं और उनकी काउंसिलिंग करें। वहीं, उन्होंने सलाह दी है कि दिखावे को ज्यादा हावी न होने दें। दुनिया भर मे ऐसा ट्रेंड चल रहा है, जिसमें दिखावे खासकर सोशल मीडिया पर दिखावे को बहुत महत्व दिया जा रहा है। इसी के चलते लोग इस आभासी दुनिया को वास्तविक मानने लगे हैं। इसके परिणामस्वरूप बहुत से रोग उन्हें घेर रहे हैं। इन्हें खुद पर हावी होने से रोकना चाहिए।

सर्जरी नहीं है समाधान

बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल की नीलम वाशी का कहना है कि लोग स्नैपचौट डिस्मोर्फिया के शिकार हैं और वे अलग–अलग लुक में सुंदर दिखने के लिए सर्जरी करा रहे हैं। इसका समाधान सर्जरी नहीं है और सर्जरी से लुक और भी खराब होने का खतरा है। ऐसे लागों को सर्जरी के बजाय मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए।

आपका स्वास्थ्य हमारा परामर्श

छाती में इन्फेक्शन : भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर परिणाम

छाती में इन्फेक्शन होने के लिये जहाँ एक ओर कुपोषण यानि स्वस्थ व संतुलित आहार का अभाव व दूसरी तरफ दूषित वातावरण के कारण कीटाणुओं की हवा में भरमार ।...

क्या होता है छाती का इन्फेक्शन?

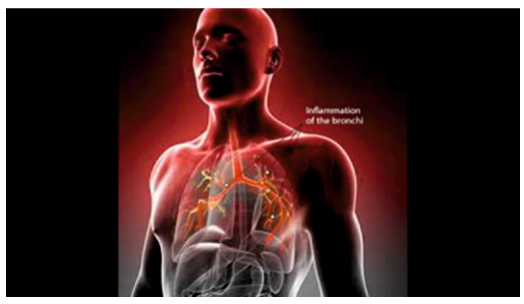

छाती के इन्फेक्शन में पहले गला ख़राब होता है फिर नमोनाईटिस यानि निमोनिया के लक्षण पनपनते हैं । उसके बाद निमोनिया यदि नियंत्रित नहीं होता तो टीबी यानि टयूबरक्युलोसिस का ख़तरा हो जाता है ।

अगर समय रहते न्यूमोनिया को नियंत्रण में न लाया गया तो मरीज को भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं । इसके अलावा छाती में और भी कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, जो फेफड़े को लगभग नष्ट ही कर देते हैं ।

खतरनाक हो सकती है लापरवाही

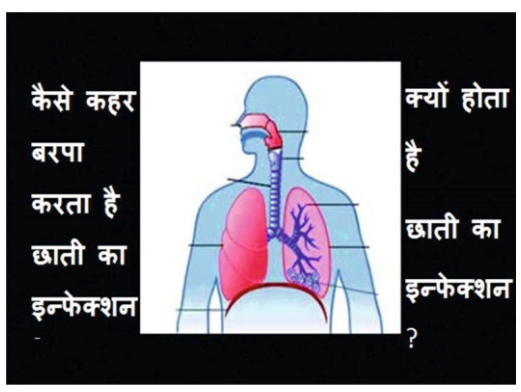

समय रहते यदि छाती के इन्फेक्शन को नियंत्रण में न लाया गया तो जानलेवा भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं ।

छाती के इन्फेक्शन का अगर समय पर पूरी तरह से खात्मा न किया गया तो एक तरह से यह इन्फेक्शन स्वंय ही लाइलाज हो जायेगा और कोई भी दवा असर करना बन्द कर देगी ।

दूसरी बात यह है कि इन्फेक्शन फेफड़े को धीरे-धीरे नष्ट कर देगा।

इसी तरह से अगर न्यूमोनिया के इन्फेक्शन को नियंत्रित न किया गया तो छाती में मवाद यानि पस बन जायेगा । ये पस आपके फेफड़े व आपकी जान दोनों के लिये घातक सिद्ध होगा । फेफड़े का हिस्सा नष्ट होगा ही होगा और साथ–साथ जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है ।

क्यों होता है छाती का इन्फेक्शन?

छाती में इन्फेक्शन होने के लिये जहाँ एक ओर कुपोषण यानि स्वस्थ व संतुलित आहार का अभाव व दूसरी तरफ दूषित वातावरण के कारण कीटाणुओं की हवा में भरमार। इसके साथ–साथ लोगों की आधुनिक व व्यायाम रहित जीवन शैली, पूर्ण निद्रा का अभाव व तनाव ग्रस्त मानसिकता है। अगर छाती के इन्फेक्शन को समय रहते नियंत्रित न किया गया तो फेफड़े के चारों ओर छाती के अन्दर पानी का जमाव होना शुरू हो जाता है । यह छाती में टी.बी. के इन्फेक्शन और उसके बाद कैंसर की शुरूआत है ।

अगर टीबी का पानी छाती से समय रहते न निकाला गया और टीबी के इन्फेक्शन को कंट्रोल न किया गया तो छाती में मवाद बनने की सम्भावना बड़ी प्रबल हो जाती है और ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है ।

छाती में इन्फेक्शन होने पर क्या करें ?

अगर छाती में इन्फेक्शन की आशंका है और आपके डॉक्टर उसे हफ्ते या दस दिन में कंट्रोल नहीं कर पा रहे है और समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है तो आप तुरन्त किसी अनुभवी चेस्ट विशेषज्ञ (पेनवरी फिजिशियन) से परामर्श लें और उनकी निगरानी में जरूरी जाँचें व प्रभावी इलाज करवायें, क्योंकि प्रारम्भिक दिनों में छोटे ऑपरेशन यानि छाती में एक टयूब/स्रिंज डालकर समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है और आगे चलकर जानलेवा फेफड़े की जटिलताओं को पनपने से रोका जा सकता है।

कुछ जरूरी जाँचें

छाती के इन्फेक्शन में पहले खून की जांच, थूक की जांच, चेस्ट एक्स–रे, छाती का सीटी स्कैन व कभी–कभी एमआरआई स्केन की भी जरूरत पड़ती हैं ।

डॉ0 के आर शांडिल
आईआईआरडी, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें: therievtime@iirdshimla.org

मुस्कुराहट लाने की ओर एक नऐ प्रयोग के साथ

कहा जाता है कि हमारे ज्ञान, चेतना व संसाधनों का स्वामित्व ईश्वर के पास है तथा हम मनुष्य इनके मात्र उपयोगकर्ता एवं देख–रेख करने वाले हैं। हमें ये विधाऐं ईश्वर के बनाए व अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों में बांटने के लिए मिली है, मात्र संचित करने के लिए नहीं। हम जितना इनको अधिक बांटने का प्रयास करते हैं, ईश्वर कई गुणा अधिक संसाधनों से पुनः उपकृत करते हैं तथा जितना अधिक हम मात्र अपने लिए संचित करने का प्रयास करते हैं उतना इनके ह्रास होने का भय बना रहता है।

हमारे समस्त विचारों, संकल्पों तथा कर्मों का प्रभाव प्रकृति में या ब्रह्माण्ड में विचरण करता है और पुनः हमारी ओर गुणात्मक आयतन के साथ आना आरम्भ होता है। यह ब्रह्माण्ड का नियम है। हम धनात्मक, आशावादी तथा आम जनोपयोगी विचारों का संप्रेषण करते हैं तो हम जीवन की यात्रा में अपने आपको अधिक उपयोगी पाते हैं। जितना भी सामर्थ्यानुसार हम अपने परिश्रम से अर्जित धन का अपने परिवेश में रहने वाले या अपनों के कष्टों को कम करने के उपयोग में लाते हैं, कई गुणा अधिक धन के आने की रचना प्रकृति बनानी आरम्भ करती है। उदासी, चिंता, भय, लोभ व जलन के संचार से बदले में अधिक मात्रा में ये ही मिलते हैं। जीवन में आगे बढ़ने की और कष्टों को साझा करने की आशा उत्पन्न करने से दूसरों के चेहरे में जो मुस्कान मिलेगी वही वापसी में कई गुणा अधिक हम को प्राप्त होगी। इस ब्रह्मांडीय नियम के ज्ञान का बोध न होना ही मनुष्य के बहुत सारे कष्टों का कारण भी है। इसे यदि आत्मसात किया जाए तो समाज कलहविहीन बन जाए, चहुंओर समृद्धि व खुशहाली का वातावरण बन जाएं। शायद यही हम सभी एक सरस व सम्पन्न समाज की कल्पना करते हैं। सम्पन्नता धन की अपेक्षा मन से जुड़ा पहलु है क्योंकि मानसिक रुप से प्रफुल्लित एक रंक भी धन से लदे अशांत राजा से कहीं अधिक सम्पन्न है। मानसिक संपन्नता ही आर्थिक संपन्नता को जन्म देती है, जबकि आर्थिक संपन्नता कभी मानसिक संपन्नता प्रदान नहीं कर सकती। अब प्रश्न यह है कि मानसिक संपन्नता लाने की पहल कैसे की जाए ताकि चेहरे पर शिकन की झुर्रियां नहीं अपितु मुस्कुराहट युक्त आभा की झलक हो।

इसके लिए यहां मनुष्य की चिंताओं का विवेचन करना आवश्यक हो जाता है। आज के व्यस्तता वाले दौरे में, धनोपार्जन में आगे बढ़ने की होड़ तथा कहीं–कहीं आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में संघर्षरत व्यक्तियों की चिंताओं के लक्षण, प्रकार तथा आयतन अलग–अलग हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इन से जुड़े समाधान तक जब तक नहीं पहुंच पाते, चिंता ज्यों की त्यों बनी रहेगी। चिंताऐं उम्र के अंतराल के अनुसार बदलती हैं तथा व्यवसाय के अनुसार अपना आकार बनाना आरम्भ करती हैं। जबकि इनका प्रादुर्भाव मूल आवश्यकताओं की समय पर पूर्ति एवं वांछित पूर्ति न होने से होता है। कई बार हम आवश्यकताओं व इच्छाओं में भेद न कर पाने से भी चिंता को जन्म देते हैं। ऐसे में जब उम्र के अनुसार आवश्यकताओं का विवेचन करते हैं तो हम पाते हैं कि आयु अंतराल 6 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 26 से 35 वर्ष, 36 से 50 वर्ष, 51 से 60 वर्ष, 61 से 70 वर्ष तथा 70 वर्ष से ऊपर वाले आयु समूहों में आवश्यकताऐं लगभग सामान्य सी रहती हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यवसाय प्रबन्धन, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण उत्पाद क्रय–विक्रय, वित्तिय व बैंकिंग सहयोग, विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ व विभिन्न ऑनलाईन सेवाओं आदि में भी जनमानस की आवश्यकताओं तथा चिंताओं को पाटने के प्रयास किए जा सकते हैं।

जब इतनी व्यापकता में व्यक्ति विशेष को चिंतामुक्त करने के प्रयास हो तो निश्चित ही इसके निष्पादन व निराकरण के लिए एक बड़े समूह में कार्यकर्ताओं की आवश्यकता रहनी स्वाभाविक है जिसमें आगे चलकर कार्यकर्ताओं का मानदेय, कार्य पद्धति, तकनीकी व्यवस्था आदि का समावेश होना अपरिहार्य है। अंततः इससे एक प्रकार की व्यवसायिक पृष्ठभूमि का निर्माण होने लगता है तथा समस्त व्यय पूर्ति के लिए उपभोक्ता शुल्क जैसी व्यवस्थाऐं जन्म लेना आरम्भ करने लगती है। सेवाओं को जब धन से जोड़कर देखें तो वे सेवाऐं नहीं रहती तथा बिना धन के सेवाओं में गुणवत्ता की कमी होते सिमट जाने का अंदेशा बना रहता है।

ऐसे में यह चुनौतीपूर्ण बन जाता है कि सेवाओं में उत्कृष्टता, निष्पादन में गुणवत्ता तथा मिलने के बाद चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आए बिना सामाजिकदायित्व वाले इस विचार की पुष्टि नहीं हो सकती जबकि इसकी पूरी व्यवस्था की आपूर्ति के लिए यदि सेवा प्राप्त करने वालों से कार्यानुरुप शुल्क लें तो कहीं यह उनके चेहरे पर शिक़न व झुर्रियों का कारण न बन जाए। इसी कशमकश में एक नया अध्याय लिखने के लिए मार्ग प्रशस्त होता है जहां हम व्यक्ति विशेष पर छोड़ें कि वह जितना देना चाहे.....दें जबकि सेवा प्रदातादल हर सेवा को दिल से देने के हरसंभव प्रयास करें।

मिशन रीव की प्रथम वर्षगांठ पर वर्षपर्यन्त की सीख से तथा प्रायोगात्मक दृष्टिकोणों से मिशन का दूसरा संस्करण 'दिल से सेवा–दिल से भुगतान' महावाक्य के साथ हिमाचलवासियों के सम्मुख प्रस्तुत करने से जो मिशन रीव गौरवान्वित हो रहा है, उससे असीम प्रसन्नता की अभिव्यक्ति होना स्वाभाविक है। हम आशान्वित है कि इस के माध्यम से हम हर चेहरे पर मुस्कान की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे।

डॉ0 एल सी शर्मा
प्रधान संपादक
md@iirdshimla.org

Rural Consumerism

India's economic growth has accelerated swiftly in the last two decades and so has the purchasing power of its population. McKinsey Global Institute (MGI) study suggests that if India continues to grow at the current pace, average household incomes will triple over the next two decades, making the country the world's fifth-largest consumer economy by 2025. The growing income and rising influence of the social media has enabled consumers to binge on good things irrespective of their prices.

India's rural population, accounting for about 12 per cent of the world's population, presents a huge, untapped market. Brands cannot afford to disregard vast opportunities rural India offers, taking into consideration the population density in such areas. Almost 67 per cent of companies in India are expanding their presence in tier IV cities.

A stronger rural India with increasing consumerism is also inciting demand for products and services. The people in the rural areas are now quality conscious and thus the rural market is emerging fast lucrative. Also, the increase in rate of literacy in rural areas has led to employment opportunities and hence higher incomes. The retail sector in these remote areas are becoming more organized and has become the second major occupation after agriculture.

A blend of consistent agro commodity prices, better irrigation facilities and greater involvement by the government in the agriculture sector has resulted in an increase in income of the farmers of rural India. Increased government involvement and better infrastructure has resulted in a meaningful impact on farmer's income and thus rural consumption demand.

Another reason for increase in rate of consumption in rural India is the exposure of internet and social media. The rural population has got exposed to the standard of living of the urban population and has started expecting a similar lifestyle for themselves. The masses demand better quality products and money worthy services. Big companies are increasingly sculpting their strategies and brand marketing to influence consumer in rural areas. Hindustan Unilever aimed to empower rural women to make its products reach every rural home by training rural women, reportedly, this initiative now delivers around 20 per cent of Unilever's overall rural sales. Meanwhile Godrej Consumer Products trains rural youth in channel sales. ITC has Choupal Sagar and Godrej Agrovet has large format retail stores called Adhaar in Indian hinterlands, While Coca-Cola, the beverage major since it re-entered India, intends to increase its rural reach.

Today, in spite of comparatively low incomes, rural consumers due to their majority share of the population altogether are India's largest consumers — 57% of current consumption is in rural areas versus 43 percent in cities. However, it is assumed that by 2025 the Indian consumer market will largely be an urban affair, with 62 percent of consumption in urban areas versus 38 percent in rural areas.

Most of the companies are steadily transforming their rural operations into viable profit centres. They have been devising 'reach strategies' which proved to be instrumental in selling to unsophisticated buyers in geographically dispersed locations.

According to Tata Strategic Management Group report, about one-third of fast-moving consumer goods (FMCG) and consumer durables are sold in rural markets. Companies that recognize this enormous opportunity are experimenting with various go-to-market models to garner their share of this growth. But the results have been mixed. An efficient sales and distribution model are the most critical factor to achieve profitable and sustainable growth in rural markets.

The hallmark of success in rural India is overcoming challenges in the three stages of the consumer lifecycle reaching, acquiring and retaining the rural customer. In terms of reaching the rural consumer, the biggest obstacles companies facing are inadequate distribution networks, partners with limited capabilities, long payment cycles, and weak marketing channels. As far as rural customer acquisition is concerned, understanding and meeting the diverse, specialized needs and preferences of such customers pose major challenges to companies.

As rural markets evolve and competition in rural markets intensifies, companies will have to look for new approaches to harness this opportunity in ways that protect their margins while also growing revenue. Deploying the correct sales and distribution model can assist companies in driving profitable growth in a relatively short span of time. Rural masters will have to find ways to scale operations without hurting their bottom line. For a rural performer, the challenge will be to create differentiated offerings and brand loyalty to retain customers and sustain their business models. Rural voyagers will build their own ecosystems and brand awareness to acquire new customers.

Mission RIEV, provides everything that companies require - consumer reach, acquisition and retention along with strong distribution networks of more than 10,000 dedicated people across Himachal Pradesh and on the success of this pilot project, it aims to go PAN India with the model. Through its reach and strong connect with family members in the village it has been able to increase the capabilities, reduce long payment cycles and enhance the marketing channels. With its vast & active network, Mission RIEV understands diverse local markets and consumer needs.

Mission RIEV provides immense opportunities for all big companies and multinationals for selling their products in geographically dispersed locations. An enormous opportunity waits these companies to experiment and garner market share and increase their growth and make their operations into a viable profit centre.

Join us in our initiative of making products available by reaching the last person in the village!

Anand Nair, Managing Editor
anand@iirdshimla.org

बंदरों और आवारा कुत्तों से शिमला असुरक्षित

समस्या से निपटने की कोई कारगर नीति नहीं बन पाई अभी तक

हेमराज चौहान
सहायक संपादक,
द रीव टाइम्स
chauhan.hemraj09@gmail.com

अपनी सुंदरता और पहाड़ों की रानी से मशहूर राजधानी शिमला अब आवारा कुत्तों और ख़तरनाक हो चुके बंदरों से असुरक्षा के घेरे में है। स्थिति यहां तक ख़राब हो चुकी है कि अब सड़कों और रास्तों तक में चलना सुरक्षित नहीं रह गया है। बंदरों ने पूरे शिमला पर एक प्रकार से कब्जा करके रखा है। विद्यालय जाते बच्चें अब न तो अकेले जा सकते हैं और न ही घर वापिस आ सकते हैं। उनके साथ एक परिचारक की आवश्यकता रहती है। इतना ही नहीं बाज़ार से सामान लाना अब ख़तरे से खाली नहीं रहा। बंदर सामान का थैला देखते ही हमलावर हो जाते हैं और सामान के साथ–साथ लोगों को भी घायल कर देते हैं। इन बंदरों ने अपने अपने स्थान निश्चित कर रखें हैं और हर समय नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। मौका देखते ही ये झपट पड़ते हैं। यह स्थिति पूरे शिमला में हैं और इस पर समय–समय पर सरकार और नगर निगम के समक्ष लोगों की गुहार लगती रही हैं। पर्यटकों को शिमला में प्रकृति की खूबसूरती कम और इन बंदरों का डर अधिक सता रहा है। सरकार और नगर निगम के पास कोई भी कारगर नीति अब तक नहीं थी। नतीजतन, समस्या जस की तस ही नहीं अपितु भयंकर होती जा रही है। पहले कहा गया कि पेड़ों पर एक ऐसा यंत्र लगाया जा रहा है जिसकी तीखी बीप की आवाज़ से बंदर परेशान होते हैं और दूर भाग जाते हैं। ऐसा प्रयोग हुआ भी। परंतु जिस पेड़ पर वो यंत्र था, बंदर उसी पेड़ पर उस बीप के संगीत का आनंद लेते पाए गए। फिर सरकार ने

जब बंदरों को मारने की स्वीकृति प्रदान की तो लगा कि अब कुछ राहत मिलेगी । किंतु सरकार की चालाकी और होशियारी भी प्रशंसनीय है । बंदरों को वर्मिन घोषित करने के बाद लोगों को ही बंदरों को मारने के लिए कहा गया और उसके लिए भी ढेरों शर्तों की अधिसूचनाऐं सामने रख दी। नतीजा..... यह योजना भी सिरे नहीं चढ़ पाई। जहां छुट–पुट बंदरों को मारने की बात सामने आई.....वहां कुछ धर्म के संचालक अपने–अपने झंडों पर हनुमान चालीसा छपवाकर सड़क पर आने की चेतावनी देने लगे। यहां तक कि जानवरों के साथ अन्याय के लिए आवाज़ बुलंद होने लगी।

प्रति बंदर औसतन 2 हज़ार के करीब खर्चा कर लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये बंदरों पर पानी की तरह बहाने के बाद समस्या जस की तस

उसके बाद बंदरों को निर्यात करने पर भी सरकार के कभी–कभार ब्यान आते रहे। इस पर भी चर्चा और उग्रता लिए कुछ धर्म के संवाहक हनुमान जी और श्रीराम जी को बीच में लाकर योजना को आईना दिखाते नज़र आने लगते हैं। बंदरों की नसबंदी का अभियान बड़े ज़ोर–शोर से शुरु होता है और फिर उसकी एक सफल रिपोर्ट भी सरकार और नगर निगम लोगों के सामने रखते हैं। पर न जाने क्यों बंदरों की तादात तो फिर भी कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। कोई भी सार्थक पहल अभी तक अपने नागरिकों के लिए इस समस्या पर करने में सर्वथा नाकाम रही है। इतना ही नहीं, बंदरों के कारण लोग जान तक गवां चुके हैं जिनमें विदेशी भी शामिल हैं। आए दिन बंदरों के काटने और खरोंचने की ख़बरें सुनने के लिए मिलती है और हमारे कर्ताधर्ता चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन चुनावी घोषणापत्र में यह मुद्दा सर्वोपरी होता है और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़ी–बड़ी डींगे हांकते हैं।

विगत वर्षों में बंदरों के हमलों के आंकड़े (आंकड़े साभार)

कुल संवेदनशील तहसीलें	
चंबा	4
कांगड़ा	7
ऊना	5
बिलासपुर	5
शिमला	4
सिरमौर	5
कुल्लू	3
हमीरपुर	2
सोलन	3
मंडी	1

आवारा कुत्तों ने भी अब शिमला में अपना आतंक बना रखा है। दिनोंदिन ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है । पर्यटक नगरी होने के कारण इस समस्या के लिए सरकार की चिंता घोषणाओं और अधिसूनाओं में ही सिमट कर रह जाती है । मॉल रोड़, रिज़, चौड़ा मैदान आदि सभी जगहों पर आवारा कुत्तों को दिन–रात देखा जा सकता है। ये कुत्ते सड़क के बीचों–बीच आराम से लेटे

बंदरो के हमले

वर्ष	हमले	मुआवजा (लाखों में)
2007	18	0.55
2008	71	3.38
2009	112	5.57
2010	163	8.92
2011	402	16.99
2012	399	20.08
2013	358	15.80
2014	513	24.24
2015	59	1.38
2016	102	2.38

कुत्तों को नगर निगम क्यों नहीं उठाता, ये समझ से परे हैं। इन आवारा कुत्तों ने बहुतों को अस्पताल तक पहुचा दिया है। बच्चों एवं बुजुर्गों को सबसे अधिक भयाकांत किया हुआ है। माननीय न्यायाल के आदेशों के बाद भी नगर निगम की छाती पर दर्जनों कुत्ते बेझिझक सारा दिन सोये रहते हैं। नगर निगम इस समस्या के प्रति भी संजीदा नज़र नहीं आता है। आवारा कुत्तों के काटने के मामले बड़ी तादात में सामने आ रहे हैं और प्रशासन उस पर ब्यान देकर अपना पल्ला झाड़ लेता है । ऐसे में लोग जांऐ तो कहां जांऐ ? किसी भी कारगर नीति के साथ सरकार और विशेष तौर पर नगर निगम को सामने आना ही होगा अन्यथा नागरिकों की सुरक्षा में इस असफलता के मायने समझ से परे हैं।

आवारा कुत्तों के लिए बनेंगे पार्क

नसबंदी से शिमला में कम हुई है बंदरों की संख्या

द रीव टाइम्स ब्यूरो

से बातचीत मे कहा महापौर नगर निगम शिमला कुसुम सदरेट ने बताया कि शिमला में इस समस्या से यहां के नागरिकों को दो–चार होना पड़ा है लेकिन अब इस पर निगम ने कुछ सफल क़दम उठाने के लिए प्रयास किए हैं। बंदरों की नसबंदी करवाने का कार्य हुआ है तथा इससे शहर में बंदरों की संख्या में कमी हुई है । महापौर ने बताया कि बंदरों से लोगों को बचाने के लिए शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर एक निगम बचाव कर्मी की तैनाती की गई है ।

आवारा कुत्तों के लिए बन रहे हैं पार्क

आवारा कुत्तों के लिए निगम शीघ्र ही एक पार्क बनाने की योजना पर कार्य कर रही है जिसमें कुत्तों के लिए खाने–पीने से लेकर खेलने तक की सुविधा होगी और शहर को आवारा कुत्तों से मुक्त कर दिया जाएगा ।

शिक्षा की ऊँची दुकानों का फीका पकवान कब तक

छात्रों के भविष्य से होते खिलवाड़ पर कौन लगाएगा रोक

अंजना ठाकुर
anjna@iirdshimla.org

आलीशान भवन, गाड़ियों से घिरा कैंपस और बाहर बड़ा सा बोर्ड, जिस पर आकर्षक शब्दों में लिखा है संस्थान का नाम। अपने भविष्य के सपने संजो रहे किसी भी छात्र और उसके अभिभावक को आकर्षित करने के लिए किसी भी निजी संस्थान का ये चित्रण काफी कारगर रहता है। भले भीतर कुछ न हो लेकिन दिखावे के आधार पर ये ऊंची दुकाने अक्सर छात्रों और उनके अभिभावकों को अपना फीका पकवान खिलाने में कामयाब हो ही जाती है और आखिर में जब जेब गर्म हो जाती है तो खुद का दिवालिया घोषित कर या किसी और बहाने से प्रबंधन इन दुकानों को बंद कर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने में जरा गुरेज नहीं करते। कहने को निजी संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए आयोग है, कायदे–कानून हैं लेकिन बावजूद इसके इन संस्थानों की मनमानी जारी रहना कहीं न कहीं हमारे नीति–नियंताओं की नीति निर्माण करने की क्षमता और हमारी शिक्षा प्रणाली की लचरता को मोटी रेखाओं से अंकित करता है। दरअसल, आज के दौर में शिक्षा को व्यवसाय बनाकर उसका बाजारीकरण किया जा रहा है।

निजी कोचिंग सेटर हर गली, मोहल्ले और

सोसायटी में सभी को झूठे प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसा रहे हैं और सरेआम शिक्षा के नाम पर सौदेबाजी कर रहे हैं। ऐसा कई बार होता है जब इन निजी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र कक्षाओं में अपना भविष्य तराशने की जगह सड़कों पर नारेबाजी करने को मजबूर हो जाते हैं। हाल ही में शिमला के एक नामी निजी संस्थान में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। संस्थान ने बच्चों से भारी भरकम फीस ली और फिर अपना उल्लू सीधा होते ही छात्रों को माइग्रेशन के लिए दबाव बनाया गया। बीच समेस्टर में छात्रों को जब परीक्षाओं की तैयारी करनी थी तो वह कैंपस में अपने हक के लिए नारे लगा रहे थे। मीडिया के सामने सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे थे और प्रदेश सचिवालय में मंत्रियों अधिकारियों को चक्कर काट रहे थे। मामले में फिलहाल आश्वासन ही अभी तक छात्रों को मिला। मामला अभी भी सुलझा नहीं है।

गुस्साए छात्र अब तोड़फोड़ पर उतर आए हैं और प्रशासन के खिलाफ छात्रों के साथ–साथ अभिभावकों में भी रोष है। अपने हक की इस लड़ाई में छात्रों को कहां तक कामयाबी मिलती है, यह तो आने वाले

समय में ही साफ हो पाएगा लेकिन इस घटना ने उन नियमों और नीतियों पर सवालिया निशान लगा दिया है जिनके तहत प्रदेश में पुंजीपतियों को शिक्षा के नाम पर दुकानें चलाने की अनुमति दे दी जाती है। एक समय था जब प्राचीन समय में छात्र गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। वहां गुरु छात्र को संस्कारित बनाता था लेकिन आधुनिक जीवन में लोगों के पास शायद विकल्प कम रह गए हैं और ये कोचिंग संस्थान इसी का फायदा उठाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनका शिक्षा से कोसों तक कोई नाता नहीं होता लेकिन उन्होंने अपने धन और ऊंची पहुंच के बल पर इन विद्या मंदिरों को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का साधन बना दिया है। अब सवाल यह है कि आखिरकार इसका उत्तरदायी कौन है? हम स्वयं, सरकार या हमारी शिक्षण पद्धति। इस बात का उत्तर फिलहाल शायद किसी के पास नहीं लेकिन यह भी सत्य है कि हमें मिलकर इस सवाल का जवाब गंभीरता से ढूंढना होगा ताकि हमारी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके और कल के कर्णधार सड़कों पर नारे लगाने की जगह कक्षाओं में बैठकर निश्चिंत होकर अपना भविष्य लिखे।

यह वही भारत है जो अपनी संस्कृति के कारण विश्व भर में विख्यात है और जहां दूसरे देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं लेकिन भारतीय संस्कृति की पहचान हमारी शिक्षा का नैतिक मूल्य स्तर किन कारणों से दिन–प्रतिदिन कम होता जा रहा

है, इस पर गंभीरता से मंथन करने की आवश्यकता है।

सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो निजी शिक्षण संस्थान नियंत्रण आयोग के मुताबिक प्रदेश में वर्तमान में 254 निजी शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। इस फेहरिस्त में सबसे उपर बीएड संस्थान हैं जिनकी संख्या 85 है।

हिमाचल में कितने हैं निजी संस्थान		
1	बायो साइंस	10
2	बीएड	85
3	डिग्री कॉलेज	57
4	डेंटल इंस्टीट्यूट	4
5	होम्योपैथिक	1
6	इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट	13
7	लॉ इंस्टीट्यूट	9
8	एमसीए इंस्टीट्यूट	1
9	नर्सिंग इंस्टीट्यूट	40
10	फार्मेसी इंस्टीट्यूट	12
11	संस्कृत इंस्टीट्यूट	16
	कुल	254

हिमाचल कैबिनेट ने विभिन्न पदों को भरने की दी मंजूरी, ये हैं 18 बड़े फैसले

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

मंत्रिमंडल की बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में रिक्त पदों को भरने सहित करीब 18 बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसंबर, 2018 तक बुलाने के लिए अपनी संस्तुति भेजने का निर्णय लिया। सत्र के दौरान 6 बैठकें होंगी। बैठक में 'स्वस्थ हिमाचल' के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री निरोग योजना शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की। यह योजना प्रदेश में सभी आयु वर्ग के स्थायी नागरिकों पर लागू होगी तथा इसका उद्देश्य लंबी अवधि की बीमारियों की मूलभूत स्वास्थ्य जांच करके शीघ्र निदान सुनिश्चित करना है। कैबिनेट ने अस्थायी पुलिस चौकी धबोटा को पुलिस स्टेशन नालागढ़ के तहत स्थायी पुलिस चौकी बनाने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के सुपर स्पेशिलिटी विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों की भर्ती जिसमें नर्सों के 144 पद भी शामिल हैं को भरने की मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट ने मंडी जिला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ सांइसिज नेर चौक को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को भरने की मंजूरी दी। इसमें कुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक तथा फाईनेंस ऑफिसर के पद शामिल हैं। कैबिनेट ने विश्वविद्यालय के बेहतर संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में खोले गए मेडिकल कॉलेजों में काडर निर्माण के लिए नीति के प्रारूप को भी मंजूरी प्रदान की। साथ ही हमीरपुर जिले में हिमुडा द्वारा समेंकित आवास एवं सल्म विकास कार्यक्रम के तहत निर्मित 72 फ्लैटों को डॉ. राधा कृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर को प्रदान करने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधानाचार्य (कॉलेज काडर) के 25 पदों को सीधी भर्ती के आधार पर भरने की अनुमति दी। साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन व भरने को मंजूरी दी। बैठक में पंचायत सहायक पदनाम को समाप्त करने तथा बदल कर पंचायत सचिव (अनुबंध) करने तथा उन्हें सरकारी नीति के अनुरूप नियमित करने का भी निर्णय लिया। उन्हें प्रतिमाह कम से कम 9710 का वेतन उपलब्ध करवाया जाएगा और ग्राम पंचायतों में अनुबंध आधार पर 300 पद पंचायत सचिवों के भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी सहभागिता आधार पर सोलन जिले के बद्दी में समेंकित ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजैक्ट स्थापित करने के लिए मैसर्ज जेबीआर टैक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड को सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र लगडू को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्तरोन्नत करने व आवश्यक पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की । इस निर्णय से 20,500 से अधिक की जनसंख्या लाभान्वित होगी। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा में सुधार व गुणवता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के गठन का निर्णय लिया। कैबिनेट ने सोलन जिले की कंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लेबोटरी में विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों को (नियमित आधार पर भरे जाने तक) आउट सोर्स आधार पर भरने की मंजूरी दी । साथ ही किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा लाभान्वित करने के लिए मंडी जिले के बगस्याड़ में उप मंडलीय मृदा संरक्षण कार्यालय को पांच पदों के सृजन के साथ स्थापित करने की प्रदान की। कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि विशेषकर पैट्रोलियम कम्पनियों को पैट्रोल व डीजल में मिलाने के लिए इथानोल लाने ले जाने पर किसी परमिट व पास की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही कोई निर्यात और आयात शुल्क या काराधान शुल्क भी नहीं लगेगा। मंत्रिमंडल ने राज्य परियोजना अवलोकन एवं नवीन प्रयास इकाई एवं राजकीय महाविद्यालयों में उत्कृष्ठता, दक्षता एवं स्वरोजगार पोषण केंद्र स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। इससे शिक्षित युवाओं को प्रतिष्ठित उद्योगों एवं संस्थानों में प्लेसमेंट दिलाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने उठाया हिमाचल बटालियन का मुदा

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

पश्चिमी कमाड चंडी मंदिर चंडीगढ़ के चीफ ऑफ स्टाफ ले. जनरल पीके बाली अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से को ओकओवर में भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं द्वारा भारतीय सेना में दी जा रही सेवाओं के मद्देनजर राज्य के लिए भारतीय सेना में अलग हिमाचल बटालियन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। सासे हेलीपैड को नागरिक उड़ानों के लिए प्रयोग किया जाए, ताकि क्षेत्र में जाने वाले पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध हो सके। ले. जनरल पीके बाली ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि वे इस मामले को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। सेना धर्मशाला में बनने वाले वार मेमोरियल के निर्माण में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। इस भेंट के दौरान पारस्परिक हितों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से राज्य के अधिकतम सिपाही भारतीय सेना में कार्यरत हैं। राज्य में एक लाख से अधिक पूर्व सैनिक हैं तथा सरकार ने उनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की है। राज्य सरकार हिमाचली युवाओं के लिए प्रादेशिक सेना के मुद्दे को उठाएगी। सेना प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के समय राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, मुख्य सचिव बीके अग्रवाल, सचिव जीएडी डॉ. आरएन बत्ता, पश्चिमी कमाड के कर्नल जस्बीर संधू, उपायुक्त शिमला अमित कश्यप, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विनय सिंह आदि उपस्थित थे।

शिमला कालका रेल मार्ग पर ट्रेन की गति बढ़ाने की कवायद, घुमावदार रास्ते पर नयी तकनीक का प्रयोग

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

रेलवे, यूनेस्को विश्व धरोहर शिमला कालका रेलखंड की 96 किलोमीटर की दूरी को तीन घंटे में पूरा कराने की कवायद में जुटा है । इसके लिये एक नई तकनीक के तहत रेलवे ट्रैक की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है तथा रेल पटरियों एवं स्लीपर में आवश्यक सुधार किया जा रहा है । शिमला कालका रेलखंड में 102 सुरंगें हैं और सैकड़ों घुमावदार मोड़ हैं जिनकी वजह से ट्रेन की रफ्तार कम रखनी पड़ती है। अब ऐसी पहल की जा रही है कि 48 डिग्री के तीव्र घुमाव वाले ट्रैक पर भी ट्रेन की रफ्तार बनी रहे । हाल ही में कालका–शिमला रेलमार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस ट्रैक पर चलने वाली गाड़ियों का समय करीब पांच घंटे से कम करके तीन घंटे करने की संभावनाएं तलाशने को कहा था। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार रेल मंत्री ने कालका–शिमला रेल मार्ग पर यात्रा अवधि तीन घंटे किए जाने हेतु संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए थे। इस साल के अंत तक इस संबंध में रिपोर्ट सौंपी जानी है। फिलहाल ट्रायल किए जा रहे हैं । शिमला से शोघी के बीच रफ्तार बढ़ाने के लिए ट्रैक को बेहतर बनाया जा रहा है । 22 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर चेकरेल डाला जा रहा है ताकि तेज गति से चल रही ट्रेन तीव्र घुमाव पर संतुलन बरकरार रखे । रेलवे अधिकारियों को उम्मीद है कि चेकरेल तकनीक से इस रूट पर ट्रेन 30–33 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल सकेगी जो अभी 20–22 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलती है। रेलवे के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि शिमला कालका रेलमार्ग पर जेडबीएम–3 इंजन चलता है जिसकी क्षमता 40 किलोमीटर प्रतिघंटा है। लेकिन घुमावदार मार्ग होने के कारण इसकी रफ्तार कम रखनी पड़ती है । हिमाचल प्रदेश में ही पठानकोट..जोगिन्दर नगर रेलमार्ग पर जेडबीएम–3 इंजन चलता है, लेकिन इसकी गति अधिक रहती है क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के बावजूद यह रेलमार्ग बिल्कुल सीधा है। शिमला कालका रेलमार्ग पर रेलवे ट्रैक की ऊंचाई बढ़ाने के साथ ही पटरियों के बीच रोड़ी एवं पत्थर भी डाले जा रहे हैं। रेलवे इस ट्रैक पर जल्द ही पूर्ण पारदर्शी कोच उतारेगा । यात्री इस कोच में बैठकर कालका–शिमला के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकेंगे ।

अनोखी परंपरा: यहां खून नहीं बहने तक पत्थरों की बरसात करते हैं लोग

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

राजधानी शिमला से करीब 35 किलोमीटर दूर हलोग धामी में को पत्थर मेले का आयोजन किया गया। यह ऐसा अजीब खेल है, जब तक खून न बहने लगे तब तक पत्थरों की बारिश नहीं रुकती। पत्थरों का यह मेला दीपावली के एक दिन बाद खेला जाता है। मेला देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़े। 25 मिनट तक दोनों तरफ से पत्थर बरसाए गए। इस बीच कनोड़ी के सुरेश शर्मा को पत्थर लगा। खून की धारा बहने लगी तो सुरेश को खेल का चौर में स्थित सत्ती स्मारक पर लाकर उसके खून से तिलक किया गया। मेला देखने के लिए सुन्नी, अर्की और राजधानी शिमला से भी लोग पहुंचे थे। पुलिस के पहरे में इस धार्मिक परंपरा को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करवाया गया। दोपहर बाद करीब चार बजे पत्थर का मेला शुरू हुआ जिसमें धमेड़ (धामी) की ओर से टीम में शामिल कनोड़ी के सुरेश शर्मा (धमेड़ टीम) के सिर पर पत्थर लगने पर पत्थरबाजी बंद करने का इशारा किया गया । जमोगी और दरबारी धामी की टीम के सभी खिलाड़ी स्मारक के पास एकत्र हुए और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नाचे। सुरेश ने बताया कि उसकी आंख के पास पत्थर लगा था। चोट लगने पर उसे हल्का दर्द महसूस हुआ लेकिन अब वह ठीक है। मेला आयोजन के दौरान नायब तहसीलदार धामी रोशन लाल कपाटिया भी मौके पर मौजूद रहे। राजदरबार धामी परिसर में स्थित भगवान नरसिंह के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भारी संख्या में खेल का चौरा तक पत्थर खेल स्थल तक ढोल नगाड़ों की थाप पर शोभायात्रा निकाली गई। इस बार पत्थर का यह खेल बहुत लंबा चला। पिछली बार पंद्रह मिनट में ही खेल समाप्त हो गया था लेकिन इस बार 25 से 30 मिनट तक चला। जानकारी के मुताबिक दोनों ओर से करीब दस लोगों को पत्थर लग चुके थे लेकिन किसी ने खेल नहीं रोका। पत्थर लगने पर लाल झंडा जरूर लहराया गया लेकिन पत्थरों की बौछार बंद नहीं हो रही थी। ऐसे में मेला कमेटी के सदस्यों को बड़ी लाठी उठाकर बीच में आना पड़ा, उनके मना करने के बावजूद पत्थर नहीं रुक रहे थे।

इस ढोंग से कब मुक्त होगा समाज

इस प्रथा को भी देवताओं और परंपरा के साथ जोड़कर मनाने वालों पर हंसी आती है । एक दूसरे पर पत्थर फेंकने वालों को नहीं मालूम कि भारत की परंपरा फूल फेंकने की है, पत्थर की नहीं । इसका विरोध संस्था ने लगातार किया है तथा इससे पूर्व भी बलि प्रथा को देवताओं के नाम पर समाज में प्रचारित करने वालों को हमने जनता के मध्य सामने लाया था ।

हिमाचल के खिलाड़ियों ने देश के लिए जीते 5 मेडल

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

जयपुर में चल रही अंतरराष्ट्रीय कॉमनवेल्थ मास्टर जूडो गेम्स में हिमाचल के खिलाड़ियों ने देश की झोली में 5 कांस्य और एक रजत पदक डाला है। प्रतियोगिता में 70 देशों के 500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें हिमाचल के छह खिलाड़ी शामिल हैं। 90 किलोग्राम भार वर्ग में विपिन चंदेल, 81 किलोग्राम में वीरेंद्र सिंह, 73 किलोग्राम में उत्तम डॉड, 65 किलोग्राम भार वर्ग में ध्यान सिंह और 60 किलोग्राम भार वर्ग में सुरेंद्र ठाकुर ने दमखम दिखाया। उन्होंने 4 कांस्य और 1 रजत जीतकर इतिहास रचा। विपिन चंदेल ने देश के लिए रजत पदक जीता। संजय यादव, वीरेंद्र धौलटा, ध्यान सिंह और उत्तम डॉड ने कांस्य पदक हासिल किया है। ध्यान सिंह और उत्तम डॉड इस प्रतियोगिता में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में खेले, विपिन चंदेल 45 वर्ष आयु वर्ग में खेल। संजय यादव और वीरेंद्र धौलटा 30 से 40 आयु वर्ग में खेले और प्रदेश और देश के लिए कांस्य और रजत पदक दिलाया।

इस उम्र के युवाओं को मिलेगा औद्योगिक भत्ता, अधिसूचना जारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

हिमाचल में लगे उद्योगों में कार्यरत हिमाचली कामगारों को 1000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार इन उद्योगों में 15 हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले 36 साल से कम उम्र के युवाओं को यह लाभ देगी। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा शारीरिक रुप से अक्षम कामगारों को 1500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। यह लाभ दो साल तक मिलता रहेगा। यह फायदा केवल उन्हीं हिमाचलियों को मिलेगा, जो अधिसूचना जारी होने के बाद नियुक्त होंगे, जबकि पहले के भर्ती कामगारों को नहीं दिया जाएगा। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने यह भत्ता देने का निर्णय लिया था । सरकार ने अब इस योजना की अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्य में स्थापित उद्योगों में नौकरी पाने वाले हिमाचल के स्थायी निवासियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। राज्य से बाहर के कामगारों के लिए यह योजना लागू नहीं है। इसकी अधिसूचना प्रधान सचिव श्रम एवं रोजगार की ओर से जारी की गई है। इस भत्ते को औद्योगिक भत्ता नाम दिया गया है। औद्योगिक भत्ते का लाभ पाने के लिए लाभार्थी का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज न होने पर यह भत्ता नहीं मिलेगा। प्रदेश में कौशल विकास भत्ता योजना पहले से ही चल रही है। इसी से मिलती–जुलती यह नई योजना अधिसूचित की गई है। माना जा रहा है कि इसका लाभ आने वाले समय में हजारों युवाओं को मिलेगा ।

राजस्व विभाग का कारनामा, तकसीम में बदल दिए जमीन के खसरा नंबर

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

शहर के साथ लगते सरगीण और दोची में राजस्व महकमे ने करोड़ों की जमीन की ऐसी पैमाईश कर डाली की भूमि मालिकों के खाता नंबर इधर से उधर हो गए। लोगों की जमीन भी किसी दूसरे खाते में शिफ्ट हो गई । मालिकाना हक किसी और के नाम होने से हिस्सेदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसमें एक दो नहीं बल्कि सरगीण गांव के 40 और दोची गांव के 73 हिस्सेदार शामिल हैं। इसमें एक हिस्सेदार ऐसे भी हैं जिनका दस्तावेजों में पहले डेढ़ बीघा हक था अब इसकी जगह नौ बिस्वा रह गया। राजस्व विभाग ने सौ बीघा से अधिक इस जमीन की तकसीम भी कर दी है। हिस्सेदारों को जब इस कथित गड़बड़झाले का पता चला तो उन्होंने तत्काल इंतकाल को रद्द करने के लिए लिखित में उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपा। तत्कालीन राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इस पूरे प्रकरण में पहले चरण में 40 हिस्सेदारों ने एक संयुक्त शिकायत दी है। इनमें शिकायतकर्ता नारायण सिंह ठाकुर ने कहा कि बंदोबस्त से पहले सरगीण गांव एक ही था लेकिन बाद में दो हिस्सों में बदल दिया । इसमें एक सरगीण और दूसरा दोची गांव हो गया। इन दो जगहों पर गांव वालों की बीघों के हिसाब से जमीनें हैं और इनके 100 से भी अधिक हिस्सेदार हैं। 28 जनवरी 2017 को तकसीम के लिए आवेदन किया। इसके बाद पता चला कि मालिकाना हक किसी और के नाम हो गया ह। यह अकेले उनके साथ नहीं कई हिस्सेदारों के साथ हुआ है। हिस्सेदारों ने उपायुक्त से अपील की है कि जब तक इंतकाल को रद्द न किया जाए तब तक जमीन के इन खाता नंबरों की रजिस्ट्री करने पर तत्काल रोक लगा दी जाए। न ही इन खाता नंबरों पर ऋण लेने की स्वीकृति दी जाए। राजस्व महकमे की वजह से दर्जनों हिस्सेदारों को परेशानी में डाल दिया है। इसके पीछे जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। डीसी शिमला अमित कश्यप ने कहा कि शिकायतपत्र को पढ़ने के बाद सभी तथ्य जांचें जाऐंगे। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई होगी ।

पांच मिनट के रास्ते में लग गए 18 मिनट

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला :

अग्निशमन विभाग ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। इसके लिए विभाग ने उपायुक्त कार्यालय से लोअर बाजार और शेर–ए–पंजाब से होते हुए माल रोड तक वाहनों से अभ्यास किया। उपायुक्त कार्यालय से शेर–ए–पंजाब तक पांच मिनट के रास्ते में विभाग के वाहन को निकलने में करीब 18 मिनट लग गए, जबकि मंगलवार को ट्रायल में अग्निशमन विभाग का छोटा वाहन लोअर बाजार से गुजारा गया था। छोटे वाहन में ही इतना अधिक समय लगने का कारण लोअर बाजार में जगह–जगह लगाई अस्थायी दुकानें थी। नगर निगम लगातार इन दुकानों को हटाने के दावे करता रहता है, मगर अग्निशमन विभाग के अभ्यास ने दावों की पोल खोल दी। लोअर बाजार से वाहन के गुजरने के दौरान संकरी सड़क एक बड़ी समस्या बन कर उभरी। साथ ही तहबाजारियों की जगह–जगह लगी अवैध दुकानें भी परेशानी बनी। ऐसे में वाहन को बाजार से निकलने में करीब 18 मिनट का समय लग गया। कुछ समय के लिए तहबाजारियों ने वाहन के लिए अपनी दुकानें हटा तो दी मगर वाहन निकलने के बाद सड़कों पर अवैध दुकानें फिर से लगने लगी। ऐसे में विभाग का यह अभ्यास भी मात्र औपचारिकता ही लग रहा था ।

भारत का पहला जलमार्ग बंदरगाह वाराणसी में आरंभ

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर 2018 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 2400 करोड़ रुपये की सौगात दी। उन्होंने यहां रामनगर स्थित पहले वॉटर वेज टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह जलमार्ग वाराणसी–हल्दिया मार्ग पर बनाया गया है।

गंगा नदी में बंगाल से वाराणसी तक पोत का परिचालन शुरू हो गया है। आज़ाद भारत में पहली बार गंगा के रास्ते एक कंटेनर कोलकाता से वाराणसी पहुंचा है। पेप्सिको कंपनी गंगा नदी के रास्ते जलपोत एमवी आरएन टैगोर के जरिए अपने 16 कंटेनर को कोलकाता से वाराणसी लेकर आई। इनलैंड वाटर हाइवे–1 पर दो जहाजों के माध्यम से ये कंटेनर आए, जिन्हें 30 अक्टूबर को कोलकाता से रवाना किया गया था।

यह जलपोत एमवी आरएन टैगोर वाराणसी से इफ्को कंपनी का उर्वरक लेकर वापस कोलकाता लौटेंगे। इस टर्मिनल को हल्दिया–वाराणसी के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग–1 पर विकसित किया जा रहा है। इस टर्मिनल के जरिए 1500 से 2000 टन के बड़े जहाजों की भी आवाजाही संभव हो सकेगी।

भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 - (इलाहाबाद से हल्दिया) – गंगा नदी से गुजरनेवाले 1680 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद–हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग–1 का दर्जा दिया गया है। इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, बाढ़, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता तथा हल्दिया है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-2 - (सादिया से धुबरी पद्दी) – ब्रह्मपुत्र नदी में धुबरी से सदिया तक के मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग–2 के नाम से जाना जाता है। इस जलमार्ग को वर्ष 1988 में राष्ट्री य जलमार्ग घोषित किया गया था। इस जलमार्ग की कुल लम्बाई 891 किमी है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-3 - (कोल्लम से कोट्टापुरम) – पश्चिमी भारत में स्थित तटीय नहरों की श्रृंखला को कोट्टापुरम से कोल्लयम तक राष्ट्रीय जालमार्ग – 3 घोषित किया गया है। इस जलमार्ग की शुरूआत वर्ष 1992 में हुई थी। इस राष्ट्रीय जलमार्ग कुल लंबाई 205 किमी है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-4 - (काकीनाडा से मरक्कानम) – काकीनाडा पुदुचेरी नहर विस्तार के साथ गोदावरी नदी विस्तार तथा कृष्णा नदी विस्तार को सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग–4 नाम से जाना जाता है। इस जलमार्ग की लंबाई 1095 किमी है। यह जलमार्ग चेन्नई बंदरगाह को काकीनाडा तथा मच्छलीपट्टम के बन्दरगाहों को जोड़ता है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-5 -(तलचर से धमरा) पूर्वी तटीय नहर प्रणाली में ब्राह्मणी तथा महानदी डेल्टा क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 5 के नाम से जाना जाता है। यह जलमार्ग मंगलगडी से पारादीप बन्दतरगाह के बीच 101 किमी जलमार्ग को भी जोड़ता है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 623 किमी है. इसकी शुरूआत 1985 में हुई थी इसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय जलामार्ग घोषित किया गया था।

राष्ट्रीय जलमार्ग-6 - (लखीपुर से भंगा) भंगा से लखीपुर जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 कहा गया है। अभी यह जलमार्ग प्रस्तावित है इसकी शुरूआत अभी नहीं हुई है। इस राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई 121 किमी है।

मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत दिसंबर 2018 में यूनिसेफ की मातृत्व, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य हितधारकों की भागीदीरी बैठक की मेजबानी करेगा। इसमें करीब 100 देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पार्टनर्शिप फॉर मैटेरनल, न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ (पीएमएनसीएच) के साथ मिलकर दिसंबर 2018 में कार्यक्रम की मेजबानी करेगा।

यूनिसेफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचेलेट और पीएमएनसीएच के अध्यक्ष कार्यक्रम के मुख्य वक्ता होंगे। यूनिसेफ के अनुसार, भारत ने मातृ स्वास्थ्य और बाल मृत्यु दर संकेतकों में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

वर्ष 2010 के बाद यह दूसरी बार है जब भारत में यूनिसेफ का यह कार्यक्रम आयोजित होगा। भारत ने मातृ स्वास्थ्य और बाल मृत्यु दर संकेतकों में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

यूनीसेफ

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। वर्ष 1953 में यूनीसेफ, संयुक्त राष्ट्र का स्थाई सदस्य बन गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनीसेफ को वर्ष 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1989 में संगठन को इंदिरा गाँधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसके 120 से अधिक शहरों में कार्यालय हैं और 190 से अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत हैं।

भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज मार्ग पर मानव रहित क्रॉसिंग को समाप्त किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज पर सभी मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग बंद करने का निर्णय लिया है। 01 अप्रैल 2018 के अनुसार ब्रॉड गेज मार्गों पर 3479 मानव रहित लेवल क्रॉसिंग हैं। पिछले सात महीनों में कुल मिलाकर ऐसे 3402 क्रॉसिंग समाप्त किए गए हैं। बाकी बचे 77 क्रॉसिंग दिसंबर 2018 तक बंद करने की योजना है।

भारतीय रेलवे

भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेलवे का 1,51,000 किलोमीटर ट्रैक, 7000 स्टेशन, 13 लाख कर्मचारी तथा 160 वर्षों का इतिहास है। भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर और थाने के बीच हुई थी। राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में भारतीय रेलवे अग्रणी रहा है।

भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गश्ती जहाज आईसीजीएस वाराह लॉन्च

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गश्ती जहाज़ आईसीजीएस वाराह लॉन्च किया गया। यह गश्ती जहाज समुद्र के तटीय इलाकों में गश्त करने के लिए लाया गया है। यह एक ऑफशोर पट्रोल वेसल है, इसे चेन्नई के लार्सन एंड टुब्रो कट्टुपल्ली शिपयार्ड में लांच किया गया। यह 98एम ओपीवी श्रेणी का चौथा गश्ती जहाज है। इसका निर्माण लार्सेन एंड टुब्रो द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। इस जहाज में एडवांस्ड नेविगेशन तथा संचार उपकरण, सेंसर तथा मशीनरी का उपयोग किया गया है। इसमें 30 मिमी तथा दो 12.7 मिमी गन का उपयोग किया गया है। इसकी अधिकतम गति 26 नॉट है। इसमें इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, ऑटोमेटेड पॉवर मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड प्लेटफार्म मैनेजमेंट हाई पॉवर एक्सटर्नल फायर फाइटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है।

टॉप कैबिनेट मंजूरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को भारत और कोरिया के मध्य समझौता ज्ञपन को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और कोरिया के मध्य समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस समझौता ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करना, पर्यटन से संबंधित जानकारी और डाटा के आदान–प्रदान को बढ़ाना, मानव संसाधन विकास में सहयोग के लिए आदान–प्रदान कार्यक्रमों को स्थापित करना, सुरक्षित, सम्मानित और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना, एक–दूसरे के देश में यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना इत्यादि हैं।

संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों देशों को आईएसए की सदस्यता के लिए प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की सदस्यता के लिए आईएसए के समझौता ढांचे में संशोधन के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की प्रथम बैठक में प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता देने से सौर ऊर्जा वैश्विक एजेंडा में शामिल हो जाएगा और सौर ऊर्जा के विकास और तैनाती के लिए सार्वभौमिक अपील की जा सकेगी।

कानूनी सहायता पर भारत और मोरक्को के बीच समझौते को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत और मोरक्को के बीच समझौते को अपनी स्वीकृति दे दी है। यह समझौता भारत और मोरक्को के बीच अपराध की जांच तथा अभियोजन, रोकथाम, अपराध से हुई प्राप्तियों और अपराध के साधनों की जब्ती तथा अपराध के तरीकों से निपटने में व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य अपराध की जांच और अभियोजन को अधिक कारगर बनाना तथा समाज के लिए आवश्यक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करना है। यह समझौता संगठित अपराधियों और आतंकवादियों के तौर–तरीकों के बारे में जानकारी हासिल करने में सहायता देगा और परिणामस्वरूप आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में उचित नीतिगत निर्णय लिए जा सकेंगे।

भारतीय सेना में 30 वर्ष बाद दो तोपों को शामिल किया गया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय सेना में 09 नवम्बर 2018 को दो तोपों को शामिल किया गया है। 30 साल के लंबे अंतराल के बाद भारतीय सेना में किसी तोप को शामिल किया गया है। इनमें एक अमेरिकन तोप है तो दूसरी कोरियन तोप है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने देवलाली में एम 777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर और के 9 वज्र सेल्फ़ प्रोपेल्ड गन को सेना को सौंपा। बोफोर्स के बाद ये पहली 155 एमएम तोप है जो कि भारतीय सेना में शामिल हुई है। इससे आर्टिलरी की ताक़त में इज़ाफ़ा होगा।

कोचीन में देश के सबसे बड़े ड्राई डॉक के निर्माण की घोषणा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत के सबसे बड़े ड्राई डॉक का निर्माण किये जाने के लिए केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में परियोजना का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी परियोजना मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण किया जायेगा।

कोचीन शिपयार्ड में पहले से ही दो ड्राइ डॉक मौजूद हैं, लेकिन वो दोनों ही इस नए बनने वाले ड्राइ डॉक से छोटे हैं। इस निर्माण के साथ ही भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में जहाज़ मरम्मत का हब बन कर उभरेगा। ड्राइ डॉक कोची का निर्माण कोचीन शिपयार्ड में किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1799 करोड़ रुपये है।

यह नया ड्राइ डॉक 310 मीटर लंबा व 75 मीटर चौड़ा होने के साथ ही 13 मीटर गहरा भी होगा। इस डॉक का उपयोग समुद्री जहाज के निर्माण व उसकी मरम्मत के लिए किया जाएगा। इस डॉक में एलएनजी कैरिज, ड्रिल शिप व इंडियन नैवी के विमानवाहक पोत को भी खड़ा किया किया जा सकेगा। इस ड्राइ डॉक के निर्माण के साथ ही वैश्विक जहाज़ निर्माण में भारत की हिस्सेदारी में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इस परियोजना के मई 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है।

ड्राई डॉक (शुष्क गोदी)

ड्राई डॉक (शुष्क गोदी) एक ऐसा संरचित क्षेत्र होता है जिसमें व्यापारिक जहाजों और नौकाओं के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव संबंधी कार्य किए जाते हैं। इसके विशेष प्रकार के निर्माण में पानी भरा जा सकता है जिसे लॉक एरिया कहा जाता है, इससे जहाज इस क्षेत्र में आ–जा सकते है। एक बार जहाज के अंदर आ जाने पर मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं तथा समुद्र के पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा करने पर जहाज को लंबे समय तक यहां रखा जा सकता है तथा मरम्मत का काम किया जा सकता है।

जस्टिस हेमंत गुप्ता, आर सुभाष रेड्डी, एमआर शाह और अजय रस्तोगी ने ली सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 02 नवम्बर 2018 को जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अजय रस्तोगी को सुप्रीम कोर्ट के जज के पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति ने सबसे कम समय में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश स्वीकार करते हुए जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का आदेश पारित किया है। इन चारों जजों की नियुक्तियां उनके पद ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी।

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या:

चार नए जजों के शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 28 हो गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल मंजूर पद 31 हैं, जिसमें अभी भी तीन पद खाली रह गए हैं। हाईकोर्ट में जज की सेवानिवृत्ति आयु 62 है. सुप्रीम कोर्ट जस्टिस 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

अयोध्या विवाद पर सुनवाई जनवरी 2019 तक टली

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को अयोध्या विवाद पर सुनवाई जनवरी 2019 तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच 2010 में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विचार कर रही थी।

क्या था मामला?

इस्माइल फारूकी ने अयोध्या में भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी थी जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि नमाज पढ़ना मस्जिद का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। मुस्लिम समुदाय इससे सहमत नहीं था और वह चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर दोबारा से विचार करे। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दलील दी गई थी कि मस्जिद में नमाज़ मामले पर जल्द निर्णय लिया जाए।

मुस्लिम समुदाय यह भी चाहता था कि मुख्य मामले से पहले 1994 के इस फैसले पर सुनवाई हो। अयोध्या जमीन विवाद पर फैसला तथ्यों के आधार पर होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रखा था। इसके साथ ही राम जन्मभूमि में यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया गया था, ताकि हिंदू धर्म के लोग वहां पूजा कर सकें। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में जो फैसला दिया था उसके खिलाफ हिंदू महासभा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले मामले की सुनवाई चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर कर रहे थे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने LEAP और ARPIT कार्यक्रम लॉन्च किये

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए अर्पित (एन्युअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग) और लीप (लीडरशिप फार ऐकेडमिशियन्स प्रोग्राम) नाम से दो नए प्रोग्राम लॉन्च किये हैं। राज्य मानव संसाधन विकास मंत्री सत्यपाल सिंह ने इन दोनों कार्यक्रमों को लॉन्च किया।

इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को उनके विषयों से संबंधित नई जानकारियों से अपडेट किया जाएगा। साथ ही लीडरशिप की प्रतिभा भी विकसित की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तैयार किए गए इस प्रशिक्षण प्रोग्राम में विश्वविद्यालय के कुलपतियों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशक और शिक्षकों को शामिल किया गया है। मौजूदा समय में देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में करीब 15 लाख शिक्षक पढ़ा रहे है।

लाभ

योजना के तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण कोर्स की गणना उनकी पदोन्नति के दौरान की जाएगी अर्थात ऐसे शिक्षकों को पदोन्नति में वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण में नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए भी एक इंडक्शन कोर्स डिजाइन किया है, जिसके तहत भर्ती होने वाले नए शिक्षकों को नियुक्ति के दौरान ही एक महीने का इंडक्शन कोर्स करना होगा।

इंसानी दिमाग जैसे दुनिया के सबसे बड़े कम्प्यूटर ने काम शुरू किया, एक सेकंड में मानेगा 20 हजार करोड़ से ज्यादा कमांड

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इंसानी दिमाग की तरह काम करने के लिए बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े और पहले सुपर कम्प्यूटर ने रविवार को काम करना शुरू कर दिया है । ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए इस सुपर कम्प्यूटर को बनाने में 141.38 करोड़ रुपए की लागत आई है । 2006 में इसे बनाना शुरू किया गया था । यह कंप्यूटर सिर्फ एक सेकंड में 20 हजार करोड़ से ज्यादा कमांड एक बार में कर सकता है। इसके प्रोसेसर में लगी चिप्स में 100 अरब ट्रांजिस्टर हैं। इस कंप्यूटर के जरिए वैज्ञानिकों को न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियों की पहचान और उसके इलाज में मदद मिलेगी ।

12 साल की मेहनत के बाद बना सुपर कम्प्यूटर

- सुपर कंप्यूटर की इस मशीन को 'स्पिननेकर' नाम दिया गया है । इस प्रोजेक्ट के मुखिया स्टीव फरबेर का कहना है कि यह मशीन दुनिया की अब तक की सबसे तेज और नियत समय में सबसे अधिक बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स की नकल कर सकती है।
- उन्होंने बताया कि कम्प्यूटर में बहुत सी ऐसी चीजें करने में मुश्किल होती है, जो इंसान स्वाभाविक रूप से कर लेते हैं। नवजात शिशु भी अपनी मां को पहचान लेते हैं लेकिन किसी खास व्यक्ति को पहचानने वाला कम्प्यूटर बनाने का काम हमने संभव कर दिखाया।
- उन्होंने कहा कि अब हम दिमागी क्रिया को आसानी से पहचान सकते हैं। मैं अब यह कह सकता हूं कि हम 12 सालों की मेहनत और कोशिशों में कामयाब रहे हैं और हमारा उद्देश्य पूरी तरह सफल रहा।
- इस परियोजना से जुड़े प्रोफेसर हेनरी मार्कराम कहते हैं कि इंसान का दिमाग इतना खास क्यों होता है? ज्ञान और व्यवहार के पीछे का मूल ढांचा क्या है? दिमागी बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए सुपर कम्प्यूटर के जरिए हम अब इन सभी उपायों का आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं ।

श्रीलंका के विदेश मंत्री बोले- भारत है हमारा असली दोस्त, चीन नहीं

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

श्रीलंका के विदेश मंत्री ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है जिसमें चीन के साथ बेहतर होते उसके रिश्ते को लेकर आशंकाएं जताई गई हैं । यह भी कहा जा रहा है कि श्रीलंका और चीन की दोस्ती भारत के रणनीतिक और सामरिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है । ऐसी मीडिया रिपोर्ट आई हैं जिसमें कहा गया है कि चीनी पनडुब्बी श्रीलंका के हंबनटोटा पोर्ट पर डेरा डालेंगी जिससे भारत की सुरक्षा पर खतरे के बादल मंडरा सकते हैं ।

विदेश मंत्री सरत अमूनगामा ने 'इंडिया टुडे' से खास बातचीत में कहा कि श्रीलंका के लिए भारत हमेशा 'पहली प्राथमिकता' बना रहेगा । उन्होंने स्पष्ट किया कि 'श्रीलंका किसी अन्य देश के सैन्य और रणनीतिक हितों के लिए खुद को घसीटा जाना पसंद नहीं करता' और श्रीलंका हर हाल में अपनी 'संप्रुभता की रक्षा' करेगा ।

अमूनगामा ने हंबनटोटा पोर्ट के बारे में भी बात की जिसे एक चीनी कंपनी को ठेके पर दिया गया है. उन्होंने इसे पूरी तरह से श्रीलंका का मामला बताया न कि चीन का । अमूनगामा ने कहा, 'यहां (हंबनटोटा) कोई चीनी पनडुब्बी खड़ी नहीं होगी...हम चीन से लोन लेते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसका रणनीतिक हित साधने का जरिया बनेंगे ।'

तालिबान के साथ पहली बार बातचीत की मेज पर भारत, उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि भारत की सतत नीति यह रही है कि इस तरह के प्रयास अफगान–नेतृत्व में, अफगान–स्वामित्व वाले और अफगान–नियंत्रित तथा अफगानिस्तान सरकार की भागीदारी के साथ होने चाहिए। अफगानिस्तान में शांति बहाली की कोशिशों के तहत भारत शुक्रवार को पहली बार आतंकी संगठन तालिबान के साथ बातचीत की मेज पर बैठा। तीन दशकों से युद्ध और आतंक का दंश झेल रहे अफगानिस्तान के भविष्य के लिहाज से ये बहुपक्षीय बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। इस बैठक में तालिबान के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

भारत की गैर आधिकारिक एंट्री

रूस में हो रही इस बैठक में अफगानिस्तान में शांति और स्थायित्व के मुद्दे पर भारत चर्चा की । भारत ने कहा कि वह अफगानिस्तान पर रूस द्वारा आयोजित की जा रही बैठक में 'गैर–आधिकारिक स्तर' पर भाग लेगा । अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके अमर सिन्हा और पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त टीसीए राघवन इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ।

जम्मू-कश्मीर में भी ऐसी ही बातचीत क्यों नहीं?

इधर भारत सरकार की इन कोशिशों पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने तंज कसा है । उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यदि मोदी सरकार को बातचीत की मेज पर तालिबान कबूल है तो जम्मू कश्मीर में केंद्र मुख्यधारा से इतर दूसरे तत्वों से बात क्यों नहीं कर सकती है ।

उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, 'ऐसी बैठक जहां की तालिबान भागीदारी है, इसमें मोदी सरकार को अपना गैर आधिकारिक प्रतिनिधित्व मंजूर है तो सरकार जम्मू–कश्मीर में भी मुख्यधारा से इतर काम कर रहे संगठनों से केन्द्र गैर आधिकारिक बात क्यों नहीं करती है।'

भारत की बड़ी जीत, ईरान से तेल खरीदने पर अमेरिका नहीं लगाएगा रोक

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

अमेरिका और ईरान के बीच चली आ रही तल्खी का असर भारत समेत दूसरे तेल आयातक देशों पर क्या होगा, इसे लेकर ट्रंप प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि ईरान पर जारी यूएस के प्रतिबंध सख्ती से लागू रहेंगे। लेकिन भारत समेत आठ देशों को ईरान से तेल खरीदने की छूट दी गई है। हालांकि, यह मोहलत अस्थायी है।

अस्थायी है छूट

पोम्पियो ने सोमवार को कहा, 'हमने खास परिस्थितियों को देखते हुए तथा बाजार में पर्याप्त मात्रा में तेल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुछ गिने–चुने देशों को ईरान से तेल आयात की छूट अस्थायी रूप देने का फैसला किया है। अमेरिका यह छूट चीन, भारत, इटली, यूनान, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और तुर्की को देगा।'

इसके साथ ही उन्होंने संकल्प जताया कि ईरान पर दबाव बनाने के लिये अमेरिका हर संभव प्रयास करता रहेगा. उन्होंने कहा कि इन देशों ने पहले ही महीने से ईरान से कच्चे तेल की खरीद पहले ही काफी कम कर दी है। दरअसल, ईरान के खिलाफ आज (सोमवार) से अमेरिका के अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लागू हो गए हैं । अमेरिका ने ईरान के बैंकिंग और पेट्रोलियम क्षेत्र पर यह पाबंदी लागू की है, जिसके तहत ईरान से तेल खरीदने वाले यूरोप, एशिया तथा अन्य सभी देशों और कंपनियों पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का प्रावधान है ।

भारत बड़ा आयातक

भारत और चीन, ईरान से कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं । पोम्पियो ने कहा कि इन आठ में से दो देश पहले ही ईरान से कच्चे तेल का आयात शून्य पर ले आए हैं और जब तक पाबंदी रहेगी, वे आयात शुरू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, 'हम सभी देशों से आयात शून्य स्तर पर लाने को लेकर बातचीत जारी रखेंगे।'

गला घोंटकर की गई खशोगी की हत्या, शरीर के किए कई टुकड़े

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इस्तांबुल स्थित सऊदी अरब के दूतावास में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का मामला दिन–ब–दिन उलझता ही जा रहा है। तुर्की के एक शीर्ष अभियोजक ने बुधवार को कहा कि दूतावास में खशोगी के प्रवेश करने के साथ ही गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, उनके शव को ठिकाने लगाने से पहले शरीर के टुकड़े–टुकड़े किए गए थे। उन्होंने कहा कि यह सब सुनियोजित तरीके से किया गया।

इस्तांबुल के प्रमुख अभियोजक इरफान फिदान के कार्यालय की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया कि सच का खुलासा करने के तुर्की के भरसक प्रयासों के बावजूद सऊदी अरब के प्रमुख अभियोजक अल–मोजेब के साथ चर्चा में कोई ठोस परिणाम नहीं निकले ।

यह बयान किसी तुर्की अधिकारी द्वारा की गई पहली सार्वजनिक पुष्टि है कि खशोगी को गला घोंटकर मारा गया था और उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे।

यह घोषणा सऊदी अरब के मुख्य अभियोजक सऊद अल–मोजेब का इस्तांबुल का तीन दिवसीय दौरा खत्म होने के बाद की गई. अपने इस दौरे के दौरान मोजेब ने फिदान और अन्य तुर्की अधिकारियों के साथ बातचीत की ।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

द रीव टाइम्स संस्थापकः डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक श्री प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस सायबू निवास समीप सेक्टर -2, बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित प्रधान सम्पादकः डा. एल.सी. शर्मा, प्रबन्ध सम्पादकः आनन्द नायर फोन न. 0177 2640761, मेलः editor@themissionriev.com
RNI Reference No. 1328500

सामान्य ज्ञान

1. तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है।
– मुस्तफा कमालपाशा

2. रेड इंडियन कहां के निवासी थे ।
– अमेरिका

3. किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई ।
– शारदा एक्ट (1930)

4. राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की ।
– अकबर द्वितीय

5. मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधी किसने प्रदान की।
– महात्मा गांधी

6. कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है।
– उत्तराखंड

7. महलों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है ।
– कोलकाता

8. गंगासागर परियोजना किस नदी पर स्थित है।
– चंबल (मध्यप्रदेश)

9. अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर है।
– नेपानगर (मध्य प्रदेश)

10. भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहां पर खोला गया ।
– ट्रंकवार में (1716)

11. किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है।
– राष्ट्रपति

12. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है ।
– लोक सभा

13. किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी ।
– वी.वी. गिरि

14. संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है ।
– अनुच्छेद 75

15. राज्य सभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष है ।
– 30 वर्ष

16. वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित है।
– 98

17. वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं।
– 62

18. वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं।
– 52

19. रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया।
– सरदार बल्लभ भाई पटेल

20. दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया है ।
– संविधान के 69वें संशोधन में

21. रैक्सिन (रेग्जिन) कृत्रिम चमड़ा किस वनस्पती पदार्थ से बनाया जाता है।
– सेल्यूलोज

22. भारी जल का अणुभार कितना होता है ।
– अणुभार 20

23. ट्युबलाइट में होती है।
– पारे की वाष्प

24. देश का पहला भारी जल का संयत्र कहां पर स्थापित किया गया।
– नंगल (पंजाब)

25. राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गो की सर्वाधिक लंबाई की दृष्टी से जिला है ।
– जोधपुर

26. विश्व का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है (भारतीय) ।
– तेजस

27. राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी थी ।
– दी कृष्णा मिल ब्यावर

28. राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है ।
– एनएच 3

29. विश्व की पहली रेल सेवा किस देश में शुरू हुई ।
– इंग्लैंड(1826)

30. राजस्थान में प्रथम रेल कब व कहां चलाई गई।
– 1974 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई(भरतपुर)

31. नैनो सैकंड का मान कितना होता है ।
– 10'9

32. राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग किस जिले से निकलते हैं।
– अजमेर (पांच)

33. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई।
– 25 दिसंबर 2000

34. राजकीय बस सेवा प्रारंभ करने वाला राजस्थान का पहला जिला है ।
– टोंक (1952)

35. भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहां पर है ।
– उदयपुर

36. शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है ।
– अस्थि मज्जा

37. हिमोफिलिया,मांगोलिज्म, वर्णाधता किस प्रकार के रोग हैं ।
– आनुवंशिक रोग

38. पक्षियों एवं उनके स्वभाव का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं ।
– आरनिथोलॉजी

39. मानव जाति का अध्ययन करने को कहते हैं ।
– एंथ्रोपोलॉजी

40. छिपकलियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है।
– सौरालॉजी

खेल-खेल में

हरमनप्रीत कौर टी-20 के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हरमनप्रीत कौर ने 09 नवम्बर 2018 को तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी–20 मैच में केवल 49 गेंदों में शतक बना डाला। हरमनप्रीत कौर ने अपनी शतकीय पारी में 8 छक्के और 7 चौके लगाए। उन्होंने 76 रन सिर्फ बाउंड्री से हासिल कर लिए। अपनी शतकीय पारी के साथ ही उन्होंने कई रिकॉर्ड्स को तोड़ा तथा नये रिकॉर्ड्स भी बनाए। कप्तान हरमनप्रीत ने पहले 50 रन 33 गेंदों में और अगले 50 रन मात्र 16 गेंदों में ही बना डाले थे।

बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम वर्ग में नंबर एक पहलवान बने

द रीव टाइम्स

भारत के प्रसिद्ध पहलवान बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष विश्व रैंकिंग हासिल की। इस सत्र में 5 पदक जीतने वाले 24 वर्षीय बजरंग पूनिया यूडब्ल्यूडब्ल्यू की सूची में 96 अंकों के साथ रैंकिंग तालिका में शीर्ष पर हैं।

इस वर्ष बजरंग पूनिया ने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर पदक हासिल किया था। बजरंग पूनिया का प्रदर्शन इस वर्ष सराहनीय रहा। वह बुडापेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में वरीयता पाने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान रहे।

बजरंग ने दूसरे स्थान पर मौजूद क्यूबा के एलेजांद्रो एनरिक व्लाडेस टोबियर पर मजबूत बढ़त बना रखी है जिनके 66 अंक हैं। बजरंग ने विश्व चैंपियनशिप के करीबी सेमीफाइनल में टोबियर को हराया था।

वन डे में सबसे तेज छक्के लगाने वाले खिलाड़ी रोहित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रोहित शर्मा 01 नवम्बर 2018 को तिरुवनंतपुरम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पांचवें मैच के दौरान वनडे इतिहास में सबसे तेज़ 200 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। रोहित शर्मा ने विंडीज के खिलाफ पांचवें और अंतिम वनडे में अपनी नाबाद 63 रन की पारी में चार छक्के लगाने के दौरान यह उपलब्धि हासिल की।

हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करते हुए जैसे ही दूसरा छक्का जड़ा वह एकदिवसीय क्रिकेट में छक्कों का दोहरा शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए।

सबसे कम पारियों में 200 छक्के

रोहित शर्मा ने सबसे कम पारियों में 200 छक्के जड़ने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने 193वें वनडे की 187वीं पारी में ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के बल्लेबाज शाहिद अफरीदी के नाम दर्ज था। अफरीदी ने 195 पारियों में छक्कों का दोहरा शतक पूरा किया था।

पंकज आडवाणी एशियन स्नूकर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पंकज आडवाणी एशियन स्नूकर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए है। पंकज आडवाणी ने यह उपलब्धि 31 अक्टूबर 2018 को चीन में आयोजित एशियन स्नूकर टूर के सेकेंड लेग में चीनी खिलाड़ी जु रेती को 6–1 हराकर हासिल की।

पद्म भूषण से सम्मानित पंकज आडवाणी ने मार्च 2018 में एशियन बिलियड्र्स चैंपियनशिप का खिताब जीता था। इस खिताब के जीतने के साथ ही पंकज ने होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है।

पंकज आडवाणी का जन्म 24 जुलाई 1985 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। पंकज आडवाणी स्नूकर और बिलियड्र्स के विश्व विजेता हैं। पंकज ने पहला पेशेवर बिलियड्र्स विश्व खिताब वर्ष 2001 में जीता था। इससे पहले वे एमेच्योर विश्व बिलियड्र्स और स्नूकर चैंपियनशिप जीत चुके थे। पकंज आडवाणी को 'राजीव गांधी खेल रत्न' पुरस्कार (2006) प्रदान किया गया।

यूनिसेफ द्वारा भारतीय एथलीट हिमा दास को युवा एंबेसडर बनाया गया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत की प्रसिद्ध धाविका तथा एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता हिमा दास 15 नवम्बर 2018 को यूनिसेफ इंडिया की युवा एंबेसडर बनाई गईं। हिमा बच्चों के अधिकारों और आवश्यकताओं के बारे में जागरुकता बढ़ाने, बच्चों और युवाओं की आवाज को बुलंद करने में हिस्सा लेंगी। हिमा दास उस समय प्रसिद्ध हुईं जब उन्होंने जुलाई 2018 में फिनलैंड में आयोजित आईएएफ वर्ल्ड अंडर–20 चैम्पियनशिप की महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने फाइनल में 51.46 सेकेंड का समय निकालते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया था।

हाल ही में संपन्न हुए जकार्ता एशियाई खेलों में भी हिमा दास ने चार गुणा 400 मीटर रिले स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले वह अप्रैल में गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों की 400 मीटर स्पर्धा में तत्कालीन भारतीय अंडर 20 रिकॉर्ड 51.32 सेकेंड के समय के साथ छठे स्थान पर रही थीं। हिमा दास वर्ष 2020 टोक्यों में होने वाले इंटरनेशनल एथलीटिक्स मीट में देश के लिए मेडल हासिल करने की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं।

भारत के आईटी सेक्टर में 2027 तक 14 लाख नई नौकरियां होंगी: रिपोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल विशेषज्ञों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए एक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 2027 तक इस क्षेत्र में देश में 14 लाख नई नौकरियों की संभावनाएं बनेंगी। देश में साइबर सिक्यॉरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा जैसे स्पेशल फील्ड्स में 2027 तक 14 लाख नौकरियां उत्पन्न होंगी। सिस्को द्वारा कराये गये अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है।

वर्तमान समय में कम्पनियां आईटी में दक्ष एवं कुशल युवाओं को तलाश रही है। ग्लोबल नेटवर्किंग पर नजर रखने वाली संस्था सिस्को ने इंटरनेशनल डाटा कारपोरेशन के साथ मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है। इस अध्ययन में पाया गया है कि आने वाले सालों में भारत में सोशल मीडिया एडमिनेस्ट्रेटर, मशीन लर्निंग डिजायनर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिजायइनर की नौकरियां सबसे ज्यादा मांग में होंगी। स्टडी में बताया गया है कि लगभग 89 फीसदी रिपोर्टिंग मैनेजर अपने योग्य सबऑर्डिनेट्स पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। साइबर सिक्यॉरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा जैसे स्पेशल फील्ड्स में 2027 तक 14 लाख नौकरियां होंगी। सिस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आईटी सेक्टर और की जॉब्स में 46 फीसदी की ग्रोथ देखने को मिलेगी। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब भी सीटें खाली पड़ी हैं। इस क्षेत्र में 1.4 लाख नौकरियां, बिग डेटा ऐनालिटिक्सम सेगमेंट की भी जरूरत है। बिग डेटा ऐनालिटिक्स सेगमेंट में भी देश के बड़े संस्थानों को अच्छे दक्ष युवाओं की तलाश है। इस तरह कुल मिलाकर 5.1 लाख नौकरियों की जगह है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इनमें 2021 तक 3.7 लाख नौकरियां भर जाएंगी।

बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का नया कार्यक्रम

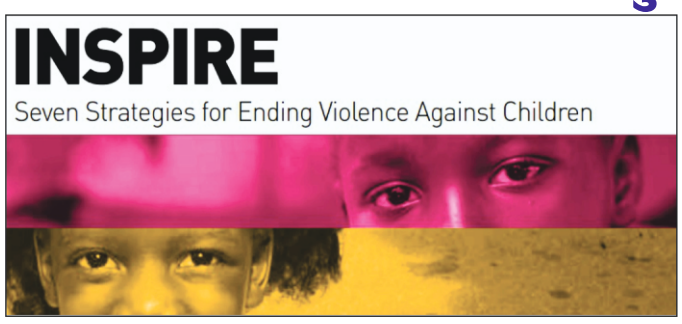

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपात राहत कोष परिषद (यूनिसेफ) ने विश्व में बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसात्मक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सात सूत्रीय कार्यक्रम (सेवन स्ट्रेटिजीज फॉर एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन) इंस्पायर (INSPIRE) की शुरूआत पर सहमति जताई है।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 21 देशों के प्रतिनिधि इन दिनों यहां एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं जिसका उद्देश्य बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसात्मक घटनाओं पर रोक लगाने की दिशा में कदम उठाना है। यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर से एक नवंबर तक है। एक अनुमान के मुताबिक विश्व में कम से कम एक अरब बच्चे हर साल किसी न किसी रूप में हिंसा का सामना कर रहे हैं और एशिया में पिछले वर्ष 50 फीसदी बच्चों को हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ा था। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने वर्ष 2030 तक बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने की प्रतिबद्धता जताई है। यह सतत विकास के उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में एक प्राथमिकता तय की गई है। इसे हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की दस एजेंसियों ने मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर, 15 से 19 (84 मिलियन) आयु वर्ग की प्रत्येक तीसरी लड़की को अपने पति या साथी द्वारा भावनात्मक, शारीरिक अथवा यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता है।

यूनिसेफ के बारे में

यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसम्बर साल 1946 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा न्यूयार्क में की गई थी। यूनीसेफ विश्वभर में मौजूद स्वास्थ्य सेवा संस्थानों विशेषकर विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि के साथ मिलकर बच्चों को पानी, स्वच्छता, बीमारियों आदि से बचने के लिए कार्यक्रम चलाती है।

यूनिसेफ पूरे विश्व में मौजूद बच्चों के कल्याण हेतु कार्य करने के दौरान किसी भी तरह के जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचारधारा आदि आधारों पर भेदभाव नहीं करता. यूनिसेफ प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में नवजात बच्चों के टीकाकरण के लिए लगभग 3 बिलियन से अधिक टीके उपलब्ध कराता है।

सेशेल्स ने विश्व का पहला ब्लू बॉण्ड जारी किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सेशेल्स ने विश्व का पहला ब्लू बॉण्ड जारी किया है, जिसका उद्देश्य सामुद्रिक एवं मत्स्य पालन परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस बॉण्ड के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों द्वारा 15 मिलियन डॉलर भी दिए गये हैं।

इस बॉण्ड के माध्यम से कोई भी देश सामुद्रिक संसाधनों के सतत् उपयोग के लिये वित्त हेतु किसी भी प्रकार के पूंजी बाज़ार से धनराशि एकत्र कर सकता है। इसके अंतर्गत, ब्लू ग्रांट्स निधि के ज़रिये अनुदान भी दिया जाएगा। इस निधि का प्रबंधन सेशेल्स के संरक्षण एवं जलवायु अनुकूलन न्यास द्वारा किया जाएगा।

सेशेल्स के बारे में

सेशेल्स गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपसमूह राष्ट्र है। यह अफ्रीकी मुख्यभूमि से पूर्व दिशा में और मेडागास्कर के, उत्तर–पूर्व में स्थित है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स का अजंपशन आइलैंड भारत के लिए सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत यहाँ अपना सैन्य बेस बनाने का प्रयास कर रहा है।

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में भारत 77वें स्थान पर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विश्व बैंक की 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' रिपोर्ट में भारत ने 23 स्थानों की ज़बरदस्त छलांग लगाते हुए 77वां स्थान हासिल किया है। विश्व बैंक ने 31 अक्टूबर 2018 को वैश्विक कारोबार सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस) रिपोर्ट जारी की। भारत का यह रैंकिंग अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दस में से 8 मानकों में भारत की स्थिति सुधरी है।

दरअसल, पिछले वर्ष 190 देशों की सूची में भारत को पहली बार शीर्ष 100 में जगह मिली थी। पिछले 2 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रैंकिंग में सुधार करने वाले टॉप 10 देशों में भारत भी शामिल है। वहीं, दक्षिण एशियाई देशों में भारत की रैंक फर्स्ट है। इससे पहले साल 2014 में भारत 6वें स्थान पर था।

दुर्लभ उपलब्धि:

भारत द्वारा 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में लगाई गई 23 पायदानों की ऊंची छलांग निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में 30 पायदानों की जबर्दस्त छलांग लगाई थी जो भारत के आकार वाले किसी भी विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है।

पिछले कुछ सालों में भारत की रैंकिंग:

वर्ष	रैंकिंग
साल 2018	77वां रैंक
साल 2017	100वां रैंक
साल 2016	130वां रैंक
साल 2015	130वां रैंक
साल 2014	142वां रैंक

रैंकिंग कैसे तय होती है?

भारत ने वर्ष 2003 से अब तक 37 बड़े सुधार लागू किए हैं। इस रिपोर्ट में वर्ष 2017 में दिल्ली और मुंबई को शामिल किया गया था। रिपोर्ट में किसी कारोबार को शुरू करना, कंस्ट्रक्शन परमिट, क्रेडिट मिलना, छोटे निवेशकों की सुरक्षा, टैक्स देना, विदेशों में ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट लागू करना और दिवालिया शोधन प्रक्रिया को आधार बनाया जाता है।

छह वर्षों में भारत में कैंसर के मामलों में 15.7 फीसदी वृद्धि: रिर्पोट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी (ग्लोबोकेन) द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले छह वर्षों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। यह आंकड़े वर्ष 2012 से 2018 तक के हैं। इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में लगभग 11.57 लाख कैंसर के मामलें दर्ज किये गए, जो कि वर्ष 2012 में दर्ज 10 लाख मामलों की तुलना में 15.7 प्रतिशत अधिक हैं। रिपार्ट के मुताबिक वर्ष 2012 में कैंसर के कारण सात लाख लोगों की मौत हुई थी जबकि वर्ष 2018 में कैंसर के कारण होने वाली मौतों की संख्या में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्ष 2012 की तुलना में अब तक 114.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2018 में 1.62 लाख स्तन कैंसर के मामले सामने आए जो कि वर्ष 2012 की तुलना में10.7 प्रतिशत अधिक हैं। वर्ष 2012 के 1.45 लाख मामले सामने आये थे। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के मामलों की संख्या में 21.2 प्रतिशत की गिरावट आई है। वर्ष 2018 में मात्र 96,922 मामले ही सामने आए जबकि वर्ष 2012 में 1.23 लाख गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के मामले दर्ज किये गए थे।

शिक्षा लोन योजना : ऑनलाइन आवेदन एवं एप्लीकेशन फार्म... जाने पूरी प्रक्रिया

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

ऐजुकेशन लोन योजना - अधिकतर देखा जाता रहा है की कई प्रतिभाशाली छात्र पैसे न होने के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते है देश में इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने देश में एजुकेशन लोन योजना को शुरू करने का एलान किया था । इस योजना के अंतर्गत, अब कोई भी छात्र जो पढ़ना चाहता है परन्तु वह पैसों की कमी के कारण नहीं पढ़ पाता है अब वह छात्र भी अपनी शिक्षा के लिए लोन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है । आज हम आपको अपने इस लेख में विस्तार से बताएंगे की कैसे आप इस अपनी एजुकेशन के लिए लोन ले सकते है । इसके लिए आपको कही जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योकि आप इस योजना के अंतर्गत, अगर लोन लेना चाहते है इसके लिए घर बैठे–बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते है ।

एजुकेशन लोन योजना

यदि आप इस योजना के अंतर्गत, भारत में पढ़ाई करने के लिए लोन लेना चाहते है तो आपको इसमें 10 लाख रूपये तक का लोन प्राप्त कर सकता है इसके साथ ही अगर कोई छात्र विदेश में रहकर अपनी पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए इस योजना के अंतर्गत, 20 लाख रूपये की धनराशि का लोन दिया जाएगा । जिससे वह अपनी शिक्षा सम्पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है ।

डिजिटल सेवा पोर्टल ऑनलाइन पंजीकरण

ज़रुरी पात्रता व एजुकेशन लोन योजना

यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो आपका भारत का निवासी होना अनिवार्य है तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते है ।

इसके साथ ही आपकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच की होनी चाहिए।

इसके अलावा, आप केवल मान्यता प्राप्त वेबसाइट से ही इस योजना के लिए आवेदन करके लोन प्राप्त कर सकते है।

इस योजना के लिए आवेदन करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा की पहले आपका किसी भी बैंक में पैसा बकाया न हो ।

दो पासपोर्ट साइज फोटो
उम्मीदवार–माता–पिता–अभिभावक तथा गारंटर (जो भी लागू हो) का पहचान पत्र (आईडी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड) पासपोर्ट अथवा बिजली या टेलीफोन बिल की फोटो कॉपी गारंटर से जुड़े विवरण (जब ऋण की राशि 4 लाख रुपये से अधिक हो)
ऋणकर्ता–गारंटर की आय का प्रमाण पत्र
आवेदन पत्र
उत्तीर्ण परीक्षा मार्कशीट
प्रवेश प्रमाणपत्र
व्यय के विवरण तथा कोर्स की अवधि
कॉलेज–विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रमाण–पत्र
कहाँ से प्राप्त करें लोन

निम्नलिखित बैंक इस योजना के अंतर्गत आपको लोन देते है जैसे की

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया : www.statebankofindia.com
इलाहाबाद बैंक : www.allahabadbank.com
पंजाब नेशनल बैंक : www.pnbindia.in
बैंक ऑफ इंडिया : www.bankofindia.com
केनरा बैंक : www.canarabank.com
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया : www.centralbankofindia.co.in
एचडीएफसी बैंक : www.hdfcbank.com
जम्मू–कश्मीर बैंक : www.jkbank.net
ऐक्सिस बैंक : www.axisbank.com
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला :www.sbp.co.in

कैसे मिलता है बैंक से लोन

बैंक एजुकेशन लोन देने से पहले उसकी रिपेमेंट सुनिश्चित करता है। आमतौर पर लोन उसे ही दिया जाता है, जो इसे वापस करने की क्षमता रखता है । रिपेमेंट लोन लेने वाले स्टूडेंट के अभिभावक कर सकते हैं या फिर लोन लेने वाला स्वयं पढ़ाई खत्म करने के बाद रिपेमेंट कर सकता है । लोन लेने के लिए गारंटर की जरूरत पड़ती है । गारंटर लोन लेने वाले का अभिभावक या फिर रिश्तेदार हो सकते हैं।

एजुकेशन लोन का दायरा

बैंक किसी भी कोर्स के लिए होने वाले खर्चों की पूर्ति करने के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराता है । एजुकेशन लोन के दायरे में देश और विदेश में पढ़ाए जाने वाले कोर्स शामिल होते हैं । आप चाहें, तो किसी के लिए भी बैंक से लोन ले सकते हैं । भारत में बारहवीं की स्कूली शिक्षा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पी.एच.डी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, लॉ, डेंटल, मैनेजमेंट, कम्प्यूटर, मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थानों के कम्प्यूटर कोर्स, आईसीडब्ल्यू, सीए आदि जैसे कोर्सों के लिए एजुकेशन लोन ले सकते हैं । यदि आप विदेश में पढ़ाई की चाहत रखते हैं, तो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमसीए, एमबीए, एमएस आदि के लिए भी एजुकेशन लोन बैंक से हासिल कर सकते हैं ।

किसके लिए मिल सकता है लोन

स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल की फीस, परीक्षा, लाइब्रेरी और लेबोरेटी की फीस, किताबें, इक्विपमेट, इंस्ट्रूमेंटस, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए,विदेश में पढ़ाई के लिए यात्रा खर्च, रास्ते का खर्च, स्टडी टूर, प्रोजेक्ट वर्क, थीसिस इत्यादि।

लोन लेने से पहले ध्यान दें

मंदी के कारण आजकल मार्केट की स्थिति काफी बेहतर नहीं है। ऐसे में जान लें कि आप जो लोन लेने जा रहे हैं। उसकी रिपेमेंट सही समय पर हो जाए। इसलिए लोन उतना लिया जाए, जितना आप उठा सकें। नौकरी लगने के बाद रिपेमेंट के ऑपशन पर विचार करने से पहले सभी विकल्पों और अच्छी–बूरी सभी प्रकार की संभावनाओं पर पूरी तरह विचार कर लिया जाना चाहिए । बेशक बाजार की मांग और आपूर्ति का इस सेक्टर पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता, लेकिन फ्लोटिंग रेट का असर जरूर पड़ता है । विशेषकर लम्बी अवधि के लोन फ्लोटिंग रेट से प्रभावित होते हैं।

लोन चुकाने के अवसर

बैंक अन्य लोन की तरह ही एजुकेशन लोन पर भी ब्याज वसूलता है, लेकिन यह वसूली करने के लिए उसके पास मुख्य रूप से तीन विकल्प हैं । इनमें एक आकर्षक जरिया है मोरेटोरियम पीरियड जिसे रिपेमेंट हॉलीडे भी कहा जाता है । इसमें विकल्प होता है कि लोन लेने वाला इसकी रिपेमेंट जिस कोर्स में एडमिशन लिया गया है, उसकी समाप्ति के बाद कर सकता है।

एजुकेशन लोन आसानी से स्वीकृत कराने के लिए किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए?

स्टूडेंट को चाहिए कि वे लोन से संबंधित जो विवरण और दस्तावेज दे रहे हैं, वे पूरी तरह सही हों और बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप हों । साथ ही, कोर्स के दौरान कितना खर्च आ सकता है, उसका भी विवरण देना चाहिए।

एजुकेशन लोन के रिपेमेंट की प्रक्रिया क्या है?

कोर्स के दौरान पहले साल उपयोग किए गए लोन का सिम्पल इंटरेस्ट ही अदा करना होता है । लेकिन कोर्स खत्म होने के बाद रिपेमेंट की प्रक्रिया शुरू होने के पांच वर्षो में पूरा पेमेंट करना होता है ।

शिक्षा लोन के ये पांच फायदे आपको हर हाल में मालूम होने चाहिए

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

शिक्षा पर लगने वाला खर्च हर साल महंगा होता जा रहा है । बच्चों की पढ़ाई के लिए माता–पिता पैसे की जुगाड़ में सोने में या फिक्स्ड एसेट में निवेश करते हैं । हालांकि, कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर का कहना है कि बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए माता–पिता एजुकेशन लोन ले सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए बैंक या एनबीएफसी (गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी) से एजुकेशन लोन मिलता है ।

ज्यादा बचत: ऐजुकेशन लोन लेने के बाद आप बिना किसी व्यवधान के अपनी कमाई में से बचत को जारी रख सकते हैं, जिससे आगे आपकी किसी भी वित्त जरूरतों की पूर्ति हो सकती है । आप चाहें तो बच्चों की शादी, घर खरीदने में अपनी बचत का इस्तेमाल कर सकते हैं । इससे यह होगा कि आप रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहेंगे।

कवरेज: ऐजुकेशन लोन से न केवल आप अपनी कोर्स का फीस भर पाएंगे बल्कि, यह आपके अन्य खर्चे जैसे– हॉस्टल खर्च, परीक्षा फीस, लाइब्रेरी चार्ज, लैब फीस में भी काम आएगा । लोन का इस्तेमाल आप किताब का खर्च, यात्रा व्यय आदि में भी कर सकते हैं ।

टैक्स में फायदा: आयकर अधिनियम की धारा 80 ई के तहत, एजुकेशन लोन पर भुगतान की जाने वाली पूरी राशि ब्याज आयकर कटौती के लिए मान्य है। आयकर कटौती का दावा आठ साल तक किया जा सकता है ।

मोरेटोरियम पीरियड: मोरेटोरियम पीरियड लोन टाइम के समय उधारकर्ता को दी गई अवकाश अवधि की तरह है । इस अवधि में उधारकर्ता को लोन चुकाने से छूट मिलती है । ऐजुकेशन लोन के मामले में, उधारकर्ता को कोर्स पूरा होने की तारीख से 6 महीने से 1 वर्ष तक के लिए छूट मिलती है, इससे लोन लेने वाले को अच्छी नौकरी तलाशने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है

क्रेडिट की जानकारी: अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है और उसका पुनर्भुगतान समय पर करते हैं तो इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रहेगी और आगे भी आपको लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

ये भी जाने ऐजुकेशन लोन के रूप में आपको ऐसी परिस्थितियों में काफी मदद मिलती है। यह लोन आपकी जरूरत और उपलब्ध रकम के बीच की खाई को भरता है एक अध्ययन के अनुसार पढ़ाई का खर्च सालाना 15 फीसदी की दर से बढ़ रहा है । इस समय अगर पढ़ाई का खर्च 2.5 लाख रुपये है तो 15 साल बाद एमबीए करने में 20 लाख रुपये खर्च होंगे ।

अगर कोई पैरेंट अभी से 15 सालों तक हर महीने 2000 रुपये का निवेश करता है और इस पर औसत रिटर्न 12 फीसदी मान लें तो वह करीब 9.5 लाख रुपये ही जोड़ पायेगा ।

एजुकेशन लोन में क्या कवर होता है?

इसमें कोर्स की बेसिक फीस और कॉलेज के दूसरे खर्च (रहने, एग्जाम और अन्य) कवर होते हैं । लोन के लिए कौन अप्लाय कर सकता है? पढ़ाई करने वाला छात्र मेन बॉरोअर होता है । उसके पैरेंट्स, या भाई–बहन को बॉरोअर हो सकते हैं ।

लोन किसे मिल सकता है?

भारत में पढ़ाई या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्र लोन ले सकते हैं। दोनों जगह पढ़ाई के लिए लोन की रकम अलग हो सकती है और यह बैंक पर भी निर्भर करता है ।

लोन के तहत किस तरह के कोर्स आते हैं?

लोन लेकर फुल टाइम, पार्ट टाइम या वोकेशनल कोर्स किये जा सकते हैं । इसके अलावा इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, होटल मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर आदि में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए लोन लिया जा सकता है ।

प्रधानमंत्री आवास योजना

गांव और शहरों में किसे और कैसे मिल सकता है इस योजना का लाभ?

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

अगर आपके पास अपना खुद का घर नहीं है और आप अपना घर लेने की योजना बना रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। पहले जहां इस योजना का लाभ गरीब वर्ग के लिए था वहीं अब इस योजना में लोन की रकम बढ़ाकर शहरी गरीब और मध्यम वर्ग को भी दायरे में लाया गया है । पहले लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपए तक थी जिसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपए तक कर दिया गया है । लेकिन यहां एक बात बार–बार लोगों के दिमाग में आती है, वो ये कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन के लिए क्या जरूरी शर्तें हैं और क्या दस्तावेज जरूरी हैं, कई बार लोग योजना की शर्तों को नहीं समझ पाते हैं और वह इस बेहद लाभकारी योजना से वंचित रह जाते हैं, तो यहां द रीव टाइम्स आपको बताएगा कि इस योजना के लिए सरकार ने कौन–कौन सी श्रेणी बनाई है, किस आय वर्ग के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं, सरकार इस योजना के लिए किसे कितनी सब्सिडी दे रही है और कौन से लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आय वर्ग क्या है?

अगर आप पीएम आवास योजना के अंतर्गत घर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि आप किस आय वर्ग में आते हैं। अगर आप 3 से 6 लाख रुपए तक के आय वर्ग में आते हैं तो आपको ब्याज पर ज्यादा सब्सिडी मिलेगी, वहीं 6 से 12 लाख रुपए और 12 से 18 लाख रुपए सालाना आय वर्ग के लोगों का सब्सिडी कम होगी। 1 जनवरी 2017 से इस योजना के लाभ का दायरा बढ़ा दिया गया हैं। मिडिल क्लास के लिए दो श्रेणी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए मध्यम वर्ग (डप्ळ) के लिए दो श्रेणी बनाई गई है । इसमें 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक की पहली श्रेणी है जबकि दूसरी श्रेणी 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए की है। अब बताते हैं कि 6 से 18 लाख सालाना आय वर्ग के लोग कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और क्या है इस योजना की शर्तें ।

क्या हैं शर्तें

पीएम आवास योजना का उद्देश्य है कि सभी को पक्का मकान मिले। हां इस योजना की कुछ शर्तें जरूर हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है । सबसे पहले तो ऐसे लोग जिनके पास पहले से घर है वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है । प्रधानमंत्री आवास योजना का नियम है कि लाभ उसे ही मिलेगा जिसके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होगा ।

दूसरी शर्त

इस योजना की दूसरी शर्त है कि परिवार के किसी सदस्य को भारत सरकार की किसी योजना के तहत आवास योजना का लाभ ना मिला हो । यदि परिवार में किसी सदस्य को सरकारी योजना के तहत आवास का लाभ मिला है उसके किसी अन्य सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है ।

तीसरी शर्त

इस योजना के लिए आवेदन के वक्त अविभाजित परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड का नंबर देना जरूरी है। इसमें पति–पत्नी, और अविवाहित बेटे और बेटी शामिल हैं। शादी के बाद बेटा या बेटी इस योजना के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं।

ज़रुरी निर्देश

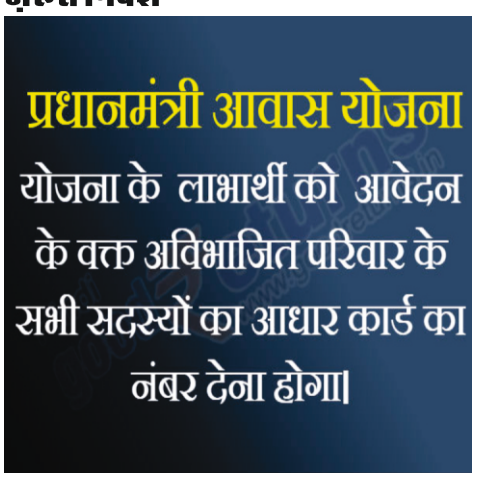

पक्के घर का लाभ उठाने वाले माता–पिता के विवाहित बेटे–बेटियां तो वैसे भी अलग परिवार माने जाते हैं । हालांकि, पति–पत्नी दोनों च्ड।ल का लाभ नहीं ले सकते। यानी, बेटे–बहू या बेटी–दामाद के नाम पर हर हाल में एक ही मकान पर सब्सिडी मिल सकती है । यह उनकी मर्जी होगी कि मकान का मालिकाना हक कोई एक अपने पास रखें या दोनों साथ–साथ ।

अब आपको बताऐंगे कि कितनी ब्याज पर कितनी सब्सिडी देगी सरकार ?

12 लाख प्रति वर्ष आय वर्ग के लोगों के लिए इसी तरह 12 लाख प्रतिवर्ष की आय वाले लोगों को 9 लाख रुपए तक लोन मिलेगा जिसमें ब्याज दर पर 4 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी इसमें मासिक ईएमआई पर 2,158 रुपए की बचत होगी जो कि 20 वर्ष की अवधि में 2 लाख 39 हजार 843 रुपए तक होगी। 12 से 18 लाख आय वर्ग यदि आपकी सालाना आय 12 से 18 लाख रुपए के बीच है तो आपको 12 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज दरों में 3 फीसदी की छूट मिलेगी। ये 110 स्क्वायर मीटर में हो रहे घर के निर्माण को लेकर दिए गए लोन पर निर्भर करेगा। 12 लाख रुपए पर 3 फीसदी की सब्सिडी को 20 साल में चुकाना होगा जिसके ब्याज पर मिली कुल छूट 2.30 लाख रुपए होगी। इस तरह से देखा जाए तो सरकार आपके लोन के लिए 2.30 लाख रुपए देगी जो कि आज के वक्त में बड़ी बचत है।

6 लाख सालाना आय वर्ग के लोगों के लिए वहीं 6 लाख रुपए की वार्षिक आय वालों को 6 लाख रुपए तक का होम लोन मिल सकता है और ब्याज दर पर सरकार की तरफ से 6.5 फीसदी की सब्सिडी मिलती है। जिससे

मासिक EMI में 2,219 रुपए की बचत होती है, ये बचत 20 वर्ष की अवधि में 2 लाख 46 हजार 625 रुपए तक होती है ।

समझें ब्याज पर सब्सिडी का पूरा गणित

इसे ऐसे समझें मान लीजिए आपकी वार्षिक आय 18 लाख रुपए है तो आपको 12 लाख रुपए तक लोन मिलेगा जिस लोन पर सरकार आपको ब्याज दर पर 3 फीसदी की सब्सिडि देगी। इससे प्रतिमाह

आपको 2,200 रुपए की बचत होगी जिसका 20 वर्ष में कुल 2 लाख 44 हजार 468 रुपए लाभ मिलेगा ।

5 साल और बढ़ी सीमा

अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपए है तो आपको पीएम आवास योजना पर 20 साल के होम लोन पर 2.4 लाख रुपए का लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप पहली बार घर खरीदने जा रहे हों । पहले लोन चुकाने की सीमा 15 वर्ष थी जिसे बढ़ाकर अब 20 साल कर दिया गया है । सरकार अब आपके ब्याज पर सब्सिडी देगी जिससे मिलने वाली छूट का लाभ बढ़ जाएगा । इसके लिए सरकार ने रियल स्टेट मार्केट को चुना है ।

घर की मरम्मत कराने के लिए भी मिलेगा लाभ

आप किसी बिल्डर से घर खरीद रहे हैं या कोई पुराना मकान खरीद रहे हैं तो आप च्ड।ल का लाभ उठा सकते हैं। जो लोग घर खरीदने की बजाय इसे खुद बनवा रहे हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा । जिनके पास अभी पक्का मकान है, वो इसकी मरम्मत करने या इसमें कुछ और कमरे जुड़वाने या किसी दूसरे तरह से इसका विस्तार करने के लिए भी लोन ले सकते हैं । बैंक आपको मौजूदा पक्का मकान में किचन, कमरा आदि बनाने के लिए योजना के तहत लोन देने से यह कहकर इनकार नहीं कर सकता कि आपके पास पहले से ही पक्का मकान है। कार्पेट एरिया हर कैटिगरी के लाभार्थी के अनुसार घर का क्षेत्रफल भी तय है। हालांकि, इसके तहत उसी एरिया को मापा जाता है जो दीवारों से घिरा हो जिसे कार्पेट एरिया कहा जाता है। इसमें दीवार की मोटाई का माप शामिल नहीं होता। आसान शब्दों में कहें तो जिस भाग पर आप दरी बिछा सकते हैं, वही घर का कार्पेट एरिया कहलाएगा। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कार्पेट एरिया 90 वर्ग मीटर यानी 968.752 वर्ग फीट है

जबकि इसी श्रेणी के दूसरे भाग के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए यह 110 वर्ग मीटर यानी 1184.03 वर्ग फीट है।

खत्म हो सकती है कार्पेट एरिया की सीमा

एरिया तय किए जाने से शहरी क्षेत्र में लोग इस योजना के प्रति बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार कार्पेट एरिया की सीमा खत्म कर देगी।

कहां से ले सकते हैं लोन

आप कमर्शल बैंकों, हाउजिंग फाइनैंस कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, छोटे वित्तीय बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि से लोन लेकर ब्याज पर उचित सब्सिडी पा सकते हैं। आपको किसी तरह का प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं देना होगा। हां, आप योजना के तहत जितना लोन लेने के योग्य हैं, उससे ज्यादा लोन ले रहे हैं तो अतिरिक्त रकम पर आपको नॉर्मल प्रोसेसिंग फी देनी पड़ सकती है ।

पीएम आवास योजना के आंकड़े आए सामने

पीएम आवास योजना में अब तक कितने मकान बने और किने लोगों को इसका फायदा मिला, इन सभी बातों की जानकारी अब सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 नवंबर, 2016 को आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक एक करोड़ नये घरों का निर्माण सुनिश्चित किया जाना है । इनमें से 31 मार्च 2018 तक 51 लाख मकान बनाए जाने हैं । इस चुनौती को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 51 लाख आवास मार्च 2018 तक बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर कई कदम उठा रहा है। इसके लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि आवासों का निर्माण किया जा सके।

इन राज्यों को हुआ सबसे ज्यादा फायदा

छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों की संख्या सर्वाधिक है। इन राज्यों के लोगों ने निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने आवासों का निर्माण किया है ।

आईए जानते हैं हिमाचल की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत

हिमाचल प्रदेश में इस योजना को अभी और गति पकड़ी होगी। टीम रीव की पड़ताल में इस योजना को धीमी गति से ही आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें एक कारण तो अनापत्ति प्रमाण पत्रों की कमी तथा दूसरे शहरी क्षेत्रों में ज़मीन का न होना है। क्योंकि जिनके पास शहर में ज़मीन है, वो तो ग़रीब कम ही है और जो किराए दार है उनके पास आय के स्रोत वांछित आंकड़े को भी पार कर देते हैं यानि उनकी वार्षिक आय 3 लाख से अधिक होती है। साथ ही कुछ लोग जो बाहरी राज्यों से है और विवाहिताओं को हिमाचल में प्रवेश मिला है, उन्हें राजस्व विभाग की पेचिदगियों से दो–चार होना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मुद्दा हमें भी प्राप्त हुआ जहां एक महिला हिमाचल प्रदेश के बाहरी राज्य से हिमाचल में विवाहित हुई। वार्षिक आय 3 लाख से कम ही थी लेकिन राजस्व विभाग में पटवारियों के दस्तावेज़ी औपचारिकताओं में उलझ गई। इसी प्रकार नगर निगम शिमला के अंतर्गत भी इस महत्वकांक्षी योजना को लागु करने में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वर्टिकल 3 के अंतर्गत जो लोग भूमिहीन है तथा मकान की दरकार सबसे अधिक है लकिन शिमला में ऐसे क्षेत्र कम ही है। इसके लिए एक सर्वे 2016 में हुआ जिस पर बाद में कुछ विवाद भी हुआ और पुनः सर्वेक्षण के लिए हामी भरी गई। सर्वे में 3000 के लगभग नाम सामने आए जिनमें से 184 के लगभग ही आवेदन कर पाऐं। बाकी आवेदनों को भी प्रशासन ने जांचने का कार्य चलाया है। अगर वर्टिकल 4 की बात करें तो उसमें लगभग 61 डीपीआर तैयार की गई हैं जिसमें 20 से 22 लोगों का मकान का कार्य अंतिम चरण में हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास या तो अपनी ज़मीन है या पुराना मकान मुरम्मत के लिए है अथवा नये कमरे का निर्माण पुराने मकान के साथ कर रहे हैं। इसमें भी गति को और अधिक तीव्र करने की आवश्यकता रहेगी। नगर निगम शिमला में जुड़ें नए क्षेत्रों में ज़मीन की उपलब्धता कुछ आसानी से हो जाती है इसलिए यहां पर इस योजना को आसानी से लागु किया जाने की आवश्यकता है। क्योंकि यहां ज़मीन की उपलब्धता रहती है। यह भी देखने में आया है कि आवेदकों में बहुत सी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। किसी न किसी प्रकार से ये लोग इस योजना का लाभ लेकर मकान हासिल करना चाहते है। ऐसे में इस योजना का लाभ पात्र एवं ग़रीब भूमिहीन लोगों को कैसे मिले, यह प्रशासन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। भूमिहीन लोगों को रिहायिश किन शर्तों पर मिलेगी और कब तक सभी भूमिहीनों को मकान आबंटित किए जाऐंगें इस पर भी अभी बहुत तीव्रता से कार्य करने की आवश्यकता है। हालांकि सर्वेक्षण का आंकड़ा या आवेदन का 3000 से अधिक हो सकता है परंतु भूमिहीन होने का प्रमाणपत्र केवल 400 के लगभग ही लोग दे पाए हैं। दोनों ही श्रेणियों में इस योजना को लाभान्वितों तक पंहुचाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना शेष है।

Advertorial

प्रदेश के युवा उद्यमियों के रोजगार व व्यवसाय में मिशन रीव बनेगा सारथी

शून्य से संपूर्ण तक के सफर में सहयोग करेगा रीव

व्यवसाय शुरू करने से स्थापना तक देगा साथ

अगर आप अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या पुराने व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के इच्छुक हैं तो मिशन रीव आपके इस सपने को साकार करने में पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार है। रीव न केवल व्यवसाय को शुरू करने में आपकी मदद करेगा बल्कि एक सारथी की तरह उस व्यवसाय को आगे ले जाने में आपकी पूरी मदद करेगा। इतना ही नहीं व्यवसाय को शुरू करने से लेकर अगले एक साल तक उस व्यवसाय के पूरी तरह स्थापित होने तक मिशन रीव हर पल आपके साथ रहेगा। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को मिशन रीव के पास ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा और मिशन के साथ जुड़ना होगा। आप कैसे इस योजना का लाभ लेकर अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं इसकी प्रक्रिया आप निम्नलिखित विविरण से समझ सकते हैं।

उद्देश्य

- अपना व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों को मार्गदर्शन कर व्यवसाय
- नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ना
- वांछित व्यवसाय शुरू करने के लिए उनकी क्षमता और कौशल का आकलन करना
- कम जोखिम में अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने में सहयोग देना
- उद्योग स्थापित करने के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना
- सर्वांगीण विकास में सहयोग करना
- भविष्य के लिए बेहतर योजना तैयार करने में सहयोग करना

ऐसे काम करेगा मिशन

अगर आप अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो मिशन रीव उसमें न एक सहयोगी के तौर पर आपका सहयोग करेगा। यहां पर बंद हो चुके व्यवसाय को पुनः शुरू करने का विकल्प भी मिशन रीव दे रहा है। अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो व्यवसाय शुरू करने से लेकर व्यवसाय एक साल तक व्यवसाय स्थापित करने तक मिशन रीव आपके साथ रहेगा और आपके व्यवसाय को आगे ले जाने में पूरा सहयोग करेगा।

इसके लिए जो भी दस्तावेजी औपचारिकताएं जैसे कि अन्नापति प्रमाण पत्र लेना, विभागीय अनुमति लेना, व्यवसाय शुरू करने से संबंधित योजनाओं की जानकारी, लोन का प्रबंध व अन्य दस्तावेजों से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने में मिशन रीव व्यवसायी की पूरी मदद करेगा।

रणनीति

नए व्यवसाय को स्थापित करने के लिए आवयश्क प्रशिक्षण एवं अन्य संबंधित जानकारियों के लिए रीव राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी जैसे एनआईआरडी जो कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थानों के साथ इस प्रकार के प्रशिक्षण करवाती है, से संबद्ध किया जाएगा ताकि भावी उद्यमियों को उचित प्रशिक्षण मिल सके। साथ ही ग्रामीण विकास में एनएसआईसी उद्यमिता के क्षेत्र में ज्ञान, कला–कौशल, एवं व्यवहार कुशलता आदि क्षेत्र में कोर्स, कार्यशालाएं एवं जागरूकता शिविर एवं सेमीनार आदि के माध्यम से सहयोग करती है।

मिशन रीव का फोकस

प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्तम एवं गुणवत्तापरक पठन सामग्री का खाका तैयार करना

बेहतरीन प्रश्नावली तैयार कर भावी उद्यमियों से व्यवसाय से संबंधित जानकारी प्राप्त करना

लघु अवधि प्रशिक्षण के लिए संभावित उद्यमियों का चयन करना

उद्यमशील योग्यताओं की क्षमता की पहचान करना

प्रंबधकीय समझ और आधारभूत कौशल विकास, विश्लेषणात्मक मानव प्रशासकीय और तकनीकी कौशल प्रदान करना

उद्यमियों को उनकी क्षमता के अनुसार बेहतर व्यवसाय का चयन करने में मदद और औद्योगिक प्रोजेक्ट दिलाने में मदद करना

कैंसे करे आवेदन

मिशन रीव के तहत इस योजना का लाभ लेने के लिए मिशन रीव की ओर से ऑनलाइन पोर्टल पर लिंक दिया जाएगा। इस लिंक में दिशानिर्देशों के मुताबिक कोई भी अपना पंजीकरण करवा सकेगा।

नियम व शर्तें

व्यवसाय शुरू में जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए देय निर्धारित शुल्क आवेदन करने वाले व्यक्ति को कंपनी के नियम और शर्तों के अनुसार अदा करना होगा। इसके साथ ही पोर्टल पर दिए गए दिशानिर्देशों को भी अच्छी तरह समझना और उनका अनुसरण करना अनिवार्य रहेगा।

आयु : प्रार्थी (अनु0जाति,अनु.जन0,सामान्य वर्ग) की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए जबकि महिलाओं के लिए आयु सीमा में छूट रहेगी ।
क्षेत्र : उस क्षेत्र का विवरण जिसमें परियोजना को स्थापित करना है या वो स्थान जो अपना बिजनेस आरंभ करने के लिए प्रस्तावित है ।
उद्यम का प्रकार : विनिर्माण(मैन्युफेक्चरिंग)/सेवा /व्यवसाय
ऋण के प्रकार : 10,000/रुपये से 1 करोड़ रुपये तक या प्रोजेक्ट के अनुसार ।
व्यवसाय के प्रकार : विनिर्माण(मैन्युफेक्चरिंग)/सेवा /व्यवसाय के लिए जो क्रेडिट(सॉफ्ट लोन एवं कार्यशील पूंजी) लोन सुविधा है उसके लिए किसी भी प्रकार की कोलेटरल सक्युरिटी/तृतीय पक्ष गारंटी नए व्यवसाय और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु मान्य नहीं है । योजनानुसार कोलेटरल सक्युरिटी लोन पुनःभुगतान सूची/कार्यक्रम : 3 से 7 वर्ष
आकर्षक ब्याज योजना : शेष राशि पर ही ब्याज अदायगी
साधारण सेवा शुल्क : कुल परियोजना लागत का मात्र 3 प्रतिशत पारदर्शी प्रलेखन : अवधि ऋण, कार्यशील ऋण तथा नकद ऋण : प्रमोटर का मार्जिन : अधिकतम 25 प्रतिशत

मिशन आईआईआरडी की सेवाऐं
दस्तावेज़ों की सूची :
लोन लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज़ : आवश्यकता आधारित
परामर्श सहयोग
व्यापार वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम
व्यापार वृद्धि में सहयोग
उचित उत्पाद का विज्ञापन एवं विस्तार सहयोग

नया व्यवसाय शुरू करें और रोज़गार पायें

लघु उद्योग सूची, लघु उद्योग के प्रकार,
लघु उद्योग की जानकारी,
कम लागत के उद्योग, कम पूंजी के व्यापार

IIRD हम जानते हैं गाँव को बेहतर

नया व्यवसाय एवं रोजगार से संबंधी जानकारी लेने के लिए निम्नलिखित फोन नम्बर तथा ईमेल पर संपर्क करें

0177– 2640761, 2844073 anand@iirdshimla.org info@iirdshimla.org hr@iirdshimla.org